Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक ३ तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का १७वां दिवस संख्या १२

बुधवार, दिनांक १३ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर :

[पशु-पालन, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, चिकित्सा, यातायात, स्वायत्त, शासन, गृह, कृषि, विद्युत् एवं गृह विभाग]

पशुओं की नस्ल सुधारने पर खर्चा

२९८. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा बकरा, बकरी, भैंस और ऊंट की नसल सुधारने हेतु सालवार कितना कितना खर्चा किया गया है ?

उप-मंत्री, पशुपालन विभाग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : सदस्य महोदय की जानकारी के लिये विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, सूची मुझे नहीं मिली है ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : सदन की मेज पर रखी गई है । क्या आपको नहीं मिली ?

श्री अब्दुल जब्बार : एक प्रश्न के बाद सप्लीमेन्ट्री कर सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप दो प्रश्न के बाद में पूछ लें । पहले आप सूची देख लें ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २९९

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३००

श्री मानिकचन्द सुराणा ।

(अनुपस्थित)

Page No.2

प्रश्न संख्या ३०१

श्री मानिकचन्द सुराणा

(अनुपस्थित––कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३०२

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित––कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३०३

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित––कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया।

निवाई-डांगथल वाया वनस्थली मार्ग पर मोटर परमिट

३०४. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(१) क्या सरकार निवाई से डांगथल वाया वनस्थली मार्ग पर मोटर चलाने का परमिट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(२) क्या यह भी सच है कि इस मार्ग पर मोटरें लगाने के लिए बहुत लोग तैयार हैं?

(३) क्या यह भी सच है कि इस मार्ग पर मोटर नहीं होने से उधर के गांवों के लोगों को समय पर अदालतों व तहसील आदि में पहुंचने में परेशानी होती है।

(४) क्या यह भी सच है कि इस मार्ग पर शीघ्र मोटर चालू करने के लिये पंचायत समिति निवाई ने कई बार सर्व-सम्मति से प्रस्ताव पास करके सरकार को भेज दिये हैं?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह): (१) नहीं, निवाई से डांगथल वाया वनस्थली मार्ग के स्थान पर निवाई से डिग्गी वाया डांगथल वनस्थली रूट पर चलाने का आर. टी. ए. का विचार है।

(२) जी हां।

(३) इस संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(४) जी नहीं।

श्री जयनारायण सालोदिया: क्या सरकार डिग्गी वाया डांगथल गाड़ी चलाने का विचार रखती है?

श्री भीमसिंह: मैंने आपको यह निवेदन किया है कि निवाई से डांगथल वाया वनस्थली मार्ग के स्थान पर निवाई से डिग्गी वाया डांगथल वनस्थली रूट पर चलाने का आर. टी. ए. का विचार है।

श्री जयनारायण सालोदिया: यह विचार कब तक पूरा हो जायगा?

श्री भीमसिंह: आर. टी. ए. का निर्णय होते ही।

श्री जयनारायण सालोदिया: यह कब तक हो जावेगा?

सार्वजनिक-निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): मीटिंग में जब कन्सीडर होगा?

श्री अध्यक्ष: आर. टी. ए. की मीटिंग कब होगी?

श्री हरिश्चन्द्र : स्टेट ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर ने मूव कर दिया है ।

श्री भीमसिंह : आर. टी. ए. सवाई माधोपुर अपनी सर्वे कम्पलीट कर रही है । उसकी रिपोर्ट आते ही कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ३०५

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह ।

(अनुपस्थित--कृपया आगे देखिये) ।

प्रश्न संख्या ३०६

कुमारी उमा माथुर ।

(अनुपस्थित) ।

प्रश्न संख्या ३०७

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित

(अनुपस्थित)

श्री राम किशन ।

जिला भरतपुर की अदालतों में सवर्णो तथा हरिजनों के संघर्ष के फौजदारी केसेज़

३०८. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) गत पांच वर्षों में सवर्णो तथा हरिजनों के संघर्ष संबंधी फौजदारी कानून के अन्तर्गत कितने केस भरतपुर जिले की अदालतों में रजिस्टर हुए हैं ?

(२) रजिस्टर्ड केसों में कितने अपराधियों को दण्ड मिला है और कितने केसेज़ खारिज हो गये है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) पुलिस की तरफ से इस प्रकार के कुल ८८ मुकद्दमात अदालतों में पेश हुए ।

(२) रजिस्टर्ड केसों में २४ अपराधी दंडित हुये । १३ केसेज खारिज हुए ।

श्री रामकिशन : ये पुलिस की तरफ से दर्ज किये हैं या प्राइवेट पार्टीज की तरफ से भी हैं ? इसकी क्या पोजिशन है ?

श्री भीमसिंह : कुल केसेज़ अदालतों में ८८ हुए हैं । उनमें से रजिस्टर्ड केसेज़ में २४ अपराधी दंडित हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष :-नैक्स्ट, श्री कुमारानन्द ।

बीकानेर, जोधपुर तथा शेखावाटी इत्यादि जिलों में सिंचाई प्रणाली ।

३०९. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) :

Will the **Minister for Agriculture** be pleased to reply:—

1. What is the system of irrigating the land for the purpose of cultivation in Bikaner, Jodhpur and Shekhawati Districts and other places of Rajasthan where there are no canals ?

2. What are the costs for irrigating 25 bighas (one Morraba) in Ganganagar Canal area and the costs of irrigating 25 bighas of land in Shekhawati, Jodhpur and Bikaner and other districts of Rajasthan where there are no canals?

3. Is it not true that if engines are used to fetch water from the wells in place of bullocks for culti-

Page No.4

vation, much of the labour and expenses of the poor peasants can be saved and large number of dry lands can be turned into green vegetable lands ?

4. Has the Government any scheme under Third Five Year Plan to use engines to fetch water from the wells in place of bullocks ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल): 1. The system of irrigation in these areas is either by local Charas, Persian Wheel or Pumping sets, depending on the depth of wells.

2. In Ganganagar the Irrigation charges are on the basis of crops. According to the Scheduled rate fixed by the Government the cost to irrigate 25 Bighas of land for wheat comes to approximately Rs. 78-12-0, while, in other areas, it would roughly come to Rs. 400/- if irrigated by charas, Rs. 80/- if irrigated by persian wheel and Rs. 70/- if irrigated by pumping set in case of wheat crop.

3. Yes.

4. Yes.

प्रश्न संख्या ३१०

श्री अध्यक्ष :—श्री भगराज चोधरी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३११

श्री विजयसिंह झाला ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३१२

श्री सम्पत्तिलाल वोहरा ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३१३

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३१४

श्री भैरव लाल "कालाबादल"

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री नाथूलाल करौल ।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत नगरपालिकाओं का पंचायतों में परिवर्तन

३१५. **श्री नाथूलाल करौल (चाकसू)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत सन् ५९ में नगरपालिकाओं से पंचायतों में परिवर्तित-सूची, मय जन संख्या के, सदन में प्रस्तुत की जावे ।

(ख) सन् ६० से सन् ६२ तक कितनी पंचायतें नगरपालिकायें घोषित की गई ? उनकी आबादी सहित सूची सदन में प्रस्तुत की जावे ।

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (क) सूची प्रस्तुत है ।

(ख) सूची प्रस्तुत है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरव लाल "कालाबादल" (अकलेरा-सु.): आपने नगरपालिकाएं घोषित की हैं उसमें अभी तक लालसोट को क्यों नहीं शामिल किया है? वह भी उसमें आता है?

श्री दौलतराम सारण: इसकी कार्यवाही चल रही है। इस प्रकार का प्रश्न पहले आया था उसके उत्तर में मैंने बताया था।

प्रश्न संख्या ३१६

श्री अध्यक्ष: श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३१७

श्री भगराज चौधरी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री अब्दुल जब्बार।

सब-जेल निम्बाहेड़ा

३१८. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) निम्बाहेड़ा सब-जेल पर कितने वार्डर्स हैं?

(२) वार्डर्स के रहने के लिये कितने क्वार्टर्स बने हुए हैं?

(३) वार्डर्स को उन क्वार्टरों में मय फैमिली रहने की इजाजत है या नहीं?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह): (१) निम्बाहेडा सब-जेल पर सात वार्डर्स हैं।

(२) वार्डर्स के रहने के लिये फैमिली क्वार्टर्स नहीं हैं, परन्तु एक बैरेक बनी है बन्दियों की एक बैरेक को वार्डरों के लिये फैमिली क्वार्टर्स में परिणत करने के लिये धन राशि स्वीकृत हो चुकी है परन्तु संकट-कालीन स्थिति के कारण यह कार्य स्थगित किया गया है।

(३) जब क्वार्टर्स ही नहीं हैं, तो प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अब्दुल जब्बार: क्या यह माना जाय कि जो आश्वासन विभाग की ओर से दिया गया है वह सही है या गलत है?

श्री भीमसिंह: जो उत्तर निवेदन किया है वह सही है।

श्री अब्दुल जब्बार: जो रिसेंटली ही सेक्रेटरी के यहां से लेटर आया है उसमें फरमाया है: Immediate action will be taken in this respect. इसको सही माना जाय या जो आपने फरमाया है उसको सही माना जाय। वहां कैदी हैं, कॉन्सीपीरेसी होने की संभावना है तो यह जरूरी नहीं है कि उनके बैरेक्स के लिए वाटर के लिये प्रबन्ध किया जाय।

श्री भीमसिंह: शीघ्रातिशीघ्र कार्य-वाही होगी।

प्रश्न संख्या ३१९

श्री अध्यक्ष: श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३२०

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

Page No.6

प्रश्न संख्या ३२१

श्री सम्पतिलाल बोहरा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३२२

श्री श्रवणलाल ।

(अनुपस्थित)

पंचायत समिति सांचोर में पतरों का अलॉटमेंट

३२३. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि पंचायत समिति, सांचोर में कृषकों को पिछले वर्षों में कभी पतरे पर्याप्त मात्रा में नहीं दिये गये ? अगर हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

(२) क्या यह सच है कि पंचायत समिति सांचोर में जनसंख्या के आधार पर पतरों के स्टॉक का अलॉटमेंट नहीं किया जाता ? अगर हां, तो क्यों ?

(३) पंचायत समिति, सांचोर में कृषकों को पर्याप्त मात्रा में पतरे देने की व्यवस्था कब तक हो सकेगी ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं । सरकार के आदेशानुसार नालीदार पतरों का आवंटन कृषकों की जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिये, किन्तु जिला परिषद्, जालोर ने इस आदेश के अनुसार पतरों का वितरण नहीं किया । अतः जिला परिषद् को यह आदेश दे दिया है कि भविष्य में ऐसा न करें ।

(३) मांग की अपेक्षा पतरों का उत्पादन बहुत कम होता है । जितना माल आता है वह हिस्से के माफिक सभी जिलों को बांट दिया जाता है । सांचोर को सन् १९६२–६३ में अब तक १९३ पतरे दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री रघुनाथ बिश्नोई !

जालोर में टिड्डियों से फसल को नुकसान

३२४. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि जालोर में टिड्डियों से सावनू फसल सं० २०१८ में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ ? इतना लोकस्ट ब्रीडिंग होने के क्या कारण थे ?

(२) कुल नुकसान कितना हुआ ? अब सरकार इस नुकसान के बारे में क्या रिलीफ देने वाली है ?

(३) क्या यह सच है कि टिड्डी मारने का पाउडर समय पर न पहुंचने से सांचोर तहसील में भी फसल का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ ?

(४) यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) जी नहीं ।

(२) चूंकि खास नुकसान फसलों को नहीं हुआ था अतः रिलीफ देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(३) सांचोर तहसील में पाउडर देरी से पहुंचा परन्तु सावनू फसल में खास नुकसान नहीं हुआ क्योंकि फसल ब्रीडिंग होने के पहले काट ली गई थी ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पहले का 'जी नहीं' उत्तर दिया है तो क्या ब्रीडिंग नहीं हुआ था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : नुकसान के बारे में है । आपने पूछा, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, इसका जवाब दिया है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई:—प्रिवेंट करने में क्या नेग्लिजेंस बरती गई ? समय पर पाउडर नहीं दिया गया तो प्रिवेन्टिव मेजर्स नहीं लेने के लिये कौन उत्तरदायी हैं ? उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल:—अध्यक्ष महोदय, कहीं पर दो आना, एक दो जगह ४ आने से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है । जहां पाउडर देरी से पहुंचा वहां ज्यादा बारिश होने से मीन्स आफ काम्युनिकेशन्स नहीं था इसलिए देर से पहुंचा ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: सम्वत् २०१८ में अध्यक्ष महोदय, ६ आना नुकसान हुआ है । जबरदस्त लोकस्ट ब्रीडिंग हुआ था, यह जानकारी किस आधार पर दे रहे हैं ? मेरी जानकारी के अनुसार तो ८ आने तक नुकसान हुआ था । लोकस्ट ऑथेरिटीज ने लापरवाही बरती । लोकस्ट वार्निग आफिसर तक नहीं पहुंचा जिससे बड़ा भारी नुकसान हुआ ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : कलेक्टर ने रिपोर्ट दी है उसके माफिक दो-तीन जगह ४ आने नुकसान हुआ है । अलावा इसके बाकी जगह दो आने से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है ।

श्री भीमसिंह (लूणकरणसर) : क्या इस तरह फसल को नुकसान होने पर जो रिपोर्ट की जाती है उसमें पंचायत समिति की भी राय लेते हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : रिपोर्ट कलेक्टर से मांगी जाती है, वे पंचायत समिति की राय लेते हैं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या यह सही है कि कलेक्टर ने रेवेन्यू अधिकारियों के खिलाफ एक्शन्स भी लिये थे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या ३२५

श्री श्रवणलाल (अनुपस्थित)

श्री अब्दुल जब्बार!

चित्तौडगढ़ उदयपुर वाया मंगलवाड रूट का नेशनलाईजेशन

३२६. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या चित्तौडगढ़-उदयपुर वाया मंगलवाड रूट को नेशनलाइज किया जायगा ? अगर हां, तो कब तक ?

(२) इस रूट को अभी तक नेशनलाइज न करने का क्या कारण है ?

Page No.8

उप-मंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) चालू पंचवर्षीय योजना में कोई विचार नहीं है ।

(२) स्वीकृत राष्ट्रीयकृत मार्गो की सूची में इस मार्ग को नहीं लिया गया ।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या कारण हो गया, ऐसी क्या मजबूरी थी सरकार के सामने कि एक बनी हुई डामर रोड को नेशनलाइज नहीं किया और उसके बजाय दूसरी सड़क जो नहीं बनी हुई है, को नेशनलाइज किया गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : केबिनेट में निर्णय होता है कि किन किन को नेशनलाइज किया जाय । केबिनेट डिसिजन के अनुसार ही साधनों के अनुसार उन रोड्स को स्वीकृत किया जाता है ।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या कारण था कि एक बनी हुई डामर रोड को नेशनलाइज नहीं किया गया और दूसरी बिना बनी हुई सड़क को नेशनलाइज किया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: यह प्रश्न अलग है ।

श्री अब्दुल जब्बार : जो बनी हुई डामर सड़क है उसको नेशनलाइज नहीं करके दूसरी बिना बनी हुई सड़क को नेशनलाइज करना कहां तक उचित है जब कि पहले ही पैसे की कमी है ?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य का क्या मतलब है ?

श्री अब्दुल जब्बार : सड़क ऑलरेडी टार रोड है उसको नेशनलाइज न करके न्यू रास्ता बनाया जा रहा है· · · · ·

श्री अध्यक्ष : सड़क नेशनलाइज थोड़े ही होती है । रूट होता है ।

श्री अब्दुल जब्बार : इससे मेरा यही मतलब है कि उदयपुर के लिये शार्टेस्ट पॉसिबल मोस्ट ईजियेस्ट रूट वाया मंगलवाड होता है, इसको नेशनलाइज न करके वाया मावली रखा है जहां सड़क नहीं है । तो इस नेशनल एमर्जेंसी के समय में जो शार्टेस्ट ईजियेस्ट रूट है उस पर राज्य की बस न चला कर दूसरे रूट को चुनने के लिये राज्य के सामने क्या मजबूरी थी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, सड़क बनी हुई है, इसलिए उसको नेशनलाइज किया जाय यह जरूरी नहीं है । जिस जगह रिलीफ के साधन लोगों को नहीं हैं वहां भी देना जरूरी है । आपकी सड़क बनी हुई है तो जो प्राइवेट बस ओपरेटर्स हैं, बसेज चलाते हैं, उनसे आप सहूलियत उठाते हैं ।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या इससे राज्य के खजाने को नुकसान नहीं होता है ?

सार्वजनिक-निर्माण मंत्री : (श्री हरिश्चन्द्र) साधनों के अनुसार ही राष्ट्रीयकरण होता है ।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या हमारे पास इतनी बसें नहीं हैं कि वहां चला सकें ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं ।

श्री अब्दुल जब्बार : जो बसें हमारे पास पडी हैं, उनको क्या खराब समझा जाय ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कोई बस पडी हुई नहीं है ।

Page No.9

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : यह 'ए' क्लास का रूम है या बी. सी. क्लास का ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : 'ए' क्लास का।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दूसरे ए. क्लास के रूम्स को मेक्समेलाइज कर रहे हैं, तो इसको क्यों नहीं कर रहे हैं ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : सबको एक साथ नहीं कर सकते ।

श्री अब्दुल जब्बार : वहां पर परिचित व्यक्तियों को बसेज चलती हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह शुरू में ही कह दिया होता तो इतनी बहस नहीं होती ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): जब जानते हैं तो पूछते क्यों हो ?

प्रश्न संख्या ३२७

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत

देवगढ़ डिस्पेन्सरी में फर्नीचर की कमी

३२८. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि देवगढ़ डिस्पेन्सरी में फर्नीचर बिल्कुल नहीं है और यहां तक कि आउट डोर पेशेन्ट्स के टिकट काटने के लिये मेज तक नहीं है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त डिस्पेन्सरी में आवश्यक फर्नीचर का प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मैं खुद देख कर आई हूं, वहां पर फर्नीचर नहीं है । आपके पास इन्फार्मेशन कैसे आई है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मेरे पास जो इन्फोर्मेशन आई है उस ही के आधार पर बता रही हूं कि वहां पर पूरे पूरे सामान मौजूद हैं ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : ऐसा पर्व करना गलत है तो आप कभी सरप्राइज चैकिंग करिये ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आप कहती हैं तो जांच कराई जायगी ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (बसीराजपुर): उनके तो जवाब दें ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : क्या सरप्राइज विजीट करेंगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आवश्यक जांच कराई जायगी ।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम-का-थाना

३२९. श्री ज्ञान चन्द मोदी (मोई): क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) भीम का थाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कुल कितने डाक्टरों के पद निश्चित हैं और वे कितने समय से कार्य कर रहे हैं ?

(श्री ज्ञानचन्द मोदी)

(२) वहां पर कितने समय से एक ही डाक्टर कार्य कर रहा है और उसे माह में कितने दिन दौरा करना पड़ता है ?

(३) क्या यह सही है कि डाक्टर के दौरे पर बाहर रहने से कई मरीजों को विना इलाज रह जाना पड़ता है ?

(४) यदि हां, तो सरकार दूसरे डाक्टर का कब तक प्रबन्ध कर देगी ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) नीम का थाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर का पद स्वीकृत है। जिस पर डाक्टर बी. एल. सौगवी दिनांक ८-११-१९६२ से कार्य कर रहे हैं।

(२) दिनांक ८-११-१९६२ से उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक डाक्टर कार्य कर रहा है। उक्त डाक्टर को १ माह में २० दिन एवं १५ नाइट हॉल्ट करने पड़ते हैं।

(३) जी नहीं। डाक्टर की अनुपस्थिति में वहां कम्पाउन्डर मरीजों की देखभाल करता है।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : जब हॉस्पिटल में डाक्टर नहीं होता है तो उस हॉस्पिटल की क्या हालत होती होगी क्या आप इससे परिचित हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : कम्पाउन्डर देख-भाल करते हैं। हर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर पर एक ही डाक्टर की नियुक्ति है।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : जहां एक भी नहीं है वहां क्या होगा ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जहां नहीं है वहां पर भेजने की कोशिश की जा रही है और जिन प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स पर दो-दो डाक्टर हैं वहां से एक को हटा दिया गया।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स के डाक्टर के लिये यह आवश्यक है कि वह महीने में १५ दिन बाहर नाइट हाल्ट करे क्या आपके डाक्टर्स बाहर १५ दिन महीने में नाइट हाल्ट करते हैं या नहीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जहां तक मेरी जानकारी है वे ऐसा करते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई सूचना है कि वे नाइट हॉल्ट बाहर १५ दिन के लिए नहीं करते हैं तो आप बतायें उसकी जांच की जावेगी।

श्री तेजा राम गहलोत (सोजत) : बहुत कम ऐसे डाक्टर होते होंगे जो महीने में १५ दिन बाहर नाइट हॉल्ट करते होंगे बाकी हैल्थ सेन्टर पर ही आराम फरमाते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): तहसील में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है वहां पर डाक्टर एक दिन भी बाहर दौरा नहीं करता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जब डाक्टर से कहते हैं तो वे कहते हैं कि गाडी लेकर आओ। हमारे पास कहां उनके लिए जीप है कि हम उनको ले जायं ?

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : राजस्थान में डाक्टरों की कमी है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : लगभग ५०० ।

Page No.11

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : ५०० डाक्टर उपलब्ध करने के लिए क्या कोशिश हो रही है ?

थर्ड फाइव इग्रर प्लान में एक मेडिकल कालेज खोलने का प्रावधान रखा था उसको क्यों ड्रॉप किया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : डाक्टरों को उपलब्ध कराने के लिए साधन जुटाये जा रहे हैं। दूसरे प्रान्तों से भी डाक्टर बुलाये जा रहे हैं और मेडिकल कालेज में भी स्टूडेन्ट्स की संख्या बढा दी गई है। कोर्स भी कम करने की कोशिशें की जा रही है ताकि डाक्टर्स शीघ्र उपलब्ध हो सकें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : राजस्थान में।

श्री अध्यक्ष : ग्रोर्डर प्लीज ! श्री ज्वाला प्रसाद।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : ५०० डाक्टरों की कमी कब से चली ग्रा रही है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : दिनों दिन कमी बढती जा रही है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : यह कमी कितने दिनों से चली ग्रा रही है ग्रौर सरकार ने इसके लिए क्या प्रयत्न किये हैं ?

(विराम)

यू. पी. में चार मेडिकल कालेज खुलेंगे जबकि इस साल में और हमारे यहां पर थर्ड फाइव ईयर प्लान में जो एक कालेज और खुलने का था उसको भी ड्राप कर दिया और कम्पाउन्डर्स के हाथ में हम लोगों की जिन्दगी को दे रखा है। सब जगह डाक्टरों की सहूलियत है तो यहां क्यों नहीं सहूलियतें मिलती हैं ? यू. पी. में चार कॉलेज का प्रोविजन कर सकते हैं और यहां एक और कालेज का प्रोविजन किया तो उसको भी उडा दिया। जहां तक जनता की सुविधा का सवाल है आप कहां तक इसको मान्यता देते हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है और प्रयत्न कर रही है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल,जयपुर) : आपका मतलब है कि अजमेर में खोला जाय ?

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : जनता के लिए डाक्टर चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : हुकुमत तो है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : हुकुमत तो आपके हाथ में है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): दवाईयां ही नहीं हों अस्पतालों में तो डाक्टर क्या करेंगे ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपने कहा कि डाक्टर्स बाहर से, दूसरी स्टेट से बुलाये जाते हैं तो क्या जो डाक्टर्स बाहर से आते हैं उनको छः महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है इसलिए वे भाग जाते हैं और टिकते नहीं हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह प्रश्न अलग है। सरकार जागरूक है कि ऐसे केस न होने पावे।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : जो डाक्टर रिटायरमेन्ट पर हैं उनके लिए सरकार की ओर से यह बताया जायगा कि उनकी सर्विसेज को क्यों नहीं एक्स्टेन्ड कर दिया जाता है ? नये अपोइन्टमेन्ट देते हैं तो एक्स्टेन्ड करने की क्यों नहीं सोचते हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अब तक तो रिएम्प्लायमेन्ट की स्कीम थी ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (रायसिंह नगर): जो डाक्टर्स चाय जाते हैं क्या सरकार उनको किसी बाड़े में बन्द करके रखना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष : पेंडिंग क्वेश्चन्स ।

श्री ज्ञान चन्द्र मोदी : इस समय एक भी डाक्टर नहीं है, वहां एक तो भिजवाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

प्रश्न संख्या १७६

(दिनांक ६ मार्च, १९६३ का स्थगित प्रश्न)

विद्युत् कनेक्शन्स सम्बन्धी विचाराधीन प्रार्थना-पत्र ।

१७६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Will the Minister for Power be pleased to state:—

(1) How many applications for electric connections are pending with the authorities of the various State Power Houses in Rajasthan and since how long ?

(2) Is the Government aware of the statutory provision to provide electric connection within one month of the application ?

(3) If so, what measures the State Government propose to take to see that the State Electricity Board makes a due compliance with the statutory provisions of the Indian Electricity Act ?

(4) When these applications can now be expected to be disposed of ?

श्री राम किशन (बैर) : यह प्रश्न तो अंग्रेजी में ही है । आप तो जवाब हिन्दी में देंगे ना ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री परसराम मदेरना) : (1) 2,329 applications are pending with the various Power Houses in Rajasthan since January, 1963.

(2) Yes.

(3) The Electricity Board always complies with the statutory requirements. Applications are disposed of according to the rules laid down in this connection. Those applications which comply with these, such as filling 'L' form through a licenced contractor depositing the estimated cost involved etc., are given connection.

(4) As soon as they comply fully with the requirements of the rules for giving electric connections.

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले प्रश्न का उत्तर जरा रिपीट कर दीजिये ।

श्री परस राम मदेरणा : 2,329 applications are pending with the various Power Houses in Rajasthan since January, 1963.

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये सब दरख्वास्तें जनवरी, १९६३ के बाद की हैं, उससे पहले की कोई नहीं है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : That is what he has said.

श्री परसराम मदेरणा : This is what I said.

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने कहा कि स्टेच्युटरी प्रोविजन के अनुसार ही कनेक्शन दिये जाते हैं। इतनी पुरानी पुरानी दरख्वास्तें हैं। जहां एक महीने के अन्दर उनको कनेक्शन देने का प्रावधान है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अन्तर्गत तो आप उस प्रावधान का पालन क्यों नहीं करते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सही है कि स्ट्रिक्टली एक महीने के अन्दर कनेक्शन नहीं लगाये जाते हैं। उस कानून के अन्दर एक प्रोविजन यह भी है कि १४ दिन के अन्दर वह व्यक्ति बोर्ड के साथ एग्रीमेन्ट एक्जीक्यूट करेगा- उसमें ऐसा होता है कि यदि दो साल तक कनेक्शन लेने में रीजनेबलि रिटर्न बोर्ड को नहीं मिलता है तो कन्ज्यूमर देगा। यह फिजिबल नहीं है, कन्ज्यूमर्स नहीं करते हैं। जब वे नहीं करते हैं तो कान्ट्रेक्टर के थ्रू एप्लीकेशन देने के बाद हमारा आदमी आता है, जो फोर्मेलिटीज होती है वह पूरी करनी होती है और जो उस फॉर्मेलिटीज को आब्जर्व करने में अधिक समय लग जाता है।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के इन्स्ट्रक्शन्स साफ हैं और डेट मुकर्रर कर दी है। जिन जिन जगह पे यह फॉर्मेलिटीज कम्पलीट हो जाती है तो डेट दे दी जाती है कि कॉन्ट्रेक्टर के पास कितने दिन लगेंगे और दूसरी जगह कितने दिन लगेंगे। इसमें थोड़ी बहुत डिले हो जाती है। बोर्ड की तरफ से डेट्स बंधी हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो फॉर्म नियत किया है यह १ महीने के अन्दर सब कार्यवाही करने का फॉर्म है।

श्री परसराम मदेरणा : जी हां, एक महीने में पूरा करने का है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जितनी दरख्वास्तें पेन्डिग हैं उनको कितने दिन में कनेक्शन मिल जायगा ?

श्री परसराम मदेरणा : यदि फिजिबल हुआ तो पॉवर की कैपेसिटी नहीं है तो नहीं मिल सकेंगे। यह नहीं है कि एप्लीकेशन दे दी और कनेक्शन मिल गया। लाइन लगाना है तो फिजीबल है या नहीं-सब देखकर किया जाता है। मैं नहीं कह सकता कि सबको कनेक्शन मिल जायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जहां ट्रान्समीशन लाइन मौजूद है वहां तो एक माह में ही दे देना चाहिये। लाइन डालना पड़े वहां बात दूसरी है। जहां लाइन मौजूद है वहां आप इस समय कनेक्शन देने का आश्वासन देंगे ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : कानून है यह मैं मानता हूं, और कोशिश यह करते हैं कि कनेक्शन जल्दी से जल्दी दे दिये जावें। विद्युत् मंडल के सामने भी फाइनेन्स की दिक्कत हैं। ट्रान्समिशन लाइन होना जरूरी है। गांव वाले चाहते हैं तो भी उसमें कितना खर्चा आवेगा, रेम्युरेटिव है या नहीं, यह देख कर ही देंगे। यह कमिटमेन्ट मैं हाउस के सामने नहीं कर सकता कि हम सब को ही दे देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सडक और बाजार से लाइन जा रही है तो उसमें क्यों डिले होती है ? डिपार्टमेन्ट उनको कनेक्शन देने का प्राविजन करे।

Page No.14

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी मिसाल मालूम ही तो कर सकते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हर जगह की है पर्टीक्यूलर जगह का सवाल नहीं है ।

(विराम)

श्री मोहरसिंह राठौड़ (चूरू) : पेन्डिंग दरख्वास्तें हैं उनमें स्टेच्युटरी प्रावीजन्स की शिड्यूल्ड टाइम में पूर्ति नहीं हो रही है तो उनको कितने दिन में खारिज कर देंगे ?

श्री परसराम मदेरना : Pardon.

श्री मोहरसिंह राठौड़ : ये आपके पास जो पैन्डिंग एप्लीकेशन्स हैं जिनमें स्टेच्यूटरी प्रावीजन्स की पूर्ति नहीं हुई है तो आप उनको खारिज कब तक कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : खारिज़ तो मत कराइये ।

श्री मोहरसिंह राठौड़ : खारिज कर दें तो तसल्ली तो हो जाय, ताकि मिट्टी का तेल लाकर काम चलायें ।

श्री अध्यक्ष : अब भी लाकर ही काम चलाते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या २९८ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्न

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा): आपने जो लिस्ट दी है उसमें आपने बकरे बकरियों के लिये खर्च बताया है; एक जगह तो १० हजार और दूसरी जगह १ हजार ५०० तो आप उनकी तरक्की के लिये क्या कर रहे हैं ?

उप-मंत्री, पशु विभाग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : अभी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : इनका कहना यह है कि बकरे बकरियों का महत्व होते हुए इतना कम खर्चा क्यों करते हैं ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : बकरों से आप ज्यादा परिचित मालूम होते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो सब से ही परिचित रहा हूं, हांडा साहब आपसे भी और बकरों से भी । बकरियों के बारे में मैं आपसे निवेदन करूं हमारे यहां लोकल तीन ब्रीड्स हैं उन ब्रीड्स को क्रोस ब्रीड करवा कर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं । जमुना पार करके अपग्रेड करना चाहते हैं और जितने बकरों की रेवड में जरूरत होती है लोगों की मांग होती है और जितना फाइनेन्सियल प्रोवीजन है उस हिसाब से और जितना पैसा उपलब्ध था उस हिसाब से बकरे खरीद कर बांटे गये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कितनी जगहों पर आपने एक्सपेरिमेन्ट किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हर साल हमने बीस, तीस, चालीस और सौ सौ की संख्या में बकरे दिये हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सांचोर में भी भेजे हैं क्या ?

श्री अब्दुल जब्बार : १९६०-६१ में १० हजार का प्रोवीजन किया है, ६१-६२ में १ हजार ५०० का एक्सपेन्डिचर बताया है यह एकदम इतना कम कैसे कर दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : साधनों की कमी की वजह से दूसरी स्कीम्स में जब पैसा खर्च

(श्री नाथूराम मिर्धा)
हो जाता है तो बकरियों के लिये कम बचता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह ।

राजकीय मुद्रण एवं लेखन–सामग्री विभाग द्वारा मेसर्स भारत प्रेस, अलवर से रोडवेज के टिकटों की छपाई

२९९. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि संचालक, राजकीय मुद्रणालय तथा लेखन सामग्री विभाग तथा मेसर्स भारत प्रेस, अलवर के मध्य राजस्थान स्टेट रोडवेज के टिकिट की छपाई का दो वर्ष का कोई कान्ट्रेक्ट हुआ है ?

(ख) क्या यह सही है कि इसके लिये टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो किस किस फर्म के किस-किस रेट के टेण्डर आये ? कृपया टेण्डर नोटिस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) क्या यह टेण्डर की शर्तों के अनुसार स्वीकार किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों। यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो क्यों और क्या ?

(घ) इस छपाई के लिये अब तक कागज कहां कहां से दिया गया और कहां से इस प्रेस के बिलों का वेरीफिकेशन तथा पेमेन्ट किया गया ? क्या यह वेरीफिकेशन पेमेन्ट नियमानुकूल है ?

(ङ) दो वर्ष में यह छपाई कुल मिलाकर कितनी कीमत की होगी ?

(च) यह सारा काम एक ही प्रेस को क्यों दिया गया ?

(छ) क्या यह काम किसी सरकारी प्रेस में नहीं हो सकता था ?

(ज) क्या इस कार्य के लिये सरकार द्वारा मशीन भी खरीदी हुई है जो बेकार पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (क) जी हां।

(ख) टेण्डर आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं हुई।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ?

(घ) छपाई के लिये कागज राजकीय मुद्रणालय अलवर से दिया गया था। बिलों का वेरीफिकेशन रोडवेज द्वारा किया गया तथा संचालक, मुद्रण एवं लेखन–सामग्री द्वारा इसका भुगतान किया गया। भुगतान नियमानुकूल ही हुआ है।

(ङ) यह कान्ट्रेक्ट १८-१२-६१ से ही शुरू हुआ है जिसके अनुसार ३१-१-६३ तक रु० ३०,३७८.५० न. पै. का भुगतान हो चुका है।

(च) ऐसा ही उचित समझा गया।

(छ) कार्य की अधिकता के कारण संभव नहीं था।

(ज) जी हां।

श्री भैरोंसिंह : टेण्डर इनवाइट क्यों नहीं किये गये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट प्रेस के जो रेट्स निर्धारित है

उसी के मुताबिक अगर प्राइवेट प्रेसेज लेते हैं तो उसके लिये टेण्डर्स की आवश्यकता नहीं होती और उसी रेट्स पर उनको दिया गया।

श्री भैरोंसिह : आपने केवल इसी प्रेस को क्यों दिया, और भी प्रेस गवर्नमेंन्ट रेट्स से कम पर काम करने को तैयार हो सकते थे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : गवर्नमेन्ट प्रेस द्वारा निर्धारित रेट्स पर इसको दिया गया था दूसरे प्रेस ने १ न. पै. ज्यादा डिमान्ड किया। दूसरे, पांच हजार की सिक्योरिटी मांगी थी दूसरे प्रेस ने देने से इन्कार कर दिया।

श्री भैरोंसिह : दूसरे प्रेसेज से भी आपने रेट्स मांगी थी क्यों कि हमें रोडवेज के टिकट छपवाने हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां. सब प्रेसेज से रेट्स मांगी थी।

श्री भैरोंसिह : जिन प्रेसेज से आपने रेट्स मांगे उनको फिर किस प्रकार से सूचना दी गई ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : चिट्ठी लिखकर और प्राइवेटली कांन्टेक्ट करके।

श्री भैरोंसिह : आप उनसे टेण्डर इनवाइट कर लेते तो क्या आपत्ति थी ? जब कि आपने सारे प्रसेज को चिट्ठी लिख कर इनफोरमेशन दी इसके बजाय आप टेण्डर इनवाइट कर लेते ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : काम में बहुत देरी हो रही थी इसलिये जल्दी करवाने के लिये यह किया गया।

श्री भैरोंसिह : शार्ट टाइम टेन्डर इनवाइट किये जा सकते थे क्या ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिह : एक प्रश्न और है प्रारम्भ में जो कान्ट्रेक्ट हुआ था उसमें किसी प्रकार की तबदीली हुई क्या ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं, तबदीली नहीं हुई।

श्री भैरोंसिह : यह बात माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि कागज के साइज के अन्दर तबदीली हुई, जैसा प्रेसक्रिप्शन दिया था पहले आरम्भ के अन्दर जितनी बड़ी साइज की टिकिट होनी चाहिये थी जितने कागज पर टिकिट होनी चाहिये उसमें कोई तबदीली हुई क्या ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय मैं इस उत्तर को चेलेन्ज करता हूं जिस समय प्रारम्भ के अन्दर कान्ट्रेक्ट हुआ था जितने साइज पर टिकट छापने थे उसमें तबदीली हुई है। यहां जो जानकारी दी जा रही है वह सही नहीं है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जिस प्रकार का प्रेसक्रिप्शन रोडवेज द्वारा दिया गया था उसी मुताबिक टिकिट छापकर दिये गये। फिर भी आप बताते हैं तो इसको एक्जामिन किया जायगा।

श्री भैरोंसिह : पिछले टाइम जो सूचना दी गई थी उसमें साइज मोटी थी अब छोटी कर दी गई ?

मंत्री,
(श्री मथुरादास माथुर) : इकोनोमी के लिये छोटी की गई थी।

Page No.17

रेगिस्तानी लोगों को फूड एडल्टरेशन एक्ट के अन्तर्गत लाइसेन्स

३०२. **श्रीभीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राज्य के रेगिस्तानी लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन ही है? अगर हां, तो ऐसे व्यक्तियों को फूड एडल्टरेशन एक्ट के अन्तर्गत लाइसेन्स लेने के लिये क्यों बाध्य किया जाता है?

(२) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के देहाती क्षेत्र के बहुत से किसानों द्वारा रेल से अपने खुद के अथवा अपने रिश्तेदारों के लिये लाने वाले घी के लिये बीकानेर शहर के फूड इस्पेक्टर द्वारा चालान पेश करके अदालतों से उन पर जुर्माना कराया गया है? क्या राज्य सरकार ऐसे काश्तकारों की परेशानी को दूर करने का कोई रास्ता निकालेगी?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) केवल दूध व घी बेचने वालों को ही लाइसेन्स पी. एफ. ए. एक्ट के तहत लेना आवश्यक है। जो लोग घरेलू जानवर रखकर दूध घर ही में प्रयोग करते हैं उन्हें लाइसेस नही लेना पडता। पी. एफ. एक्ट द्वारा मिलावटी वस्तुओं का, जिनमें शारीरिक हानि हो, बिकना रोका जाता है।

(२) यह मालुम करना कठिन है कि अमुक किसान रेल से अपने खुद के अथवा अपने रिश्तेदारों के लिये दूध अथवा घी लाता है, परन्तु यदि अदालत द्वारा ऐसे लोगों पर जुर्माना हो चुका है तो यह मानना पड़ेगा कि वह घी या दूध बेचने के लिये लाये और उनका चालान कानूनन सही था।

मिल्क स्कीम के अन्तर्गत अधिकारी

३०३. **श्री भीमसेन** (लूणकरनसर) : क्या मन्त्री, पशु पालन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

मिल्क स्कीम के सुचारु रूप से संचालन हेतु प्रारम्भ में किस ग्रेड के अधिकारी का प्रावधान किया गया था तथा इस समय किस ग्रेड के अधिकारी कार्य कर रहे हैं? मौजूदा व्यवस्था से खर्च में कमी हुई है अथवा वृद्धि?

उप-मंत्री, पशुपालन (श्रीमती कमला बेनीवाल) : मिल्क सप्लाई स्कीम का कार्य इस चालू वित्तीय वर्ष में ही प्रारम्भ किया गया है। अतः प्रारम्भ से इस समय तक एक ही ग्रेड के अधिकारी कार्य कर रहे हैं। इस व्यवस्था से खर्च में कमी या वृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया (अनुपस्थित)

नगरपालिका भादरा को सहायता की धनराशि

३०५. **श्री हरदत्तसिंह** (नोहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार द्वारा भादरा नगरपालिका को सन् ५८ से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष कुल कितनी धनराशि की सहायता और किस किस मद में राजस्थान सरकार द्वारा दी गई?

(२) प्रशासक नगरपालिका भादरा ने इस वर्ष ड्रेनेज के लिये कुल कितनी राशि की मांग सरकार से की है और इस संबंध में सरकार क्या कर रही है?

(३) नगरपालिका भादरा का चालू वर्ष का बजट कितना है और यह सरकार द्वारा कब स्वीकार किया गया?

Page No.18

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) :

वर्ष	जनरल सहायता	विकास कार्यों के लिए,	मेंहगाई भत्ते के लिये,	अन्य
१९५७-५८	१,४०३)रू०	२,७९०)रू०	२,६८०)रू०	—
१९५८-५९	१,४०३)रू०	२,७९०)रू०	२,७६०)रू०	—
१९५९-६०	१,४०३)रू०	२,७६०)रू०	४,७६०)रू०	—
१९६०-६१	—	७,५००)रू०	४,७६०)रू०	५,०००)रु. सडकों हेतु
१९६१-६२	—	—	४,७६०)रु०	७,५००)रु० सडकों हेतु

कोई मांग विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

खर्च १९६२-६३

(क) आय:—१,६२,३८४) रु०

(ख) व्यय :—१,६२,२७०) रु०

यह बजट दिनांक १२-५-६२ को स्वीकृत हुआ है।

श्री हरदत्तसिंह : यह बजट मंजूरी के लिए कब भेजा गया था ?

श्री दौलतराम सारण : यह तारीख इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कुमारी उमा माथुर
(अनुपस्थित)

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित
(अनुपस्थित)

श्री भगराज चौधरी
(अनुपस्थित)

मावली तहसील में चम्बल की बिजली

३१२. **श्री सम्पति लाल बोहरा** (मावली) : क्या सरकार को विदित है कि मावली तहसील डिस्ट्रिक्ट उदयपुर में चम्बल से बिजली योजनानुसार जुलाई, १९६२ तक मिलनी थी ? यदि हां, तो क्या बिजली मिल गई है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा भविष्य में कब तक मिलने की संभावना है ?

उप मंत्री, विद्युत (श्री परसराम मदेरना) : जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। फन्ड्स, एवं मावली को बिजली देने की योजना की लाभदायकता पर निर्भर करता है।

श्री सम्पतिलाल बोहरा: अध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट के प्लान में लिखा है जब वह १९६२ में सदन में पेश हुआ कि जुलाई १९६२ तक मावली और फतहनगर तक बिजली दी जावेगी, और आप कहते हैं ऐसी योजना ही नहीं है ?

विद्युत मंत्री, (श्री हरिश्चन्द्र) : किसमें लिखा है ?

श्री सम्पतिलाल बोहरा : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट में लास्ट ईयर का फेज प्रोग्राम था कि जुलाई, १९६२ तक मावली और फतहनगर में बिजली देने की योजना रखी है।

श्री हरिश्चन्द्र: आपने हाइडल के लिये पूछा है। इसलिये 'ना' दी है। इसका मतलब यह नहीं कि सब जगह हाइडल पहुंच जावें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : तो फिर कौनसी पहुंचेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : आप इसके लिये अलग से पूछियेगा। आपने हाइडल के लिये पूछा उसका जवाब दे दिया।

श्री भैरोंसिंह : कौनसी पहुंचेगी फिर, आप बताइयेगा न ? प्लान्ड फेज प्रोग्राम में जुलाई १९६२ तक मावली फतहनगर तक बिजली देना चाहते थे तो कौनसी देना चाहते थे ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपने हाइडल के लिये पूछा सो हाइडल तो मिलेगी नहीं। दूसरी के लिये मुझे मालूम नहीं। आप प्रश्न पूछियेगा, मैं जानकारी करके उत्तर दे दूंगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : खम्भे वहां पहुंच चुके हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : तो फिर पूछ क्या रहे हैं ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह पूछ रहा हूं कि मावली और फतहनगर को आपके फेज प्रोग्राम के अनुसार बिजली कब तक मिलेगी ? क्योंकि खम्भे दूसरी साइड में ले जाये जा रहे हैं वहां से हटाकर। वहां से हटाकर क्यों दूसरी जगह लग रहे है ?

श्री हरिश्चन्द्र : तो हाइडल बिजली का तो सवाल ही नहीं है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : पर खम्भे क्यों हटाये जा रहे हैं वहां से और पहले क्यों लगाये गाये ? जब लगाये गये तो बिजली देने के इरादे से ही तो लगाये गये, अब क्यों हटाये जा रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आपको तो यही मालूम नहीं कि फेज प्रोग्राम में जुलाई १९६२ में बिजली देने की बात थी।

श्री हरिश्चन्द्र : हां, मुझे तो कतई कुछ मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जावे कि फेज प्रोग्राम के अनुसार कार्यक्रम चल रहा है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : अध्यक्ष महोदय . . . . . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : One at a time.

श्री भैरोंसिंह : फिर क्या यह समझा जावे कि वे खम्भे जो हटाये जा रहे हैं आपकी अनुमति के बिना हटाये जा रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है और अभी तक माननीय सदस्य ने मुझे एप्रोच भी नहीं किया। न चिट्ठी आई है, न कोई शिकायत।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : खम्भे व बिजली का सामान पहुंच गया, पर अब हटाया जा रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र : आप इसके लिये अलग से प्रश्न पूछिये। आपका यह प्रश्न तो हाइडल तक सीमित था और आप अब खम्भे की बात कर रहे हैं। आप अगर खम्भे की पूछ लेते तो उसका भी जवाब मालम करके दे देता

Page No.20

(श्री हरिश्चन्द्र)
आप सवाल कुछ दूसरा पूछते हैं और सप्लीमेन्टरी कुछ दूसरा करते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आपके फेज प्रोग्राम के अनुसार मावली और फतेहनगर में बिजली लगाने की बात थी या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह भी अलग प्रश्न है । आपने हाइडल के लिये पूछा, उसका जवाब दिया । आप यह पूछते कि बिजली डीजल की लगा रहे हैं या खम्भे हटा रहे हैं तो उसका जवाब देते । I would have given you correct answer.

श्री सम्पतिलाल बोहरा : अध्यक्ष महोदय, जो हाइडल पावर की योजना बनी है उसमें निश्चित रूप से यह है कि सन् ६२ की जुलाई में बिजली देंगे । आपके अपने बजट भाषण के अन्दर भी हाइडल का जिक्र है । इसमें डीजल के फेज प्रोग्राम का आप अब कह रहे हैं । चम्बल से पहुंचाने की बात है । चम्बल से बिजली योजनानुसार मिलनी थी, मैंने पूछा और आपका उत्तर आ रहा है नहीं । स्टेटमेन्ट फेज प्रोग्राम का था कि बिजली देंगे । आपने उस स्टेटमेन्ट को देखा ही नहीं है ।

श्री परसराम मदेरना : अध्यक्ष महोदय, जैसी हमारी इत्तला है, जैसी इन्फोर्मेशन हमारे पास आई है, मावली को बिजली देने की कोई योजना नहीं थी । इसके बाद भी आप कहते हैं कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एन्युअल रिपोर्ट पेश होती है उसमें जिक्र है । पर बोर्ड ने हमें इन्फोर्मेशन दी है कि तहसील मावली में पांच हजार का कोई गांव ही नहीं है और जिनकी आबादी पांच हजार से ऊपर है उनको ही ६२-६३ के प्रोग्राम के मुताबिक बिजली दी जायेगी । उसके बाद छोटे गांवों को तभी कन्सीडर किया जा सकता है जब कोई खास कारण हो और हमारा प्रोडक्शन अधिक हो । इस समय तो हम पांच हजार तक की आबादी या इससे अधिक के लिये ही कमिटेड हैं । इसलिये लोकल डिस्ट्रिब्यूशन प्रोग्राम इनके लिये ६३-६४ में लेने में मजबूर हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री कालाबादल ।

आहू नदी की सहायक छोटी नदी पर पुल झालावाड

३१४. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या आहू नदी, झालावाड की सहायक छोटी नदी का इसी वर्षा ऋतु में नया पुल टूट गया था ? यदि हां, तो इसके टूटने का क्या कारण था और कितने का नुकसान होने का अनुमान है ?

(२) क्या इस पुल को फिर से बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो अब इस पर क्या खर्चा होगा ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भैरवलाल काला बादल : पुलिया टूटी नहीं क्या ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : जी नहीं ।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : टूटी ही नहीं ?

Page No.21

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : सिर्फ ३० फुट मिट्टी बही है ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : पुलिया से दबी हुई थी वह मिट्टी पुलिया के सहारे ही तो थी वह मिट्टी पडी हुई मिट्टी चली गई तो पुलिया कैसे रह गई ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैं कह रहा हूं पुलिया नहीं टूटी है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): मिट्टी नीचे से खिसक गई तो क्या पुलिया आकाश में खडी रह गई ?

श्री अध्यक्ष: श्री नाथूलाल करोल (अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास (अनुपस्थित)

नेक्स्ट, श्री भगराज ।

मोकलसर पावर हाउस द्वारा बिजली

३१७. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाडा): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

मोकलसर स्टेशन (जिला बाडमेर) पर बनाये जाने वाले पावर हाउस के द्वारा आसपास के किन किन गांवों को बिजली उपलब्ध हो सकेगी व उस पर कुल कितना रुपया खर्च होगा ?

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री परसराम मदेरणा): सिवाना और मोकलसर टाउन को बिजली उपलब्ध हो सकेगी और इस स्कीम पर १०.८२ लाख की धनराशि खर्च होगी ।

श्री भगराज चौधरी: कब तक यह काम पूरा हो जायेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : पावर हाउस की बिल्डिंग बननी शुरू हो गई है-- डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का सर्वे कम्पलीट हो गया है । अब समय इसमें कितना लग सकेगा, यह नहीं कह सकूंगा । पर काम शुरू है ।

श्री भगराज चौधरी : जब कि इससे भी अधिक बडे या बराबर के गांव आस पास के क्षेत्रों में हैं पांच मील के एरिया में उनको बिजली क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : सिवाना तो काफी बडा गांव है और सिवाना में वह सबसे बडा होगा इससे बडा और कौन होगा ?

श्री भगराज चौधरी: मोकलसर से बडा समदडी और खण्डप है जिनकी आबादी सिवाना से अधिक है ।

श्री परसराम मदेरणा : मोकलसर से सिवाना देने का प्रश्न है हमारे सामने और सामान पहुंचा रहे हैं । अब मोकलसर ट्रान्सपोर्ट के हिसाब से सामान पहुंचाने करने की सहूलियत है इसलिये उसको पहले दे रहे हैं । वहां डीजल सैट लगावेंगे इसके बाद वहां से ट्रान्समिसन करेंगे सिवाना को । मोकलसर को तो सिचुएशन की वजह से चूज किया है । वहां पानी आदि की भी सहूलियत है ।

राजकीय मुद्रण एवं लेखन-सामग्री विभाग द्वारा व्हाइट पेपर के लिफाफों की खरीद

३१९. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मंत्री, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सन् ६०-६१ में संचालक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन-

(श्री भैरोंसिह)

सामग्री विभाग द्वारा जयपुर स्टेशनर्स, जयपुर को ६० हजार के लगभग ४। × ५। व्हाइट पेपर के लिफाफे खरीदने का आदेश दिया गया था ?

(ख) क्या यह सही है कि लिफाफे सप्लाई करने से पूर्व इसका एप्रूव्ड सेम्पल जयपुर प्रेस के अधीक्षक के पास नहीं भेजा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि संचालक ने अधीक्षक, जयपुर प्रेस को लिख दिया कि ये लिफाफे सेम्पल के अनुसार नहीं हैं इसलिए इनको नहीं लिया जावे ?

(घ) क्या यह सही है कि कुछ समय पश्चात् संचालक ने अधीक्षक को इन लिफाफों की डिलीवरी लेने की तथा ढाई प्रतिशत रेट्स कम करके पेमेण्ट करने की आज्ञा दी है ?

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त अनियमितताएं क्यों हुई और इसके लिए कौन दोषी है ?

उप-मंत्री, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, संभव नहीं हो सका।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) लिफाफों को रिजेक्ट करने के पश्चात् फर्म ने रिप्रेजेण्ट किया कि जो पेपर लिफाफों के बनाने में काम लिया गया है वह उसी वजन का है और उसी डाइमण्ड ब्रांड के है जिसका कि एप्रूव्ड सेम्पल है। लिफाफे प्रेस्क्रिप्शन के माफिक है पर चमक बहुत है इसलिए दो परसेण्ट की कटौती करके पेमेण्ट कर दिया जाय। इस पर एप्रूव्ड सेम्पल व एक लिफाफा सप्लाई में से तोला गया और उनके वजन में किसी प्रकार का फर्क नहीं पाया गया। इस पर जयपुर प्रेस को लिखा गया कि चूंकि केवल चमक इनमें एप्रूव्ड सेम्पल से अधिक है इसलिए २ परसेण्ट कमी पर लिए जाएंगे।

श्री भैरोंसिह : जिस कमेटी ने एप्रूव किया उसको यह लिफाफा पेश किया गया था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां, एक सेम्पल भेजा था फर्म ने।

श्री भैरोंसिह : जो सेम्पल कमेटी के सामने भेजा गया उस सेम्पल से डिलीवरी हुई है सब लिफाफों की, उनकी तुलना उससे हुई है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां, मैंने बताया कि उसमें केवल इतना फर्क था कि उसमें ग्लेज थोड़ा ज्यादा था इसलिए २ परसेण्ट की कटौती की गई उसके बिल में से ?

श्री भैरोंसिह : क्या वेट में भी वह कम था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं, वेट में बराबर था।

श्री भैरोंसिह : जिस बात के लिए पेनल्टी इम्पोज की, क्या जो सेम्पल दिया और जो माल डिलीवर किया उसमें जितना पेपर की वजह से अन्तर था वह उस पेनल्टी से कवर हो जाता है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह मैंने केलकुलेट नहीं किया, पर दो परसेण्ट कटौती करके लिया।

श्री भैरोंसिह : फिर दो परसेण्ट कटौती करके किस आधार पर लिया गया, यही तो मैं पूछ रहा हूं। किस बेसिस पर यह दो परसेण्ट कटौती की ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह कमेटी का डिसीजन था। सारे केस को एग्जामिन करके उन्होंने डिसाइड किया था ?

श्री भैरोंसिह : जिस समय सप्लाई सेम्पल के अनुसार नहीं मिल रही है तो उस समय आउट राइट सारी डिमाण्ड को रिजेक्ट कर सकते थे और इसके बाद में सेम्पल के अनुसार ही डिलीवरी लेनी चाहिए थी माल की। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, डिमाण्ड को रिजेक्ट क्यों नहीं किया गया ? सेम्पल से नहीं मिलता हुआ माल क्यों लिया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : वजन बराबर था। केवल ग्लेज उसमें ज्यादा थी इसलिए बुरा नहीं समझा गया और यह जरूरी नहीं समझा गया कि री-टेण्डर किया जाय।

श्री भैरोंसिह : जब खुद मानकर चल रहे हैं कि सेम्पल के अनुसार उसने डिलीवरी नहीं दी तो दो परसेण्ट की पेनल्टी क्यों दी गई ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इतनी ही कमी थी इसलिए।

श्री भैरोंसिह : तो क्या यह नियम है कि सेम्पल के अनुसार अगर सामान नहीं भी दे, रही दे दे तो उस सेम्पल के और उस माल के बीच में कितना डिफरेंस है वह ले लिया जावे और बाकी पेनल्टी इम्पोज नहीं की जावे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अगर बहुत बडा फर्क होता है तो रिजेक्ट भी किया जाता है और अगर साधारण फर्क होता है तो पेनल्टी लगा कर उसको मंजूर भी कर लिया जाता है।

श्री भैरोंसिह : यह आप साधारण फर्क मानते हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : ऐसा ही समझना चाहिए।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि जो लिफाफे हैं उन पर स्याही से लिखने पर स्याही फूटती है इसलिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : टाईप करा लीजिए।

श्री भैरोंसिह : क्वालिटी का फर्क है उसमें सबसे बडी शिकायत यही है। चमकने की शिकायत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : शिकायत नहीं भी हो, फिर भी यह गलत प्रोसीजर है कि सेम्पल किसी और चीज का हो और सप्लाई किसी और की हो। ग्लेजपेपर के टेण्डर करते तो शायद ५-१० परसेण्ट कम में मिल सकते थे। यह तो बहुत बडी कमी है।

(विराम)

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

Page No.24

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ।

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

टेप मेजरिंग की खरीद

३२७. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मंत्री, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री विभाग द्वारा सन् १९६१-६२ के लिए आमंत्रित टेण्डर नोटिस के आइटम नं० २१४, २१५, २१६ पर अंकित टेप मेजरिंग किस किस फर्म से कितनी कितनी कीमत की और किस किस दर में खरीद की गई ?

(२) क्या यह सही है कि यह खरीद लोएस्ट टेण्डर से नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों, और नहीं, तो कृपया टेण्डरर फर्म्स की दरों का कम्पेरेटिव स्टेटमेंट यदि बनाया हो तो उसकी प्रतिलिपि कारणों सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(३) क्या इस खरीद के माल के स्पेसिफिकेशन निर्धारित थे और इस माल का टेस्ट करवाया गया था ? यदि हां, तो स्पेसिफिकेशन क्या थे और टैस्ट का क्या परिणाम रहा ?

(४) क्या यह सही है कि माल टेण्डर की शर्तों के अनुसार निर्धारित समय तथा क्वालिटी के आधार पर सप्लाई नहीं किया गया ? यदि हां, तो कृपया बतावा जावे कि कितने समय में माल सप्लाई करना था और वास्तव में कब कब कितना कितना किया गया ?

उप-मंत्री, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री (श्रीमती कमला बेनीवाल) : सदस्य महोदय की जानकारी के लिए पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । (कृपया परिशिष्ट ३ देखिए) ।

श्री भैरोंसिंह : नहीं मिला ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपको प्राप्त नहीं हुआ है ? इसमें कई विवरण हैं । नहीं मिला तो आप देखलें और बाद में मैं बता सकती हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : प्रश्न संख्या ३०१ । एक प्रश्न छोड देता हूं ३०० नम्बर का क्योंकि वह अंग्रेजी में है ।

प्रेस कर्मचारी यूनियन बीकानेर—
डाइरेक्टर का मुआयना

३०१. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या मंत्री, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या डाइरेक्टर, राजकीय मुद्रणालय ने माह सितम्बर सन् ६० में बीकानेर के राजकीय मुद्रणालय का दौरा किया और प्रेस कर्मचारी यूनियन को उसके रजिस्टर, सदस्यता शुल्क वगैरह दीगर कागजातों का मुआयना कराने के लिए मजबूर किया ?

(ख) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर ने रोकड़ चैक करके अपने हस्ताक्षर भी उस पर किए ?

Page No.25

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(ग) यदि हां, तो किस कानून के तहत ?

(घ) क्या अधिकारी वर्ग द्वारा की जा रही इस प्रकार की ट्रेड यूनियन आन्दोलन में दखलन्दाजी सरकार उचित समझती है ?

उप-मन्त्री, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (क) जी हां, संचालक ने दौरा किया था तो प्रेस कर्मचारी यूनियन बीकानेर के रजिस्टर शुल्क आदि के कागजात को देखा था।

(ख) जी हां।

(ग) विभागीय संचालक होने के नाते यूनियन की मांगों से संबंधित कागजात देखना आवश्यक हो जाता है।

(घ) जी नहीं, विभागीय कर्मचारियों द्वारा यूनियन के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : रोकड को चैक करने की क्या आवश्यकता थी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मेम्बरशिप बनी है वह कायदे में बनी है या नहीं। फीस ली है या नहीं, उसको देखने की जरूरत पडी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यूनियन के मेम्बर कौन हैं, कितने हैं यह लेबर डिपार्टमेंट के देखने की बात है न कि डाइरेक्टर के ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यूनियन ने मांग की थी कि हमें दूसरी यूनियन के मुकाबले में रिकॉग्नाइज करो इसलिए रजिस्टर देखना जरूरी था क्योंकि रिकमण्ड करना था।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो रोकड चैक की गयी वह अनावश्यक रूप से चैक की गयी और यह देखने के लिए चैक की गयी ताकि उनको मालूम हो जाए कि यूनियन के मेम्बर्स कौन २ हैं ताकि उनको पोनेलाइज किया जाए। यह तो लेबर डिपार्टमेंट ही वेरिफाई करके भेज सकता है कि इसकी मेम्बरशिप क्या है और कौन कौन उसके मेम्बर हैं। उसके तहत रिकाग्नीशन का प्रावधान रखा गया है, इसका मतलब क्या है ?

मंत्री, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री (श्री हरिश्चन्द्र) : एम्प्लायर है उसको भी राइट है देखने का।

श्री मानिकचन्द सुराणा: वह तो इसलिए चैक किया ताकि आपका अध्यक्ष यह जान ले कि इसके कौन २ मेम्बर हैं। उनको दण्डित करने के लिए, उनका ट्रांसफर करने के लिए रजिस्टर को चैक करते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो मैं समझता हूं कि वाजिब बात आपने नहीं कही। दो यूनियनें थीं उनका वेरीफिकेशन करने के लिए वहां भेजा गया। उन्होंने वेरीफाई करके रिपोर्ट दी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप यह काम लेबर डिपार्टमेंट से क्यों नहीं करवाते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : वह भी देख सकता है, हमें उसमें एतराज नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आप इस प्रकार का आश्वासन देते हैं कि भविष्य में लेबर डिपार्टमेंट के जरिए ही इस प्रकार की इन्फरमेशन्स कलेक्ट करवायेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह तो अध्यक्ष महोदय ट्रेड यूनियन एक्ट के खिलाफ है जिसमें इस तरह की एक्टीविटीज को एण्टी ट्रेड यूनियन एक्टीविटी कहा गया है। इस तरह की दखलन्दाजी डिपार्टमेंट नहीं कर सकता।

श्री हरिश्चन्द्र : कोई दखलन्दाजी करने का सवाल नहीं है Only verification of membership. There is no 'Dakhalandazi' at all.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : जब आप उनके रजिस्टर्स को चैक करते हैं तो यह दखलन्दाजी नहीं है तो और क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी नहीं, दखलन्दाजी कतई नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपको उस प्रक्रिया को एडाप्ट करने में क्या कठिनाई है ? हम यह जानना चाहते हैं। या तो यह है कि लेबर डिपार्टमेंट को आप अथोरिटी नहीं समझते हैं या फिर उनमें विश्वास नहीं है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी बात कतई नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरह से ट्रेड यूनियन्स की एक्टीविटीज को एम्प्लायर देखेगा तो बहुत आसानी से उनको पीनेलाइज किया जा सकता है। इसीलिए ही दूसरे विभाग खोले गए हैं कि नियंत्रण रख सकें। इसलिए यह जो गवर्नमेंट की प्रेक्टिस है वह बन्द की जानी चाहिए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह तो बहुत ही सीरियस है।

श्री हरिश्चन्द्र : कोई हस्तक्षेप करने का न तो पहले ही इरादा था और न अब है। लेकिन वैरीफिकेशन तो एम्प्लायर ही करेगा। That has been the opinion of Labour Department also. Labour Department said that the employer has a right......

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : एम्प्लॉयर का कोई राइट नहीं है कि यूनियन में जाकर उनके रजिस्टर वगैरह को चैक करे। मैं ४० साल से ट्रेड यूनियन्स में काम कर रहा हूं।

श्री हरिश्चन्द्र : तो फिर कैसे वैरीफाई करेगा ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप उस डाइरेक्टर की अनावश्यक रूप से रक्षा करना चाहते हैं जिसने गलत इण्टरफियरेंस किया, जो गलत रूप से टेण्डर इनवाइट करता है और गलत रूप से लिफाफे मंजूर करता है; आप उसकी रक्षा करना चाहते हैं।

श्री कुमारानन्द : इसका साफ जवाब मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सरकार की ऐसी इच्छा नहीं है कि जो श्रम के कानून हैं उनका उल्लंघन किया जाए। फिर भी मंत्री महोदय इसको देख लें। मैं समझता हूं कि उनके विभाग द्वारा कोई ऐसी कार्यवाही नहीं होगी जो कि कानून के खिलाफ हो।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह हुआ कि जिस कारण से रजिस्टर देखे लोगों का वहां से ट्रांसफर किया और लोगों ने रिप्रेजेण्टेशन दिए......

Page No.27

श्री अध्यक्ष : सवाल ट्रांसफर का नहीं है।

श्री भैरोंसिह : रजिस्टर्स वगैरह चैक किए उसके बाद में ट्रांसफर्स हुए हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : I may respectfully beg to submit that transfer is no penalisation.

श्री भैरोंसिह : ट्रांसफर्स एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स से नहीं हुए हैं बल्कि इसलिए हुए हैं कि उन्होंने ट्रेड युनियन के सारे रजिस्टर को देखा है और उसमें भाग लेने वालों के ट्रांसफर्स कर दिए। इसके कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह देखना जरूरी है कि कौन सा ट्रांसफर पीनेलाइज करने के लिए हुआ है। The very right of seeing those registers by the employers should be stopped.

श्री अध्यक्ष : इसलिए जैसा मैंने कहा कि ट्रांसफर हुए या नहीं, हुए, इस संबंध में अभी कोई विचार नहीं किया जा सकता और न यह उचित ही है। लेकिन रजिस्टर देखना अगर कानून के विरुद्ध है तो आप उसको फिर दिखवा लीजिए। इसमें जल्दबाजी का सवाल नहीं है। अगर यह प्रैक्टिस लेबर लॉज के अनुसार नहीं है तो उसको देख लें। Please have it re-examined in the light of what the hon. member has said.

प्रश्न समाप्त हुए।

(११ म. प.)

संयुक्त समाजवादी विधायक दल का गठन

मुझे प्रजा समाजवादी दल के नेता श्री रलीधर व्यास एवं समाजवादी दल के नेता श्री रामकिशन ने यह सूचित किया है कि राजस्थान विधान सभा में समाजवादी तथा प्रजा समाजवादी विधायक दलों का विलय हो जाने के फलस्वरूप समाजवादी संयुक्त दल का गठन हुआ है।

इस नए दल का नाम "समाजवादी संयुक्त दल" है और इसके नेता श्री मुरलीधर व्यास हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : बधाई है दुबारा विवाह पर।

श्री रामकिशन (बैर) : जो विधुर हैं या बूढ़े हैं, वे बहुत जल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसिन्द) : दो से एक हुए उसके लिए बधाई है; मगर कहीं फिर एक से दो न हो जाएं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो हिन्दू मैरिज है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : Who is the husband and who is wife?

पंचायत एवं विकास विभाग से संबंधित सदन की मेज पर रखी गई अधिसूचनाएं

श्री भवानीशंकर नन्दवाना (उप-मंत्री, पंचायत एवं विकास) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत एवं विकास विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :

(१) अधिसूचना संख्या एफ. २४। पी. एस.।रूल्स (५) ४०।६२-१२०।, २२, दिनांक २२ नवम्बर, १९६२, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सर्विस (रिवाइज्ड पे स्केल्स) रूल्स, १९६२ प्रकाशित किए गए हैं।

(श्री भवानी शंकर नन्दवाना)

(२) अधिसूचना संख्या एफ. ४।एल. जे.।२ (२५) ६२।२७९३४, दिनांक २१ दिसम्बर, १९६२, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (एपोइण्टमेंट आफ कौन्सिल्स) रूल्स, १९६२ प्रकाशित किए गए हैं।

(१२. ०० मध्यान्ह)

आय-व्ययक १९६३-६४ पर अग्रेतर सामान्य बहस

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष हमारे वित्त मंत्रीजी ने जो चीनी हमलावरों के शोके शाया में अपना बजट पेश किया है उसको देख कर हमको वाकई दुख हुआ। हम समझते थे कि सरकार........

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : हमले से दुख हुआ या किस से दुख हुआ ?

श्री मानसिंह महार : आपके तो हर काम से दुःख होता है। दुख यह है कि क्या क्या बतलावें।

सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान में जहां पर एक इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए हर आदमी, क्या गवर्नमेंट बेन्चेज पर बैठने वाले, क्या कांग्रेस बेन्चेज पर बैठने वाले, चाहे इधर बैठने वाले किसी भी पार्टी के हों, सबने इसको बेकार बजट बताया है। मैं समझता हूं, भारत के इतिहास में ऐसा थर्ड ग्रेड बजट पेश करने का यह प्रथम अवसर है.....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : क्या इससे पहले कोई फर्स्ट ग्रेड बजट पेश होता रहा है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसिन्द) : और उसी तरह का आपका भाषण हो रहा है।

श्री मानसिंह महार : यह ऐसा बेकार बजट है कि इसके बारे में कुछ कहना भी शर्म की बात है। लेकिन मैं समझता हूं, इस पर चुप रहा जायगा तो वित्त मंत्रीजी समझेंगे......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं देता; दूसरा भोंपू बज रहा है।

श्री अध्यक्ष : वह तो तीसरा है।

श्री मानसिंह महार : मैं निवेदन कर रहा था इस बजट के बारे में यदि इस भोंपू की शाया में भाषण नहीं दिया जायगा तो किस वक्त दिया जायगा। मैं मानता हूं माननीय सदस्य ने जो बात कही वह सही है। इस बजट में शुरू से आखिर तक भोंपू ही भोंपू है और यह भोंपू भी उपयुक्त समय में बजा है। हमको मालूम है कि वित्त मंत्रीजी ने किस प्रकार दिल और दिमाग को किस तरो और ताजा हकीकत में यह बजट बनाया है।

मैं समझता हूं, राजस्थान जैसे कृषि प्रधान प्रदेश में कृषि के हर पहलू पर टैक्स लगाना सरकार के लिए शर्म की बात है। सरकार कहती है कि टैक्स के बिना सरकार चलाई नहीं जा सकती और आड ली जाती है चीन के हमले की। हम मानते हैं कि भारत पर चीन का आक्रमण हुआ। हम यह भी मानते हैं कि आपको पैसा चाहिए खर्च के लिए। लेकिन इसको मानते हुए हम आपको सुझाव देते हैं कि आप

(श्री मानसिंह महार)

फिजूल खर्च मत करिए, अपने हाथ को रोकिए। मुझे दुख होता है जब हमारे मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि हम जब जिला वगैरह कम करने की बात कहते हैं तो उस पक्ष के लोग कहते हैं कि हमारे जिले को मत तोडिए। यह बात सही है कि हमारी तरफ से इस तरह कहा जाता है। लेकिन कहा क्यों जाता है? मुख्य मंत्रीजी ने इस तथ्य को तोड मरोड कर रखा। जिस समय तहसीलें टूट रही थीं उस समय हमने यह नहीं कहा था कि तहसीलें मत तोडें। हमने यह कहा था कि हुरडा छोटी जगह है वहां तहसील न रख कर बनेडा जो बडी जगह है वहां रख दीजिए। इस तरह की बात कही जाती है। मैं राजस्थान के लिए कांक्रीट बातें कहूंगा उन पर गहराई से सोचें। राजस्थान में इस समय २६ जिले हैं। आप जयपुर और बांसवाडा जिलों का मुकाबला कीजिए। बांसवाडा जिला कितना छोटा है और जयपुर जिला कितना बडा है आप इस पर विचार करिए। या तो आप छोटे जिलों में कलेक्टर रखे वे आर. ए. एस. केडर के रखिए, आई. ए. एस. केडर के मत रखिए। यदि आर. ए. एस. केडर के कलेक्टर नहीं रख सकते हैं तो २६ जिलों को तोड कर उनके स्थान पर १५ या १० जिले रखिए। यह मैं अपना कांक्रीट सुझाव आपके सामने रखता हूं। फिर मैं दूसरी दलील यह दूंगा कि जो जिले बनाए जावें उनके लिए एक कमेटी बनाई जावे जो सिद्धांत तय करे और उसी सिद्धांत के आधार पर नए जिले बनाए जावें। यह नहीं हो कि उन बैन्चेज पर बैठने वाले यह सोचें कि इन जिलों से विरोधी पक्ष के लोग आए हैं इसलिए उन जिलों को तोड दें। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। सिद्धान्त तय करने के लिए जो कमेटी बनाई जावे उसमें हमारे पक्ष के लोग भी लिए जावें और फिर जिले बनाने के लिए सिद्धान्त तय किए जावें। आज हमारी सरकार सिद्धान्तहीन सरकार है। उसके कोई सिद्धान्त नहीं होते। यदि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में किफायत करनी है तो २६ जिले से तोड कर १५ या १६ कर दिए जावें।

जिलों को तोडने के बाद आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर २११ तहसीलें हैं और तहसीलों में भी आप देखिए, आमेर और जमुवा रामगढ जैसी बडी बडी तहसीलें हैं जहां पर एसेम्बली की एक सीट से भी ज्यादा आबादी है और एक एम. एल. ए. से भी ज्यादा उस तहसील में है। दूसरी तरफ अजमेर में किशनगढ जैसी छोटी तहसीलें हैं........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : गलत है आपकी बात।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अजमेर में बडी बडी तहसीलें हैं।

श्री मानसिंह महार : राजस्थान सरकार के आंकडे मौजूद हैं.....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आंकडे बताइये न जयपुर के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं तो। यहां पर X X X X

श्री मानसिंह महार : मैं नसीराबाद के माननीय सदस्य की तरह XXXX नहीं हूं। मैं जो कुछ यहां रखता हूं वह तथ्यों सहित रखता हूं। अजमेर जिले में सरवाड तहसील छोटी है। किशनगढ की एसेम्बली सीट है..

XXXX अध्यक्ष पीठ की आज्ञानुसार निकाले गए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तोड दी गई।

श्री मानसिंह महार : एक तोडी है। मैं चाहता हूं कि किशनगढ की चारों तहसीलें तोड कर एक कर दी जावे·····

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हमें कोई एतराज नहीं है, डांगी साहब जानें।

श्री मानसिंह महार : स्वतंत्र पार्टी के आदमी न्यायपूर्ण बात के लिये विरोध नहीं करेंगे। यह आदत तो आपकी है, जो झूठी बातें करते हैं। जितना त्याग चाहिये हम करेंगे। छोटी छोटी बातों के लिये हम झगडा नहीं करते। अजमेर में छोटी तहसीलें नहीं हैं तो इकरार करें······

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: इकरार करते हैं। रहम किया गया है आप पर······

श्री मानसिंह महार : रहम तो उन पर हैं जो XXX जिन्दा बैठे हुए हैं दूसरों पर क्या रहम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, २११ तहसीलें हैं, मुद्दे की बात है·····

श्री गिरधारीलाल व्यास : १८० तहसीलें हैं।

श्री मानसिंह महार : २११ तहसीलों को भी कम कर सकते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: XXX शब्द का प्रयोग इन्होंने मतलब नहीं समझते हुए किया है इसलिये मेरे ख्याल से इसको वापिस लिया जाय।

श्री मानसिंह महार : सब-डिविजन ८२ हैं उनमें भी कमी हो सकती है। यदि छोटे सब-डिविजन हों तो उनके बारे में भी विचार करिये, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे कमी की जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जयपुर की तहसील तोडी जाय।

श्री मानसिंह महार : मेरी कांस्टिट्यूएन्सी में सवाई जयपुर तहसील बहुत छोटी है उसको सरकार तोडेगी तो मैं स्वागत करूंगा। या तो उसको तोडा जाय या जमुवारामगढ और आमेर तहसील जो बडी बडी हैं उनके हिस्से इसमें मिलाकर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया जाय। मैं यह नहीं कहता कि छोटी तहसील को नहीं तोडा जाय। यह वाजिब मांग है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस लाइट में सरकार, वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को किसी प्रकार से तंग नहीं करें।

इसी तरह सब-डिविजन ८२ हैं उनमें भी कमी करनी है तो करिये। मेरा कांक्रीट सुझाव है। राजस्थान में २३२ पंचायत समितियां हैं। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा १८० तहसीलें करदी हैं तो तहसीलों और पंचायत समितियों का एक यूनिट बना दिया जाय। यदि तहसील और पंचायत समितियों का एक यूनिट बनायेंगे तो ५२ पंचायत समितियां तो तोड ही सकते हैं। यदि एडमिनिस्ट्रेशन में बचत करनी है तो आपको यह बात करनी पडेगी।

आप लोगों पर टैक्स लगाते हैं वह मत लगाइये मैं, यह कॉन्क्रीट सुझाव देता हूं कि डिस्ट्रिक्ट्स को कम कीजिये, सब-डिवीजनन्स को कम कीजिये, तहसीलों के अन्दर कमी कीजिये, पंचायत समितियों के अन्दर कमी कीजिये और जो खर्च कम हो इसमें, उस हिसाब से, जो इस बजट के अन्दर किसानों पर टैक्स लगाया है, उसमें कमी कीजिये। यह मेरा पहला कान्क्रीट सुझाव है।

XXX अध्यक्ष पीठ की आज्ञानुसार निकाला गया।

(श्री. मानसिंह महार)

हमारे मुख्य मंत्री जी अमूमन कहा करते हैं कि आपका क्रिटिसिज्म होता है, वह डेस्ट्रक्टिव होता है। मैं आज यह कन्स्ट्रक्टिव सुझाव देना चाहता हूं। यह पहली बात हुई।

अब मैं आपसे निवेदन करूं, एक बडे भारी खर्च में कमी हो सकती है। वह यह है कि जब से आपने न्याय का पृथकीकरण किया है तब से एस. डी. ओ. के पास काम कम हो गया है। आप अगर विकास अधिकारी का पद समाप्त कर देंगे तो बडी भारी किफायत होगी। मैं जानता हूं, बी. डी. ओ. क्यों बना रखा है। इसलिए बना रखे हैं कि आप चाहते हैं, अपने अपने रिश्तेदारों को आर. ए. एस. में किसी प्रकार चिपकाये रखा जाय....

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह झूंठी बात है।

श्री मानसिंह महार : जी, सच बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके नमूने पेश करता हूं। झूंठी बात कहने पर मुझे नमूने पेश करने पडते हैं कि हमारे यहां मंत्रियों के कितने रिश्तेदार हैं। आप मुख्य मंत्री जी को ले लीजिये। मुख्य मंत्री जी के दामाद बी. डी. ओ., सांगानेर हैं, मुख्य सचिव के भाई जो गोरधन सिंह मेहता हैं, उनके जो लडके हैं....

श्री अध्यक्ष : आप व्यक्तिगत आफिसर्स के लिए न कहें तो ठीक है।

श्री मानसिंह महार : ये वाध्य करते हैं इसलिए नमूना पेश करना पडता है।

श्री अध्यक्ष : ये तो यूं ही करते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इनके भी तो रिश्तेदार हैं।

श्री मानसिंह महार : हमारे रिश्तेदारों के लिए, अध्यक्ष महोदय, यह तो पन्द्रह पन्द्रह साल तक कहा कि ईमानदार हैं लेकिन प्रमोशन के वक्त प्रमोशन बेईमानों को दिया जाता है, ईमानदारों को नहीं दिया जाता है। मैं सदन को चैलेंज देता हूं कि अगर मेरे रिश्तेदारों के लिए कहें कि बेईमान हैं, प्रशासन में भ्रष्टाचार करते हैं तो मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इस्तीफा दिला दूंगा....

श्री गिरधारीलाल व्यास : जयपुर की परम्परा है।

श्री मानसिंह महार : परम्परा तो आपकी है, उदयपुर ने राजस्थान का नाश कर दिया है। मैं कहता हूं कि मेवाड....

श्री निरंजन नाथ आचार्य (उप-शिक्षा-मंत्री) : इतिहास दूसरी बात कहता रहा है।

श्री अध्यक्ष : ये आधुनिक इतिहास की बात कह रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : मेरे नेता ने उदयपुर का नाम लेने से इन्कार कर दिया है इसलिए उधर न जाकर....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : नेता भी तो आपके उदयपुर के हैं।

श्री मानसिंह महार : इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि बी. डी. ओ. को आप हटा दीजिये और एस. डी. ओ. को काम दीजिये। अगर एस. डी ओ. को न दे सकें, तो तहसीलदार को दे दीजिये, इससे आपके प्रशासन के खर्च में काफी कमी होगी।

एक नई बात यह है कि इमरजेन्सी के टाइम में खर्च में कमी करें। अगर खर्च में

(श्री मानसिंह महार)

कमी करते तो कोई नई बात होती। लेकिन एक कोई सेमिनार हुआ डेवलपमेंट का, अध्यक्ष महोदय, उसने फैसला कर दिया कि प्रत्येक पंचायत के अन्दर एक ग्राम सेवक दे देंगे। मैं पंचायत के सरपंच की हैसियत से इस सदन को नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत के पास आज कोई काम नहीं है। आप ग्राम सेवक सवा सौ, डेढ सौ रुपये की तनख्वाह पर एक पंचायत को दे देंगे तो वह क्रिमिनल वेस्ट आफ मनी होगा। अध्यक्ष महोदय, इससे अच्छा तो तब होगा कि आप दो तीन पंचायतों का ग्रुप करके एक ग्राम सेवक को उन तीनों पंचायतों का सेक्रेटरी बना दें तो वह बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक पंचायत में एक ग्राम सेवक देने का फैसला हो गया, उसको आंख मीच कर लागू कर देना और हर पंचायत के लिये एक ग्राम सेवक सेक्रेटरी के रूप में दे देना ठीक नहीं है। It is a criminal waste of our money मैं कहूंगा, अगर किसी चीज को क्रिमिनल वेस्टेज की संज्ञा दी जा सकती है तो वह इस चीज को दे सकते हैं। जो माननीय मुख्य मंत्री का सुझाव है कि हर पंचायत के लिए ग्राम सेवक रखा जाय और उसको सेक्रेटरी का काम दिया जाय, इसका मैं विरोध नहीं करता हूं। लेकिन एक पंचायत पर एक ग्राम सेवक रखना राजस्थान की जनता, राजस्थान के टैक्स पेअर के प्रति घोर अन्याय है। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री को इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए। और इस बात पर पुनर्विचार करके दुबारा अपनी घोषणा को बदलना चाहिए, यह बहुत न्यायोचित बात है।

इन चन्द बातों को निवेदन करने के बाद, मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय, इस बजट को देखने से हमें ऐसा महसूस हुआ कि सरकार खर्च में कमी नहीं करना चाहती। खर्च वही का वही रहा है। तीन साल से देखते आ रहे हैं, सरकार कहती है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेज में कमी करते हैं लेकिन कमी कुछ नही होती है। अगर कुछ आदमियों को कम किया जाता है तो उन्हें इधर से हटा कर उधर लगा दिया जाता है। तब भी कमी नहीं की जाती है और खर्च बढता जा रहा है अनाप-शनाप, १९५२ से आज तक जितना खर्चा बढा है उसका अन्दाज आप लगा लीजिये। लेकिन हमारी सरकार तो चलती है अपने सेक्रेटेरियेट की गाइडेंन्स पर।

आप सेक्रेटेरियेट में जायं, अगर आप को खर्च में कमी करनी है। सेक्रेटेरियेट में आपने अनाप-शनाप अफसरान बैठा रखे हैं। बारह बजे आफिसर जाते हैं, डेढ बजे वे लंच पर जाते हैं और फिर चार बजे वे दस मिनट के लिये आकर घर चले जाते हैं। तो वह खर्च कम कैसे हो सकता है।

मैं कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मुझे बडा दुख हुआ, मैं एक रोज कुछ आंकडे इकट्ठे करने के लिये सेक्रेटेरियेट गया, तब मुझे मालूम हुआ कि सेक्रेटेरियेट बिल्डिंग में जो आदमी बैठ जाय सेक्रेटरी के नाम से उसको सेक्रेटेरियेट अलाउन्स मिलेगा। लेकिन सेक्रेटेरियेट के पास ही न्यू हाई कोर्ट बिल्डिंग है, उसमें हैड्स आफ डिपार्टमेंटस बैठते हैं, वे बडे बडे हैड्स आफ डिपार्टमेंट्स हमारी पालिसीज को एक्जीक्यूट करते हैं, जिनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है उनको कोई अलाउन्स नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि उनको अलाउन्स दिया जाय, लेकिन सेक्रेटरीज का अलाउन्स क्यों नहीं

(श्री मानसिंह महार)

बन्द कर दिया जाय। यह अलाउन्स किस बात का देते हैं ? क्या हार्ड ड्यूटी वे देते हैं ? वे दफ्तर छः घंटे के लिए दिन में जाते हैं, उसमें से सिर्फ काम के लिए तीन घंटे देते हैं। अगर मेरी इस बात को कोई चैलेंज करे तो मैं यह साबित करने के लिए तैयार हूं। फिर सेक्रेटेरियट अलाउन्स किस बात का देते हैं ? आप सेक्रेटरी को देखिये, नये नये महकमें, नये नये सेक्रेटरी-यह सरकार इसके लिए मशहूर है। ये पोस्ट, पोस्ट क्रियेट करने के लिए नहीं की जाती हैं, ये पोस्ट आदमियों के लिए क्रियेट की जाती हैं। अगर किसी मि० एक्स को सेक्रेटरी बनाना है तो फलां विभाग के अन्दर एक नई पोस्ट क्रियेट कर दी यह नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करूं कि मितव्ययता के लिहाज से मेरे मित्र, जो उधर की बैंच पर बैठने वाले हैं, ने कहा कि सिर्फ तीन सेक्रेटरी रहें। वे शायद ज्यादा आइडलिस्टिक हो गये, लेकिन पांच छः सेक्रेटरी से काम हो सकता है। फिर उनके नीचे जो लम्बा चौडा पेराफरनेलिया है, उसको भी कम किया जाय। यह मेरा सुझाव है, वित्त मंत्री इस पर गौर करेंगे, यह मैं आशा करता हूं।

मैं निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कहा गया कि मंत्रियों और उप-मंत्रियों में कमी की जाय। इसका उस पक्ष में बैठने वाले मित्रों ने घोर विरोध किया। उस घोर विरोध को देख कर मैंने सोचा, यह बात पार पडने वाली नहीं है, इसलिए जब उस डिमान्ड पर वोटिंग हुआ तो हम न्यूटरल रह गये और सोचा कि वहां कमी नहीं कर सके तो जहां हम सुझाव दें वहां शायद कमी कर दें। मैं समझता हूं, पी.ए., प्राइवेट सेक्रेटरी और न जाने क्या-क्या आपके नीचे काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां तक हुआ है कि हमारे वित्त मंत्री ने कहीं से बुला कर एक रिटायर्ड आदमी को रख लिया क्योंकि जो सेक्रेटेरियट कैडर है, उसमें उन्हें विश्वास नहीं है। वे तो कोई अजमेर के पुराने साथी को लेंगे। जो सेक्रेटेरियट के परमानेन्ट आदमी थे, उनकी सीनियरिटी खत्म, उनके प्रमोशन के चान्सेज खत्म, इसलिए कि वित्त मंत्री जी अपना आदमी चाहते हैं · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही नहीं कि आप लोगों ने उन्हें एडवाइज करने के लिए अपना आदमी दिया है। यह आपका आदमी है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : इलेक्शन के · · · · ·

श्री मानसिंह महार : मैं कॉम्युनिस्ट टेक्टिक्स में बिलीव नहीं करता हूं, कॉम्युनिस्ट्स यही करते हैं। अपने आदमी को इन्फिलटरेट करते हैं, इसलिए सरकार को कह देता हूं · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि वह आदमी पब्लिसिटी इन्चार्ज था ?

श्री बालकृष्ण कौल : जब इलेक्शन हुए थे।

श्री मानसिंह महार : वह हमारी खूबी है, अगर वह गलत काम में जाता है तो हम विरोध करते हैं। अगर वह हमारा आदमी है तो क्या हो गया ? हम ऐसे आदमी नहीं हैं कि हमारा आदमी है तो उसके लिये कान में तेल डालें और दूसरी पार्टी का आदमी होगा तो उसका विरोध करेंगे।

एक माननीय सदस्य : आप इन्स्टीगेट न करें।

श्री मानसिंह महार : इन्स्टीगेट तो आप कर रहे हैं। उन्होंने (वित्त मंत्रीजी) गलत काम

(श्रीं मानसिंह महांर)

किया तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो मजबूर हूं, चीफ मिनिस्टर ने कहा जिससे किया एक माननीय सदस्य ने कहा कि वे ऊपर से आये हुए हैं। वाकई में वे तो ऊपर से थोपे हुए हैं। मैं उनकी हिम्मत की जरूर दाद देता हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो पेराफरने-लिया है उसमें कमी करें। उनको और किसी धन्धे पर भेज दीजिये। आप इमर्जेन्सी के समय में दो तीन मंत्री रखिये या प्राइवेट सेक्रेट्री रख लीजिये। यह एक कमी की चीज है।

अब मैं एक मद पर आता हूं, अध्यक्ष महोदय, जिसकी तरफ मैं जाना नहीं चाहता मगर मजबूर होकर उसका जिक्र करना पडता है क्योंकि कल उस तरफ बैठने वाले मेरे एक मित्र ने अपनी वही पुरानी रट जागीरदारों की लगाई। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जागीरदारी खत्म हो गई १९५४ में और हम साधारण नागरिक बन गये और सोसाइटी में ऐसे ढले कि उधर बैठने वालों के दांत खट्टे हो गये। एक दो का फर्क रहा वरना हम शायद उधर बैठते।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आये तो भी मत नहीं मिले।

श्री मानसिंह महार : हमारे डीडवाने से आने वाले मित्र हैं, उनका फोबिया नहीं जाता। हो सकता है कि जोधपुर रियासत के समय में उनके साथ जुल्म हुआ हो या ज्यादतियां हुई हों, उनको पीटा गया हो। अगर उनके साथ जोधपुर रियासत में ज्यादतियां हुई हों और उनको पीटा गया हो और वह मार अभी तक याद आती हो तो मैं उसके लिये माफी चाहता हूं कि उनको पीटा गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सदन में सही वातावरण बनाये रखना है तो हमें इस प्रकार जातिवाद की बात नहीं कहनी चाहिये। मैं नहीं चाहता कि मैं कॉपरेटिव डिपार्टमेंट के बारे में कुछ कहूं मगर आप मुझको उसके बारे में कहने लिए मजबूर करते है। मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे मजबूर न करें। हम चाहते हैं कि हम जातिवाद से ऊपर उठे रहें। मगर अफसोस है, अध्यक्ष महोदय, कि जातिवाद का नग्न चित्र हमारे सामने प्रदर्शित किया गया और यह कहा गया कि जागीरदारों के मुआवजे व जागीर रिजम्पशन के मामलों को तय करने के लिये जागीरदार को जागीर कमिश्नर मुकर्रर किया गया। मैं यह कहूंगा कि एक ऐसे आदमी को जागीर कमिश्नर मुकर्रर किया गया जिससे जागीरदारों को फायदा होने के बदले बडा नुकसान हुआ। मैं मुख्य मंत्रीजी से और जो वित्त मंत्री इस विभाग से ताल्लुक रखते हैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि हम पर इस प्रकार का लांछन न लगे इसके लिये आप जागीर कमिश्नर के पद से जागीरदार को आज ही हटा दीजियेगा। हम ऐसे नहीं है जो जातिवाद को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। और न हम यह चाहते हैं कि जातिवाद को प्रोत्साहन मिले। मैं समझता हूं कि सरकार की यह इच्छा थी कि जागीर कमिश्नर अगर जागीरदार होगा तो वह जागीरदार होने के नाते जागीरदार की डिफिकल्टीज को अच्छी तरह से समझेंगे, इसलिये जागीरदार को रखा। मगर मेरे भाई को इससे बडा दुःख हुआ। हमें कोई दुःख नहीं है चाहे सरकार किसी को भी जागीर कमिश्नर बना दे। मैं तो यहां तक कहूंगा कि राजा श्री निरंजनसिंहजी को ही जागीर कमिश्नर बनादें तो हमें कोई दुःख नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी : राजा निरंजनसिंह जागीरदार है।

श्री मानसिंह महार : मुझे यह सुन कर खुशी हुई कि उन्होंने राजा निरंजनसिंह जी को भी हमारे साथ लगा दिया है। अगर यही बात आज से तीन वर्ष पहले हो जाती और उनको हमारे साथ लगा दिया जाता तो राजस्थान में कॉपरेटिव मूवमेंट फेल क्यों होता। राजा निरंजन सिंहजी जब तक कॉपरेटिव विभाग में रहे आपने उनको भाई बनाया, आपने उनको अपना सरताज बनाया और कॉपरेटिव डिपार्टमेंट में जाटवाद का बोल बाला रहा। मैं यह कहूंगा कि अगर जातिवाद का नग्न चित्र कहीं देखने को मिलता है तो वह कॉपरेटिव विभाग है। वहां आपको मिलेगा। यह बात मैं एक बार नहीं हजार बार कहता हूं और इस बात के लिये ट्रेजरी बैंचेज को चैलेंज देता हूं कि अगर यह सही नहीं हो तो वे इसको रिफ्यूट करें। यह बात मैं कहता हूं मगर मुझे बडा दुःख है इसको कहने का। मैं यह बात कभी नहीं कहता मगर जातिवाद की तरफ कुछ लोग उभारे जाते हैं। वे अपने बचपन में कुछ कहते हों। समस्या ऐसी आती है कि मैंने यह कहा कि राजा निरंजनसिंहजी को जागीर कमिश्नर बना दिया जावे तो मेरे मित्र ने उनको जागीरदार बताया। मैं मेरे मित्र से कहना चाहूंगा कि जिन्होंने उन्हें जागीरदार की बात कही अगर वे उनको पहले ही इस तरह की राय देते। मगर उस समय उन्होंने उनको यह राय नहीं दी। वे उनकी राय से अगर काम करते और थोडा बहुत काम उन्होंने किया ....

श्री मोतीलाल चौधरी : I request the Hon. member not to cast personal reflections in this way.

अध्यक्ष महोदय, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई उनसे रिश्ता नहीं। आप इस तरह से बोल रहे हैं और कह रहे है कि बचपन के दृष्टिकोण से कोई बात मैं कह रहा हूं। माननीय सदस्य ने जो शब्द कहे हैं ये व्यक्तिगत रूप से मेरे पर रिफ्लेक्ट करते हैं और यह व्यक्तिगत रूप से मेरे पर आरोप है। मैंने कोई जातिवाद का काम नहीं किया। मैं स्पष्टीकरण कर दूं कि मेरे साथ कोई उनका रिश्ता नहीं। कोई भी हो चाहे जाट हो चाहे राजपूत हो मैं सबको एक श्रेणी में मानता हूं।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह सुन कर बडी खुशी हुई कि वे सब को एक श्रेणी में मानते है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि आज जयपुर के १० मील के एरिया में काफी जमीन ले ली है। आज जो यहां के कलेक्टर थे उन्होंने जिला परिषद् की मीटिंग में कहा कि अजमेर रोड पर जिन लोगों ने अनधिकृत रूप से जमीन का कब्जा कर लिया है उनको रोकने में मैं असमर्थ हूं। यह कलेक्टर ने जिला परिषद् की मीटिंग में कहा है। हम तो जागीरदार थे मगर मैं यह कहूंगा कि मेरे पास जयपुर के आस-पास १० मील के एरिया में ५ बीघा जमीन भी नहीं है। लेकिन जो लोग अपने आपको किसान मानते हैं उनके पास आज जयपुर के दस मील के एरिया में बडी बडी जमीन हैं। और वह पिछले दस सालों में ही प्राप्त की गई है। जिस समय उनकी कुछ आवाज उठी उसी समय उन्होंने जमीन को हडप लिया। आप चाहेंगे तो लिस्ट मेरे पास है, अगर मैं उसको पेश करूंगा तो आपको मालूम होगा कि कुछ मेरे मित्र भी उसमें हैं। इसलिये मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे उसके लिये मजबूर न करें। गलत बात की तरफ इशारा करके न चलें। गल्तियां तो आप करें और दोष दूसरों को दें। चोरी और सीनाजोरी, यह चल नहीं सकती है। मैं फिर निवेदन करूंगा कि गल्तियां होती हैं लेकिन

(श्री मानसिंह महार)
आपने साइड ट्रेक निकाले है। हम जयपुर के रहने वाले हैं। हम गूंगे हैं अन्धे हैं? बहरे हैं? हमें इतना मालूम हैं, मगर हम नहीं कह सकते।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विद्युत): क्या कोई इल्लीगल कार्यवाही है जयपुर के १० मील के अन्दर जमीन लेना? Are we not entitled to take land and plough it?

श्री मानसिंह महार : १० मील रेडियस में आवादी के रूप में जमीन लेना बडा भारी अन्याय समझता हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : आबादी के रूप में किसने बेची है?

श्री मानसिंह महार: यदि मेरे स्टेटमेंट को चीफ मिनिस्टर रिफ्यूट करेंगे तो मैं इसको गलत मान लूंगा। अगर चीफ मिनिस्टर यहां होते और वे नाम के लिये कहते तो मैं नाम भी बता देता। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यहीं तक मालूम है।

एक माननीय सदस्य : क्या माननीय मंत्री यह बतावेंगे कि इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है जिसके लिये आरोप लगाये जा रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : मुझे बडा दुःख है और यह बडे दुःख की बात है कि मेरे मित्र ने मेरे आरोपों को नहीं समझा। कन्वर्शन के बाद कोई जमीन बेच दी जावे तो एतराज नहीं। मगर इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया जावे। यह एक टेन्डेन्सी हो गई है कि पहले किसी जमीन को रोकना और बाद में उसको दे देना। इसमें कई मंत्रियों वगैर ने जमीन ली हैं। डिग्गी हाउस की नजीर ले लीजिये पहले डिग्गी हाउस की जमीन को बेचने से रोक दिया गया था और बाद में जब दामोदरजी व्यास ने खुद ने अपना प्लॉट वहां ले लिया तो उसी जमीन को रिलीज कर दिया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : तभी तो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसायटी आई नहीं।

श्री मानसिंह महार: तो मैं निवेदन कर रहा था कि दामोदरजी व्यास ने वहां प्लाट ले लिया, और भी हारे हुए मंत्रियों ने, लोगों ने प्लाट ले लिये। मुझे कहने के लिये मजबूर मत कीजिये। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं मुझे मजबूर मत कीजिये यह बातें कहने के लिये। मुझे अपना भाषण जारी रखने दीजिये।

मैं सदन के समक्ष कुछ बातें रख रहा था। आज राजस्थान को, हिन्दुस्थान को फॉरेन एक्स्चेन्ज की बहुत जरूरत है, स्वर्ण की बहुत जरूरत है। तो इसके लिये हमें टूरिस्ट्स को आकर्षित करने की बहुत जरूरत है। टूरिस्ट्स को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर में बहुत अच्छी सुविधाएं दी जायं। इसकी तरफ बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। गोल्ड कन्ट्रोल ऑर्डर से हमारे सोने को छीने और जो देश में सोना लायें उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। मैं मिसाल दूंगा और एक सरकारी डॉक्यूमेंट भी पेश करूंगा।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): सरकारी डॉक्यूमेंट? ...

श्री मानसिंह महार : घबराइये मत कम्युनिस्टों का नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी कान्स्टीट्युएन्सी आमेर है, मैं जब मेरी कान्स्टीट्यएन्सी में

(श्री मानसिंह महार)

आता जाता हूं तो वहां हाथी वाले कहते हैं कि हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है । मैंने पूछा कि क्या हो रहा है ? तो बोले कि हमको १५ या २० रुपया दिया जाता है और टूरिस्ट्स गाइड हैं जयपुर में वे टूरिस्ट्स से ३० रुपया लेते हैं । इन टूरिस्टस से ३० रुपया लिया जाता है तो यह मोनोपोली क्यों टूरिस्ट्स से टूरिस्ट गाइड ३० रुपया ले और उसमें से २ रुपया सरकार को दे २० रुपया हाथीवाले को दे । वे लोग कहते हैं कि ३० हजार तो टूरिस्ट्स गाइड में बकाया पडा है । दो-दो तीन-तीन महीनों तक उन बाउचर्स को रख लेते हैं । कहते हैं कि हमारे महमान थे, १० रुपया फी हाथी लेते हैं । तो यह मोनोपोली है, इस प्रकार की मोनोपोली आज के युग में करते हैं । मैं उन बैंचेज से कहूंगा कि अगर यह गलत हो तो बोलें । मगर वे चुप हैं । मैं एक रोज हाथी ले कर गया । मैं खुद गया और वहां चैन बैरियर पर एक सरकारी नौकर बैठा था । आर्च्योलोजी का चपरासी बैठा था उसको मैंने दो रुपये दिये और कहा कि ये दो रुपये लो, मैं आमेर पैलेस में हाथी पर जाऊंगा । वह बोला कि आप नहीं जा सकते, टूरिस्ट्स गाइड का बाउचर लाइये । मैंने कहा कि मैं टूरिस्ट्स गाइड के बाप का नौकर नहीं हूं । उसने कहा, आप नाराज क्यों होते हैं, मैं क्या करूं मैं तो नौकर हूं, आप पैलेस इन्चार्ज से बात कीजिये । मैं ऊपर गया, माननीय अध्यक्ष, आप ताज्जुब में रहेंगे, सदन ताज्जुब में रहेगा, पैलेस इन्चार्ज ने मोहर लगा कर दस्तखत कर दिये : This is to inform you t' at as per Government orders, we are not in a position to allow any elephant without the voucher of Tourist Guide Service, M. I. Road, Jaipur. We are taking only Rs. 2/- as elephant tax and the vouchers issued by the Tourist Guide Service are checked by us......"

सरकारी नौकर एक गैर सरकारी संस्था के बाउचर्स को चैक करता है । "....If you would like to know the details of Government orders kindly contact with the Director, Archaeology and Museums, Jaipur.

Under the circumstances, I am unable to allow your elephant to come up with the passengers. Kindly bring the voucher from the Tourist Guide Service.

Sd./-XX

Incharge, Amber Palace,

Amber."

यह कागज है, यह मैं सदन की मेज पर रखूंगा । मैं मुख्य मंत्रीजी से, इस राजस्थान की सरकार से यह पूछूंगा कि आप कहते हैं सुरक्षा कोष में पैसा चाहिये, तो सुरक्षा कोष में फी हाथी जो यह १० रुपया लिया जाता है, वह क्यों नहीं लेते ? आपमें हिम्मत हो तो वह रुपया लीजिये टूरिस्ट्स गाइड से । फिर मुझे कहना पडेगा, इसके संचालक कौन हैं । हमें मजबूर हो कर कहना पडता है, हम कहना नहीं चाहते पर ऐसी बातें होती हैं तो कहना पडता है मजबूरन । इसके संचालक हैं श्री पण्डित । माणिकलालजी वर्मा के दामाद, जिनके कि मुख्य मंत्रीजी पर बहुत अहसान हैं ।

अफसोस है कि मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं सुन रहे हैं . . .

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री) : मैं सुन रहा हूं ।

श्री मानसिंह महार : तो जवाब दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा: इन्क्वायरी कराने के बाद ही जवाब दे सकता हूं, ऑफ हैंड नहीं दे सकता।

श्री मानसिंह महार : यह धांधली का मामला सदन में १० वर्ष से चल रहा है, ५७ से पहले में एम. एल. ए. था तब भी इस मामले को उठाया, बाद में भी उठाया। बाद में सरकार का जवाब आया कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लाखों रुपयों का इतने वर्षों में फायदा किया उस पैसे को और नहीं तो सरकार डिफेन्स फंड में ही ले ले।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आज आपके पास कितने हाथी हैं

श्री मानसिंह महार : मैं ऐसी बात का जवाब नहीं देता।

खैर, मेरे पास कोई हाथी नहीं है, मैं तो मित्र से मांग कर हाथी ले आया था। राजस्थान की जनता के पैसे पर डाका पड रहा था, उन डाकुओं को पकडने के लिये और उनको मैंने पकडा। यह कागज सदन की मेज पर भाषण समाप्त होते हो रख दूंगा या ये ले लेंगे। तो यह वडा गम्भीर विषय है। सरकार इसको साइड ट्रेक नहीं कर सकती। सुना है पिछले सदन में जनसंघ के नेता ने यह मामला सदन में रखा था तो कहा कि हमारा कोई ताल्लुक इससे नहीं है। २० हाथी भी रोज जाते हों तो २०० रुपया रोज का, ६००० रु. महीने का और ७२,००० रुपया साल का गोलमाल है। मैं यह नहीं मान कर चलता कि अकेले पण्डित का ही हिस्सा है, औरों का भी इसमें हिस्सा है।

अगर इंग्लैंड में या और कोई मुल्क में जहां आजादी को समझते हैं, वहां इस तरह का घोटाला होता तो सरकार के कई मंत्री जरूर इस्तीफा दे देते, पर यहां बडे लहजे में कह दिया जायगा कि इनकी तो कहने की आदत है, कह दिया। हमारा एक और दुर्भाग्य है कि हमें जवाब देने का अधिकार नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह बडा घोटाला है, सदन द्वारा इसके लिए जांच कमेटी बैठाई जाय। मैं आपको न्यायमूर्ति मानता हूं, इसकी जांच कराई जाय। आप गलत साबित कर देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसिन्द): आपके भाषण में कितनी बार जिक्र आया है इस्तीफा देने का?

श्री मानसिंह महार : मैं इस्तीफा देने की बात इस लिये कहता हूं कि आप भी मुझसे प्रेरणा लें और इस्तीफा दें; पर आप तो बडे चिप्पू निकले; कुर्सी के चिपक ही गये।

तो बजट पर इन बातों को बोलते हुए दुख हुआ। आज हमें कहा जाता है कि त्याग करें, बलिदान करें देश पर संकट है। जरूर त्याग और बलिदान करना चाहिये पर त्याग और वलिदान के साथ जैसे अंग्रेजी की कहावत है "First deserve, then desire" तो सरकार अपनी ओर से काम करें, अपने बैल्ट को थोडा टाइट करें। अपने भ्रष्टाचार के नमूने हैं उनको कम करें तो सरकार सोच सकती है कि हमसे भी टैक्स ले हो सकता है काश्तकारों को भी प्रेरणा मिले। रक्षा कोष में ३६ करोड रुपया किसने दिया, २० करोड रुपया राजस्थान के काश्तकारों ने दिया है।

एक माननीय सदस्य : ज्यादा।

श्री मानसिंह महार : ज्यादा हो सकता है, पर मैं अपने फीगर को नीचे ले जाता हूं, ताकि उधर के मित्र नाराज न हों। पैसा काश्तकार से आता है पर इसके मायने यह नहीं होते कि काश्तकारों को दबाया जाय और अपने बडे बडे बंगले और हवेलियां खडी करें। उस समय जो टेम्पो बना था उसे खत्म किया जाता है चीनी आक्रमण के समय में एक टेम्पो बना था उसको खत्म आपने किया। उसकी हत्या की जिम्मेदारी सरकार पर है। उस टेम्पो की हत्या का आरोप भी मैं इस सरकार पर लगाता हूं। यह दुख की बात है। जहां तक चीनी हमले का सवाल है हमारे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने कमी १९.२० के रूप में नहीं लिया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : चन्दा मत दिलाओ।

श्री मानसिंह महार : हम चाहते हैं चीनियों के खिलाफ जम कर मोर्चा हो। हम चन्दा नहीं देने के लिए नहीं कहते हैं। हम तो कहते है कि जरूर दो चन्दा, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं। आप प्रेम से चन्दा लीजिये। १५ वर्ष इन कुर्सियों पर बैठे गये हैं इसलिए आपकी मनोवृत्ति वही हो गई है जो २५ वर्ष पहले हमारी थी। हम जिस रास्ते गये थे उस रास्ते आप न जायं इसीलिए हम आपको आगाह कर रहे हैं।

अब एक अहम मुद्दे पर आता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बस एक ही।

श्री मानसिंह महार : तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस बजट को जब मैंने देखा और एमर्जेन्सी हमारे देश में आयी तो एक नयी बात देखी राजस्थान में। इस राजस्थान में अफसरों के इतने तबादले हुए जिसकी कोई हद नहीं। ऐसा मालूम होता है कि शायद एमर्जेन्सी के लिये ही यह रोके गये थे। मैं तो समझता था कि तादाद कम होगी। पहले होते थे जिनको भी मैं बेजा मानता था। लेकिन एमर्जेन्सी के आते ही इतने तबादले हुए। पुलिस में ही देखिये कि ६०-७० डी.वाई. एस. पीज के ट्रान्सफर की लिस्ट निकली। सारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भौंचक्का रह गया। जहां जो था उसको वहां से हटा दिया, कहीं डाल दिया। मेरी समझ में नहीं आता, अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि हम दो वर्ष तक तबादला नहीं करेंगे। मैं मिसाल देता हूं कि जयपुर में सांगानेर के सी.आई.को प्रमोट करके ट्रेफिक में लगाया। उसने २०-२५ दिन ही काम किया होगा कि उसको बाडमेर, जैसलमेर भेज दिया। आप कहते हैं कि तबादले कम करना चाहते है। दो साल तक एक आदमी को एक जगह पर रखना चाहते हैं। पर सब बलाये ताक। हम किसकी सिफारिश करने जांय ? और मुख्यमंत्री से कहें या और किसी से कहें कि फलां अफसर से काफी तकलीफ है उसका तबादला करो तो वे कहते हैं कि मजबूर हैं, उसको दो वर्ष वहां नहीं हुए हैं। हम सिर नीचा किये आ जाते हैं। कायदे सब के लिए हैं। वह चीज वहां फिट इन होती है जहां खास बात हैं, और जगह फिट इन नहीं होती है। पुलिस थानेदारों का बार बार तबादला कर देते हैं। चौमूं थाने में ही मेरे एम. एल. ए. होने के पश्चात् तीन थानेदारों के तबादले हो गये हैं। तीन तीन महीने में तबादले हो गये। एक आदमी को लगाइये उसको दो वर्ष काम

(श्री मानसिंह महार)
करने दीजिये। अगर इनएफिशियेन्ट हैं तो लगाया ही क्यों? इमर्जेन्सी के टाईम में हमारे ऊपर कमर तोड टैक्स लगा रहे हैं। कमर झुकी जा रही है इन टैक्सों के भार से, टैक्सों के बोझ से कमर दबी जा रही है और जब जनता रोज के ये तबादले देखती है तो बहुत दुख होता है। तबादलों पर कितना खर्चा होता है। मैंने अपनी इस एम. एल. ए. गिरी के दौरान में जयपुर में ये तीसरे कलेक्टर देख लिये हैं। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में चौमूं थाने में तीन सब-इन्स्पेक्टर देख लिये। यह सरकार की इमर्जेन्सी है? इन हालतों में, रोज अफसरों के तबादले होना, पक्षपात होना, रोज इन बातों को देखते हुए कोई यह कहे कि देश पर संकट है, सरकार सीरियस है तो मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

तबादले के बारे में निवेदन कर रहा था कि कन्स्ट्रक्टिव सुझाव लायें कि तबादलों में टी.ए. डी. ए. का बहुत पैसा खर्च होता है। मैं चाहता हूं कि तबादले के ऊपर नियन्त्रण रखा जाय। तबादले कम करें, कम तादाद में किये जांय। आप कहेंगे कि जयपुर का एक कलेक्टर सूडान चला गया, और दूसरा फाइनेन्स में आवश्यक था, और तीसरे को भी आप रेवेन्यू बोर्ड में भेज रहे हैं ऐसा आभास हो रहा है। आप ऐसे आदमी को भेजिये जो दो वर्ष जम कर काम करे। एक आदमी ने थोडे दिन काम किया, वाकफियत हासिल की और आपने उसका तबादला कर दिया। दूसरा आया, तीसरा आया और फिर तबादला। कैसे काम चले? अगर सरकार मेरे से बैठ कर परामर्श करे और राय ले और उचित समझे तो मैं ३ करोड की बचत एडमिनिस्ट्रेशन में करवा सकता हूं। यह मैं दावे के साथ कहता हूं। तीन करोड के टैक्स जो किसानों पर आपने लगाये हैं उनको माफ कर दीजिये और तीन करोड की बचत एडमिनिस्ट्रेटिवली करने के लिए, ऐसे तरीके से कि एडमिनिस्ट्रेशन एफिशियेन्ट हो, रेड टेपिज्म कम हो, मेरी बात मान लीजिये। यह विश्वास दिला दूं कि मंत्रियों और उप-मंत्रियों की कमी की बात नही होगी। उससे शायद आप चमक जायें आपकी कमी की बात कभी नहीं करूंगा, यह शर्त लिखवा लीजिये, बोन्ड लिखवा लीजिये।

एक माननीय सदस्य : बहुत समय हो गया।

श्री मानसिंह महार : अभी मेरी पार्टी का बहुत समय है।

श्री अध्यक्ष : दूसरे भी बोलने वाले हैं आपकी पार्टी के।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का नमूना ले लीजिये। मैं जानता हूं कि मेरी बात पब्लिसिटी के लिए जावेगी बाहर।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir. A Member cannot play to the gallaries. He is addressing the House.

मेरी बात जनता करेगी। पब्लिसिटी के लिए जावेगी। We are in the House. We should not care for the gallaries or anything.

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि अधिक प्राइमरी स्कूल मत खोलिए। लोग यह कहेंगे कि मानसिंह

(श्री मानसिंह महार)

महार कह रहा हूं कि प्राइमरी स्कूल मत खोलो। मैं खुद छुरी खा रहा हूं, दूसरों के छुरी नहीं लगा रहा हूं, राजस्थान के भले के लिए, भारतवर्ष के भले के लिये। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे इधर तो इतनी बाढ आ गयी है प्राइमरी स्कूलों की कि शिक्षा को बढोतरी देने के लिए पंचायतों के नेता स्कूल तो खोल देते हैं लेकिन स्कूलों में मास्टर बैठे रहते हैं और लडके होते हैं चार-पांच। मैं कहता हूं कि यह सरकारी धन का दुरुपयोग है इसको रोकिये। स्कूल वहां खोलिये जहां ४०-५० बच्चे पढते हों।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): बच्चे बढाने में सहयोग दीजिये।

श्री मानसिंह महार: जिस स्कूल में ४० बच्चे न हों तो मैं उस स्कूल को नहीं मानता कि यह प्रोडक्टिव है। ईमानदारी की पुकार होनी चाहिये। मास्टर फर्जी बना लेते हैं। वे लोग नहीं मानते हैं। आप मेरे साथ चलिये, पुराने राजाओं की तरह भेष बदल कर, हमारे मंत्रीजी तो काफी भेष बदल सकते हैं। उप मंत्रीजी ने काफी दौड-धूप की है जयपुर से बडे भारी कलंक को हटाने में, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उसे हटाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर भी मैं कहता हूं कि यह नहीं कि बजट में रख दिया कि २५० प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। आप पहले अनप्रोडक्टिव अनप्रोफिटेबल प्राइमरी स्कूल हैं उनको कम कीजिये। मैं फिर कहता हूं कि स्वतन्त्र पार्टी या कांग्रेस के हैं उनका लिहाज मत कीजिये। आप आंख मींच कर सम-दृष्टि से देखिये। कोई बुरा नहीं मानता। फिर पक्षपात नहीं चलेगा। बैराठ में ६ मील के अन्दर तीन हायर सैकन्डरी स्कूल खोल दिये। हालत यह है कि १०-१२ लडके पढते हैं। वहां पर आपने तीन हायर सैकन्डरी स्कूल खोल दिये। मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में एक भी नहीं। जवाब मिल गया कि सरकार हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं खोलेगी। जिन साथियों का पेट भरना था उनका भर गया, रोते रह गये तो हम रह गये। पूरी कांस्टीट्यूएन्सी में एक भी हायर सैकेन्डरी स्कूल नहीं है।

हम किसको कहें? कौन है हमारी सुनने वाला? फिर भी मैं दोहराता हूं और सरकार से कहता हूं कि आप लोगों का कॉपरेशन नहीं लेते। हम कहते हैं कि आप कॉपरेशन की बात तो करिये जो न्यायोचित बात कहें उस को तो मानिये। शिक्षा के लिये मेरा कहना है कि पहले जो गलत तरीके से प्राइमरी स्कूल्स खोले हैं उनमें से कई तो लोगों के घरों में खोल दिये हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं और मैं साबित करने के लिये तैयार हूं, लोगों की ढाणियों में एक नेता जो इन्फ्लूएन्शल है उन्होंने अपनी ढाणी में स्कूल खुलवाया है जहां सिर्फ दस बच्चे हैं। आप चल कर देख लीजिये। इस ओर ध्यान दिया जाय। हायर सेकन्डरी स्कूल्स जो ज्यादा नजदीक में खोल दिये गए हैं उनको थोडा इधर-उधर कर दीजिए। दस माइल्स के जो रेडियस का सवाल है उससे आप इधर-उधर शिफ्ट कीजिये जिससे शिक्षा का लाभ सब को मिल सकता है। यह मेरा कोन्क्रीट सुझाव है प्राइमरी और हायर सेकन्डरी स्कूल के लिये।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, हमें यह देखकर बडा दुख होता है और आपको

(श्री मानसिंह महार)
भी हुआ होगा कि एक तरफ कहा जाता है कि प्रॉडक्शन बढाओ, सरकार कहती है राजस्थान के पशुधन को बढावा दिया जाय। एक दिन, अध्यक्ष महोदय, मैं पशुधन के बजट को देखने लगा। उसको काटकर ऐसा कर दिया कि जहां पर पुराने दवाखाने वगैरह थे उनके लोगों को इस बजट से तनख्वाह भी मिलना मुश्किल होगा, नये दवाखानों के खोलने का तो सवाल ही नहीं। आप एग्रीकलचर को बढाने के लिये पशुधन को बढाने के लिये पैसा दीजिये वास्तव में अगर आपको तरक्की करनी है तो। अपना प्रॉडक्शन बढाना है तो इन महकमे की ओर तवज्जह देनी चाहिये। इसके साथ-साथ मैं मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा वे इन खर्चों पे कमी करने का विचार छोड कर उन टैक्सेज में कमी करदें जो टैक्स उन्होंने काश्तकारों पर लगाये हैं। आप चाहें कुछ भी कहिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि काश्तकारों के साथ अन्याय हुआ है यह उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड है इसलिये टैक्स प्रपोजल्स को रिकन्सीडर करना होगा। सदन के चाहे उधर बैठने वाले सदस्य हों या इधर बैठने वाले, सब इस बात को मानते हैं कि यह काश्तकारों के साथ अन्याय हुआ है। एक भी उधर बैठने वाला आपको समर्थन नहीं देगा। पार्टी व्हीप के कारण पार्टी के सच्चे सिपाही के नाते वे लोग आपका साथ दे दें किन्तु उनकी आत्मा तो कोसेगी उनको अपने कृत्य पर। फिर भी मैं हमारे वित्त मंत्री महोदय के दिमाग में यह भरना चाहता हूं जो मैंने सुझाव दिये हैं उससे ४ करोड रुपये की बचत हो सकती है। थोडा आप देख रहिये। एडमिनिस्ट्रेशन में बचत करके, काश्तकारों पर जो आपने टैक्स लगाये हैं उनको विदड्रा करिये।

आपने यहां पर सेल्स टैक्स दस परसेन्ट लगा दिया और बता दिया कि इससे इतनी आमदनी होगी। अध्यक्ष महोदय, पास ही दिल्ली में सेल्स टैक्स चार परसेन्ट और छः परसेन्ट है। लोग वहां से माल खरीदेंगे और यहां लाकर बेचेंगे। यह तो इन्टर स्टेट ट्रेड है इससे जो सेल्स टैक्स आपको मिलता था वह भी खत्म हो गया। जो टैक्सेशन की पोलिसी हमारी सरकार ने बनायी है उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह वर्तमान वित्त मंत्री के दिमाग की बात नहीं है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे ऐसे मामलों में जो डिप्टी मिनिस्टर हैं उनके उनसे मदद लें। वे इन कामों में माहिर हैं, उनकी राय लें। कल, अध्यक्ष महोदय, मुझे यह देखकर बडा दुख हुआ कि हमारे वित्त मंत्री महोदय अकेले नोट बना रहे थे। कोई डिप्टी मिनिस्टर वगैरह नहीं था। आप उनका कापरेशन लीजिये, उनकी राय लीजिये। बडे फरटाइल माइन्डेड हैं वे, टैक्सेज में भी कमी कर देंगे और आपको बहुत लाभ पहुंचायेंगे। आपने पहले अजमेर में गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स के लिये भूख हडताल की थी। अब किसान लोग आपके दरवाजे पर आकर भूख हडताल करेंगे। आपने जो शोहरत कमाई है वह खत्म हो जायगी। आप जनता के बडे हितैषी माने जाते हैं ऐसा हमने अजमेर में सुना था लेकिन हमें मालूम नहीं था आप हमें इस प्रकार चूसेंगे। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि आपने इस प्रकार का बजट पेश करके राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बदनाम किया है। कांग्रेस के बेन्चेज पर बैठने वाले मेरे मित्र ने एक बात कही थी कि

(श्री मानसिंह महार)

आप कहीं कांग्रेस के खिलाफ कान्स्प्रेसी तो नहीं कर रहे हैं। आप तो एक शहर से आये हैं आपको किसानों के वोट नहीं चाहिये लेकिन जो लोग किसानों के वोट से आये हैं उनके साथ तो आप उनकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में दूर करिये। और इस होली के टाइम में पधारते तो आपकी ऐसी दुर्गति होती जो आप हमेशा याद रखते। खास तौर से आप मारवाड के गांवों में जाते, नागौर पधारे होते तो आपको पता चलता कि इन टेक्सेज के कारण वहां के किसानों के क्या हाल है, वे कितने बिगडे हुए हैं। अजमेर से निर्वाचित होने के कारण आप वित्त मंत्री नहीं बनें, आपके साथ जो ८८ चुन कर आये हैं उन पर भी ध्यान दीजिये—खास तौर से नसीराबाद से आने वाले सदस्य की तरफ तो अवश्य गौर करिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: (नसीराबाद): मैं किसी की रहम नहीं चाहता।

श्री मानसिंह महार : हमारे लिये तो आप जितने ज्यादा टैक्स लगायें अच्छा है, क्योंकि आपके पहले के पांच वर्षों के कारनामों ने आपको ८८ की संख्या में ला दिया और इसी रफ्तार से चलते रहे; तो आने वाले चुनावों में यह संख्या कहीं ४४ ही न रह जाय, मैं हमारे मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री महोदय को चेलेन्ज करता हूं कि आप इन टैक्सेज के मामले पर इस्तीफा दे दीजिये और राजस्थान में नये चुनाव कराइये। हम आपका मुकाबला करेंगे और मेजोरिटी लाकर दिखायेंगे। आज आपके इन टैक्सेज के कारण जनता में इतना असन्तोष है। यह तो भारत है जहां पर कुर्सी छोडना कोई नहीं चाहता है। इंगलैन्ड जैसे देशों में स्लेप पर इलेक्शन होते हैं। जरा सी बात हुई कि मिनिस्टरों ने रिजाइन कर दिया। यहां तो यह पक्का है कि चार-चार बार मंत्री रिजाइन करते हैं फिर भी कहीं बैलेन्स बिगड न जाय इसलिये उनका इस्तीफा भी मन्जूर नहीं होता। मंत्री लोग इसमें अपना गौरव समझते हैं। यह बातें मैं बडे साफ दिमाग से कह रहा हूं। ट्रेजरी बेन्चेज से निवेदन करूंगा आप मेरे इन सुझावों पर गौर करें और बजट में ऐसा सुधार करें जिससे काश्तकारों पर करों का भार ज्यादा न पडे।

अगर आपको टैक्स लगाना ही है तो आप हाउस को कॉन्फीडेन्स में लीजिये और फिर हम बतायेंगे किस प्रकार के टैक्सेज लगने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अब समय बहुत हो गया है।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, अब मैं टैक्स के बारे में सुझाव दूं। मेरा सबसे बडा सुझाव यह है कि सरकार वकीलों पर टैक्स लगाये। इस समय जो वकील काश्तकारों को चूसते हैं उन पर आप टैक्स लगाइये और इस तरह से दस-बीस लाख पैदा कीजिये। यह आमदनी का अच्छा जरिया है। हमारी तरफ बैठने वाले वकील आपको इसमें पूर्ण सहयोग देंगे। मेरे वकील मित्र उनको पकडायेंगे जो टैक्स इवेड करते हैं। इससे आपकी तरफ चीं चीं भी भी हो सकती है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि आप बिजली कुएं कुएं पर दीजिये। मुझे दुःख हुआ, सवालों के समय . . . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बिजली तो खम्भे-खम्भे पर चाहिये।

श्री मानसिंह महार: यही तो हमारे और आपके दृष्टिकोण में फर्क है। हमें खम्भे-

(श्री मानसिंह महार)
खम्मे पर बिजली नहीं चाहिये हम तो कुएं कुएं पर बिजली चाहते हैं। लेकिन हमारी सरकार की जो नीति है उसके अनुसार चौमू में बिजली लगा दी, कस्बे के अन्दर लगा दी, आमेर कस्बे के अन्दर बिजली लगा दी। क्या इससे आपको कुछ रिटर्न मिला है ? लेकिन आमेर कस्बे में ५०० कुएं हैं, उन पांच सौ कुओं में बिजली दीजिये तो आपको पता चल जायगा कि उससे क्या रिटर्न मिलता है। एक तो यूनिट कन्जूम होगी उसका पैसा मिलेगा दूसरे कुओं से ज्यादा भूमि की सिंचाई होगी, उससे ज्यादा अनाज पैदा होगा। आज जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे चौगुना प्रोडक्शन होगा। शहरों की अपेक्षा आप कुओं में बिजली दीजिये और देखिये कि राजस्थान का यह भाग लहलहाता है या नहीं।

(१. म. प.)

हमारे यहां जयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक भी मेजर इरिगेशन वर्क नहीं है। इसके लिये सरकार को सोचना होगा। मैं बिजली मन्त्री से और मुख्य मंत्री से अपील करता हूं कि जयपुर जिले में आप विशेष रकम दीजिये। यहां पर कुएं बहुत हैं। छोटी छोटी जमीनें हैं किसानों के पास। उनमें बिजली दीजिये। मैं कहता हूं आपको गंगानगर ने सोना दिया, क्या बड़ी बात हो गई ? गंगानगर ग्रेनरी आफ राजस्थान है। महाराजा गंगासिहजी ने लाखों रुपया लगाकर नहर बना दी इसलिये आज वहां का आदमी साधन सम्पन्न है और सोना दे सकता है। हमको आप बिजली दीजिये दो वर्ष के अन्दर मैं आपको दावे से कहता हूं कि बिजली देने के दो वर्ष के अन्दर हमसे आप पैसा मांगिये। अगर गंगानगर और हनुमानगढ से अधिक पैसा नहीं दें तो हमको कहिये। हम इतना प्रोडक्शन बढ़ायेंगे कि हर प्रकार से हम उनको मात देंगे। मगर हमको बिजली दीजिये। आज बिजली दे रहे हैं पर कस्बों को दे रहे हैं। चौमू में बिजली चली गई। पर काश्तकार को नहीं मिलेगी। आप जो भेद भाव बरतते हैं, मैं वह बता रहा हूं। जैसा नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हम खम्भे-खम्भे पर बिजली लगा देंगे। हमें तो इसकी जरूरत नहीं। हम तो अन्धेरे में फिर लेंगे। हमें बिजली की जरूरत नहीं। हमारे गांवों में इतने चोर डाकू नहीं हैं जिनसे बचने के लिये हमें गली कूंचों में बिजली चाहिये, अजमेर पर खम्भे-खम्भे पर बिजली चाहिये। हमारा सत्यप्रिय इलाका है। पर हमको मेहरबानी करके बिजली मंत्री कोई अच्छी सी योजना बनाकर दें। जिस जिले में मेजर-माइनर इरिगेशन का कोई वर्क नहीं है उस जिले में अपने बिजली के बजट में से आप बिजली दीजिये। आप देखिये हम आपको क्या करके दिखाते हैं। गंगानगर के लोग कहते हैं कि हमने मिट्टी में से सोना पैदा किया, हम जयपुर वाले मिट्टी में हीरा पैदा करके दिखा देंगे आपको। आप हमें बिजली देकर देखिये। आप जिस तरह चाहें राज्य करें, पर हमें बिजली दीजियेगा। हमें तो खम्भे-खम्भे पर बिजली नहीं चाहिये, हमें कुएं-कुएं पर बिजली चाहिये। खम्भे-खम्भे पर बिजली हमारे नसीराबाद वाले माननीय सदस्य को और अजमेर वालों को मुबारक रहे।

ये चन्द शब्द कहने के बाद मैं क्योंकि मुख्य मन्त्री पधार गये हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी आमेर में मुख्य मन्त्रीजी बड़ा अन्याय हो रहा है। इस सोशलिस्टिक पैटर्न की सरकार के राज्य में मोनोपोलिस्टिक टेन्डेन्सी बढ रही है इसलिये मेरी आप से प्रार्थना है कि यह हाथियों की मोनो-

(श्री मानसिंह महार)

पोली आपकी सरकार ने आमेर में कर रखी है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये कागज हैं जिनको कि आपकी सरकार रिफ्यूज नहीं कर सकती। उसके लिये आप हमारे अध्यक्षजी के चेयरमेनशिप में एक कमेटी बनाएं यह मैं आपको सुझाव देता हूं। यह घोटाला चार-पांच वर्ष से हुआ है और इसमें २॥ तीन लाख का घोटाला है। इसको जनता के सामने लाइये। मैं मानता हूं आप बड़े ऊंचे व्यक्ति हैं, त्यागी हैं, आपका इसमें हाथ नहीं होगा। मैं यह नहीं कहता कि आपका हाथ है, पर मैं आमेर जाऊं और लोग आपकी तरफ उंगली उठावें, यह मैं बर्दास्त नहीं कर सकता अपने मुख्य मन्त्री के लिये। इसलिये आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसकी पूरी जांच करावेंगे। इस कागज को मैं सदन की मेज पर रखते हुए अपने वित्त मन्त्रीजी से आखिरी बार कहूंगा कि आप अगर राजस्थान में अपना मुंह ऊंचा रखना चाहते हैं तो आपके जो ये बेढंगे टैक्स हैं इनको आप खत्म करिये वरना मैं आपको यह दावे के साथ कहता हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब एक अप्रेल के बाद आपको इस सदन से नीचे उतरना मुश्किल हो जावेगा। इन चन्द शब्दों की चेतावनी के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर गौर करें।

वित्त मन्त्री जी भी भोले हैं। गलती से, ये टैक्स नीचे वालों के कहने से लगा दिये हैं उन्होंने। अब हमारे इतना कहने के बाद उनके दिमाग में बैठी होगी कि उन से गलती हो गई। तो जो आदमी अपनी गलती महसूस कर लेता है उसको देवता माना जाता है। हम सब आपको देवता मानेंगे, अगर आप इन सब टैक्सों को वापिस ले लेंगे तो।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल, के भाषण पर जिस समय बहस हो रही थी और जिन परिस्थितियों में इस सदन की इस बार बैठक हो रही है उस पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए हमने यह आशा की थी कि राजस्थान सरकार अपना बजट पेश करते हुए जो अभी तक नीति बरतती आई है उस नीति में कुछ बुनियादि परिवर्तन करेगी। हम यह आशा करते थे कि इन पिछले तीन चार महीनों में विशेष तौर पर संकटकाल की स्थिति में राजस्थान की आम जनता ने और विशेष तौर पर किसान-मजदूरों ने जिस प्रकार की कुरबानी की भावना, इस संकटकाल में हर प्रकार से देश रक्षा के कामों में सहयोग देने की भावना व्यक्त की है और उसके मुकाबले में जिस प्रकार निहित स्वार्थों वाले तबकों की ओर से अपने स्वार्थों की रक्षा करने का ही दृष्टिकोण अपनाया गया है इससे हम यह आशा करते थे कि राजस्थान सरकार कुछ रीअलिस्टिक बनेगी, अपनी परम्परा गत नीतियों से नाता तोडेगी, और एक इस प्रकार का बजट प्रस्तुत करेगी जो कि वास्तव में एक नई आशा का संकेत करे, नई दिशा का संकेत करे, जो कि वास्तव में राजस्थान की जनता को यह विश्वास दिलावें कि चाहे राजस्थान सरकार के अब तक कुछ भी ओमीशन और कमीशन्स रहे हों पर अब वह नयी इकॉनॉमिक पालिसी, एक नई टैक्सेशन की पालिसी निर्धारित करने जा रही है जिसके अनुसार वास्तव में राजस्थान की जनता इस संकट काल के दौर में देश की रक्षा-साधनों को मजबूत बनाते हुए अपने प्रान्त के विकास की ओर आगे बढ़ेगी। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो यह बजट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
हमारे सामने पेश किया गया है इसे देखने से हमें बहुत निराशा हुई है।

केवल इतना ही नहीं कि राजस्थान सरकार ने अपनी पुरानी नीतियों को ही इस बजट के अन्दर कायम रखा हो, बल्कि मैं यह कहूंगा कि सरकार ने रिओरियन्टेशन किया है लेकिन वह रिओरियन्टेशन एक प्रतिगामी दिशा में किया है। राजस्थान सरकार आज किस प्रकार की नीतियों को अपना रही है यह बजट उस दिशा की ओर संकेत करता है, जिसको कि मैं बहुत खतरनाक मानता हूं, राजस्थान की जनता के लिये उसके विकास के लिये बहुत हानिकारक मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पहले भी और इस समय भी यह आवाजें उठाई गई यह मत व्यक्त किया गया है विशेष तौर पर स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ की ओर से कि राजस्थान सरकार बहुत महत्वाकांक्षी प्लान्स बना रही है और इसलिये हमारे साधन, इन प्लान्स के अन्दर जो खर्चा होने वाला है, उसको मीट नहीं कर सकते और इसलिये उनकी हर तरीके से यह दलील रहती है कि या तो इस प्लान को बिल्कुल छोडो नहीं तो किसी तरह से प्लान्स को कम कर दिया जावे।

मैं समझता हूं कि चाहे राजस्थान सरकार ने उसूलन इस बात को स्वीकार न किया हो लेकिन जो बजट हमारे सामने पेश किया है उससे मैं समझता हूं कि अमली तौर पर राजस्थान सरकार ने स्वतंत्र पार्टी की इस नीति को स्वीकार कर लिया है और शायद इसीलिए हमारे वित्त मन्त्री को स्वतं‍त्र पार्टी के एक्सपीरियेन्स्ड सलाहकार को भी अपनी सर्विस में रखना पडा कि वह सही दृष्टिकोण उनका रखें जो पार्टी के वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके हितों की सही तौर से रक्षा हो सके। इस दृष्टिकोण को प्रेक्टिकल रूप भी उन्हों ने दिया है। अध्यक्ष महोदय, वह कौन सी दिशा है जिसको मैंने खतरनाक बताया, वह कौन सी दिशा है जिसको हम समझते हैं कि राजस्थान की जनता के लिये, बहुत नुकसानदायक होगी। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में जो री-ओरियन्टेशन है इस बजट में जिसके लिए हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने अपने आपको कांग्रेचुलेट किया है, संकेत इस बात का है कि हमारे प्लान्स बहुत बडे हैं, हम इतने साधन जुटा नहीं सकते इसलिए प्लान को कट करो प्लान को ट्रंकेटेड करो और दूसरी तरफ साधन जुटाने के लिये प्रोग्रेसिव रास्ता नहीं नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढाने का रास्ता नहीं, नीहित स्वार्थ के कैपीटल का एक्सप्रोप्रियेशन करने का रास्ता नहीं इसलिए आम जनता को भारी टैक्सों से लादने का रास्ता उन्होंने अपनाया है।

अध्यक्ष महोदय, बजट जिस आधार को लेकर चलता है, जिस बुनियाद को मानकर वित्त मन्त्री चल रहे हैं वह यह है कि चाहे पीछे हमने कितने ही ओवरड्राफ्ट लिए हों, चाहे वित्त मन्त्री जी के ख्याल से हमने कितनी ही फिजूलखर्ची की हो, चाहे हमने एम्बीशश प्लान बनाये हों, लेकिन आइन्दा इस वर्ष में भी और आने वाले समय में जो पर्सपेक्टिव वित्त मन्त्री महोदय रख रहे हैं वह यह है कि आगे आने वाले समय में हम अपने तमाम साधनों में अपने प्लान को छोटा करके कुछ बचायेंगे कुछ टक्सेज के जरिये कुछ रिसोर्सेस इकट्ठा करेंगे और पीछे १९५५-५६ से जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हर साल बजट में डेफिसिट होता जाता था जिसकी वजह से हमारा ओवरड्राफ्ट बढता जाता था उस रेकरिंग डेफिसिट को पूरा करेंगे और इसके अलावा जो पिछले डेफिसिट एकुमुलेट हो गये हैं उसको भी इस दौरान में पेमेन्ट कर देंगे। इस पर्सपेक्टिव के साथ हमारे वित्त मन्त्री महोदय चल रहे हैं और इसका मतलब यह है कि हमारी सरकार यह मानकर चल रही है कि हमारे प्रान्त की अर्थ-व्यवस्था इस स्थिति में पहुंच गयी जिसको हम सेल्फ जनरेटिंग इकानामी कहें यानि जिसमें इतनी क्षमता हो गयी कि वह अपने आप में इतनी वैल्यू पैदा कर देगी कि आगे के जो रेकरिंग एक्सपेन्सेस हैं उनको भी मीट कर लेंगे और आगे आने वाले डवलपमेन्ट के काम हैं उनको भी अपने ही रिसोर्सेस के जरिये मीट कर लेंगे, इस दृष्टिकोण से यह बजट बनाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान सरकार की यह समझ सही नहीं है और यह बात तो खुद राजस्थान सरकार ने भी नहीं मानी अन्य प्रसंगों में कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें हम कोई सेल्फ जनरेटिंग इकानामी क्रियेट कर पाये हैं लेकिन फिर भी एक एचीवमेन्ट के बारे में कुछ एग्ज़ेगरेटेड जुबेलीन जरूर मालूम पडता है जो कि वास्तविक को देखते हुए सही नहीं है। कल जयपुर से आने वाले मेरे माननीय मित्र ने कुछ आंकडे सदन के सामने रखे थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के, इन्डस्ट्रियल प्राडक्शन के जिसमें इस बात को जाहिर किया था कि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन सिवाय सीमेन्ट के सब चीजों में इस दौर में गिरा है। जहां तक एग्रीकल्चर प्राडक्शन का सवाल है उसको सरकार क्लेम करती है कि हमने ४० परसेन्ट इसमें इन्क्रीज कर लिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में इस समझ के कारण एक भारी गलत फहमी आम जनता में और इन्टलेक्चुअल के माइण्ड में पैदा की जा रही है। यह बहम पैदा किया जा रहा है कि एग्रीकल्चरिस्ट बहुत मालामाल हो गए, यह ख्याल किया जाता है कि उनकी अर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ गयी है और यह आंकडे राजस्थान सरकार की तरफ से पेश किये जाते हैं उनसे इस बात को इस दलील को मनवाया जाता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि राजस्थान सरकार के आंकडों को ही सही मान लें तो इन आंकडों के अनुसार जो राजस्थान सरकार ने इन्डेक्स नम्बर निकाला है आल कमोडिटीज का, वह १४०.७६ है १९५२-५३ को बेस ईयर मानकर। १९५२-५३ से और १९५५-५६ तक ४ वर्ष की पैदावार को बेस ईयर मानकर उससे १९६१-६२ में ४० परसेन्ट प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का बढा है। लेकिन अगर आप ४ साल का एवरेज लें १९५७-५८ ५८-५९, ६०-६१ और ६१-६२ इन सबका अगर आप एवरेज लें तो यह एवरेज करीब १२७ आता है क्योंकि यह १९६१-६२ के जो आंकडे हैं मैं कह नहीं सकता कि यह कहां तक आॅथेन्टिक हैं लेकिन इनको पूरा आॅथेन्टिक मानते हुए भी आपने एवरेज ४ साल का लिया है, जिस तरह राजस्थान का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अनसर्टेन है इस बिना पर भी आपके प्रोडक्शन के लिए ४ साल का एवरेज लें तो १२७ आपके प्रोडक्शन का इन्डेक्स नम्बर आता है। अगर आप होलसेल प्राईसेज के इन्डेक्स नम्बर को देखें तो १९५२-५३ की प्राईसेज के मुकाबिले में २५ परसेन्ट बढ़ गया है। इसका मतलब यह है कि जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी मालूम पड़ रही है यह रियल क्वान्टम में बढ़ोतरी नहीं, यह रियल वैल्यू में बढ़ोतरी नहीं है बल्कि कीमतों में बढ़ोतरी का नतीजा है। प्रोडक्शन में १२७ और कीमत में १२५ सिर्फ २ परसेन्ट का फर्क है। इस तरीके से जो यह समझ पैदा की जाती है कि हमने इस दौरान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढा लिया, वह वास्तव में आपके खुद के आंकडों के अनुसार भी सही नहीं है। अगर, अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को देखें कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन का पर एकड़ ईल्ड कितना है तो उससें आपको और भी ताज्जुब की बात मिलेगी और मैं आपके सामने सरकारी आंकड़े प्रस्तुत करता हूं जिसमें अगर आप बाजरे की प्रोडक्शन को देखें तो जहां १९५९-६० में २२७ पौंड पर एकड़ थी। वह ६०-६१ में १४४ रह गयी। ६१-६२ में २१८ है। ५९-६० के मुकाबले में ९ पोइन्ट कम है। यदि ज्वार का प्रोडक्शन देखें तो यह ५८-५९ में २७६ था, ५९-६० में २७१, ६०-६१ में २५५ और ६१-६२ में २२२ रह गया। हर सूरत में इसकी पैदावार गिरती जा रही है। इसी प्रकार यदि व्हीट को देखें तो ५६-५७ में ८८० पौंड था, वह ५७-५८ में ७०२ रह गया और अब भी ८७४ है। यह ८८० से अब भी कम है पर एकड़। इसी तरह यदि जौ का प्रोडक्शन देखें तो ५६-५७ में १०९९ था, वह ६१-६२ में सिर्फ १०८० है। और राइस का प्रोडक्शन देखें तो ५५-५६ में ११४० था. बीच में ८३८ हुआ फिर ५८८ हुआ और अन्त में ११९८ बताया गया है। यदि पल्सेज के प्रोडक्शन को देखें तो इसकी भी यही तस्वीर है। चना ५६-५७ में ६२८ था, वह ६१-६२ में ५०० रह गया। इसी प्रकार दूसरी रबी पल्सेज हैं वे ५६-५७ में ५२७ थीं और अब ५३१ रह गई।

तो, अध्यक्ष महोदय, यह क्या शो करता है? इन आंकडों से हमें यह बात जाहिर होती है कि हमारी ईल्ड पर एकड नहीं बढ़ी। हमारी उस जमीन में पैदावार नहीं बढ़ी। यदि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर में कुछ ईल्ड बढ़ी है तो उस जमीन की पैदावार बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ी, किसानों की पैदावार की वजह से नहीं बढ़ी बल्कि यह तो आपने जो बंजर जमीन वगैरह को तोड़ कर ज्यादा काश्त कराई है उसका नतीजा है। वैसे इकॉनॉमिक तरीके से राजस्थान में कॉमोडिटी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। किसानों की इतनी ज्यादा पैदावार बढ़ी नहीं है कि वे बेचने के लिए उसे मार्केट में ला सकें। यदि ईल्ड पर-एकड़ बढ़ती तो हम स्वीकार करते कि किसानों की पैदावार बढ़ रही है, उसकी होल्डिंग है उसमें पैदावार बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय ये आंकडे इस बात को जाहिर करते हैं कि यह बात सही नहीं है। तो फिर गवर्नमेन्ट ने पर-केपिटा जो इन्कम निकाली. राजस्थान की टोटल इन्कम की बढ़ोतरी निकाली और बताया कि इतनी एन्युअल इन्कम है राजस्थान की और उसके अनुसार हमारी पर-केपिटा इन्कम इतनी बढ़ गई इसमें क्या फालेसी है? इसमें फालेसी यह है कि आप जिसे बढ़ी हुई इन्कम मानते हैं वह रियली नहीं बढ़ी है। वह तो जो २५ परसेन्ट होल सेल प्राइसेज में इन्क्रीज हुई है उसको आप इसमें लगायें तो आप देखेंगे कि जो इन्क्रीज बताई है वह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करेन्ट प्राइस के मुकाबले में कम है । पर-केपिटा इन्क्रीज २३३ से २४६ करेन्ट प्राइस पर है और करेन्ट ३२५ पर पहुंच गई । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, यदि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो हमारे स्टेट की टोटल इन्कम कैसे बढ़ी है ? पर-केपिटा में इन्क्रीज कैसे आई है ? मैं समझता हूं राजस्थान सरकार का स्टेटिस्टिक्स रखने का तरीका है वह गलत है और गलत आंकड़े दे रहे हैं क्योंकि जो दूसरी सर्विसेज है, गवर्नमेन्ट सर्विस जिन लोगों को मिल गई है, या जिनको नौकरी मिल गई उनको महंगाई आदि की वजह से ज्यादा इन्कम हुई । जो सर्विसेज है उनकी इन्कम ९ करोड़ या कितनी लगादी । इसी प्रकार जो माइन्स वगैरह में काम करते है उनकी इन्कम निकाली और जो इन्फलेटेड प्राइस है उससे इन्कम एग्जिस्टिंग के हिसाब से लगादी । इस तरह से इन्कम बढ़ने की वजह से आप की पर-केपिटा अधिक इन्कम आती है । जितना आप क्लेम करते हैं वह भी कोई बहुत बड़ तारीफ की बात नहीं है । लेकिन वास्तव में आप के आंकडों पर पहुंचे सही इकॉनॉमिक दृष्टि से तो पर-केपिटा खाली दिखावटी है, वास्तविक नहीं है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस बुनियाद को आप हाईपोथेटिकल मान कर, जिस प्रकार राज्य की अर्थ व्यवस्था को हाईपोथेटिकल मानकर अपनी अर्थ पॉलिसी बनाते हैं, टेक्सेशन पॉलिसी रखते है उसमें यदि आपका हाई-पोथेसिस गलत है तो आप लाज़मी तौर पर गलत नतीजों पर पहुंचेंगे और उसका नतीजा राजस्थान की जनता के लिये भयंकर होगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था इतनी पिछडी हुई है तो यह बात कह सकते हैं कि हमको कोई बडा प्लान नहीं बनाना चाहिये । यह बात कह सकते हैं कि हमारे पास जितना प्लान है उसकी जितनी रिसोर्सेज हैं, जिस तरह के हमारे साधन हैं मौजूदा, उसके आधार पर हम चल सकें यह बात सही नहीं है । खास तौर से इस तरीके से इस बात की बहुत दलील दी जाती है प्लान्स बडे बनाने के बारे में और आप इस बात को अमली तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं इसका नतीजा यह होगा कि हमारे मौजूदा रिसोर्सेज राजस्थान में जो इतने पिछडे हुए हैं, दूसरे देशों की तो बात छोड़ दीजिये, हम हिन्दुस्तान के आंकडे लेने लगें तो उनके मकाबले में भी जितने पिछडे हुए हैं यदि हमको वह गेप पूरा करना है जिसका आपने टारगेट रखा थर्ड फाइव ईयर प्लान में, वह पूरा करना है तो इस प्रकार की इकॉनॉमी के लिये आपको नॉन कंजरवेटिव तरीके से सोचना पडेगा । वह जो पुराना तरीका था, पुराने तरीके से सोचने की बात थी-देख लो कितना लगान से आया और उसके मुताबिक खर्च कर दो केवल उससे ही काम नहीं चलेगा । यह पुराना तरीका चला आया है आपने विरासत में लिया है उसमें थोडा हेर फेर-करके एडॉप्ट करते जा रहे हैं । लेकिन यदि राजस्थान की जनता की वास्तव में पर-केपिटा इन्कम बढानी है, उनका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढाना है हमको राजस्थान की टोटल इन्कम में इन्क्रीज करनी है तो हम बगैर प्लानिंग के नहीं कर सकते प्लान्स में इतना इन्वेस्टमेन्ट किये बगैर कि जिससे १३।। रु० का हमारे और आल इंडिया के बीच फर्क है पर-केपिटा इन्कम में, वह पूरा हो जाय । यह हम तभी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर सकते हैं जब हम कुछ ज्यादा इन्वेस्ट-मेन्ट करें, ज्यादा बडा प्लान बनावें ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पहले प्लान के मुकाबले में दूसरा प्लान बडा था और यह पहले प्लान का नतीजा है तो तीसरा प्लान उससे भी बडा होना चाहिये क्योंकि पिछले प्लान्स के कुछ कमिटमेन्ट्स केरी ग्रोवर करने पडते हैं और कुछ रेकरिंग एक्सपेंसेज बढ जाने से लाजमी तौर से खर्चा बढ जाता है । यदि हमको वास्तव में डेवलपमेंन्ट करने की तरफ चलना है तो हमारा थर्ड प्लान बडा होना चाहिये । लेकिन हम किस स्थिति में पहुंच गये हैं ? इस साल हमने केवल ३४.५ करोड रुपये हमने प्रोवाइड किये हैं जब कि हमारा ओरिजिनल थर्ड प्लान २३६ करोड का था । ओरिजिनली राजस्थान सरकार ने यह माना था कि कुल ५५० करोड का इन्वेस्ट-मेन्ट करना चाहिये वह नहीं कर सके । फिर २३६ करोड का माना । फिर आपने पिछले इकानामिक कट में घटा कर २०८ करोड का कोर और नॉन कोर में परिवर्तन करके दूसरे रूप में उसको काट दिया । और आज क्या हालत है, उसकी भी क्या हालत है २०८ करोड की आपने पहले साल में कुल ३४ करोड खर्च किये इस प्लान पर दूसरे साल में कुल ३५ करोड खर्च किए अब कह रहे हैं कि इस साल के लिये प्रोवाइड कर रहे हैं साढे चौतीस करोड रुपये । इसका मतलब यह हुआ कि पिछले तीन वर्षों में कुल सौ करोड रुपये खर्च करे हैं । फिर जिस तरह की योजना है, जिस तरह से पिछली दफा जिसको हमारे वित्त मंत्री ने फिजल खर्चियां और जस्ट एक्स्ट्रावेगेन्स कहा था, उसको भी आपको प्लीड करना है तो लाजिमी तौर पर १०८ करोड रुपये इन दो सालों में आप पूरे खर्च नहीं कर सकते और इस प्रकार से इस ट्रंकेटेड प्लान को भी आप पूरा नहीं कर सकते इसका मतलब यह हुआ, अध्यक्ष महोदय, जिसका मैंने जिक्र किया इस बजट में एक खतरनाक संकेत मिल रहा है और वह यह है कि प्लानिंग के उसूल से आप हटते जा रहे हैं, आप जो कमिटमेन्ट करते थे राजस्थान का विकास करने का, वह चाहे क्लास इन्ट्रेस्ट को देख कर करते थे, चाहे आप पूंजीवाद के तरीके से विकास करने का रास्ता अपना रहे थे लेकिन जो इस रास्ते को अपनाने का लाजिकल कन्क्लूजन होता है, उस कन्क्लूजन पर आप पहुंच रहे हैं और जिस तरह बूर्जुआ प्लानिंग पालिसी में एक क्राइसेस क्रियेट कर देता है, खडी कर देता है, उसी तरह राजस्थान सरकार अपनी पालिसी के क्राइसेज के चौराहे पर आकर खडा है और हमारे वित्त मंत्री और मैं तो कहूं कि सारी केबिनेट ने हमारे विरोधी दल के नेता, स्वतंत्र पार्टी से प्रेरणा लेकर और जो कुछ समझ में आयी उनकी बात जो पिछली दफा उन्होंने कही, इस बार भी कही और अब भी कही—उससे कुछ प्रेरणा लेकर अब अपना रास्ता चुन लिया मालूम पडता है । वह रास्ता यह चुन लिया मालूम पडता है कि पहले कुछ डगमगा रहे थे पैर कि प्लानिंग करेंगे, विकास करेंगे और टैक्स इतने नही लगायेंगे जिससे कि जनता भडक उठे लेकिन अब कुछ बोल्ड फाइनेन्स मिनिस्टर आये मालूम पडते हैं और वे कहते हैं-तुम डरते हो । चलो, मैं आगे चलता हूं । आओ मेरे पीछे । तुमसे टैक्स नहीं लगाया गया, तुमसे रिसोर्सेज इकट्ठे नहीं किये गये । मैं बताता हूं रास्ता । तो, अध्यक्ष महोदय, आप विकास करना चाहते हैं—इससे हम सहमत हैं । हम चाहते हैं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि इससे अधिक आप विकास करें। विकास के लिए आप रिसोर्सेज चाहते हैं-इससे हम सहमत हैं। हम मानते हैं कि रिसोर्सेज होने चाहियें जिससे कि विकास हो सके। लेकिन हमारे और आपके रास्ते में यह बुनियादी मतभेद आकर खड़ा होता है, जो कि हर पूंजीवादी प्लानिंग से होता है कि आप रिसोर्सेज कहां से लाने की कोशिश करते हैं। उनसे, जो अपना गुनाह कबूल करते हैं कि पच्चीस वर्ष पहले इस प्रकार के थे? उनसे लेना चाहते हैं, जो बार बार यह आश्वासन देते हैं कि हम आपको हटाना नहीं चाहते, लेकिन जो दूसरे सेक्रेटरी हैं, जो नौकर हैं, इन्हें नौकरी से हटाना चाहते हैं? हम समझते ह, यह आपका अनरिटिन एग्रीमेन्ट है--तू कहे न मेरी, मैं कहूं न तेरी। हम तुम्हें हटाने की बात नहीं चाहते, तुम हमारा कम्पेन्सेशन कम करने की बात मत करो। हमें देने की बात है, वह देते रहो, हम तुम्हारी कहते रहेंगे। यह तरीका आप लोगो ने अपनाया है। लेकिन मैं समझता हूं, जनता से यह बातें छिपी नहीं रहेंगी, वह जनता के सामने साफ जाहिर है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि वित्त मंत्री ने इस बजट के द्वारा अपनी नीतियों का साफ संकेत उस चौराहे पर खड़े होकर दिया है और एक रास्ता पकड़ने का इस बजट से सोचा है और जो रास्ता आपने अपनाया है वह है निहित स्वार्थों की रक्षा करने का। वह रास्ता अपनाया है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली प्लानिंग और विकास की बात को कम करते जाने का जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने की बात कही थी। आपने अब सोचा कि अब इस मंजिल पर पहुंच गये कि या तो निहित स्वार्थों को काटना पड़ेगा नहीं तो प्लानिंग को छोड़ना पड़ेगा। और क्योंकि आप एक दम नहीं कह सकते कि प्लानिंग का तरीका छोड़ा इसलिए जिस तरह सीढ़ियों पर आप थोड़ा थोड़ा करके चढ़े थे, उसी तरह अब आहिस्ता आहिस्ता उतर रहे हैं, जैसा कि विरोधी दल, स्वतन्त्र पार्टी के नेता कहते हैं-इस बात को कबूल करने जा रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति इस बजट के द्वारा पेश कररहे हैं।......

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद): गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूं कि राजस्थान की जनता के सामने और यह राजस्थान सरकार, जो जनता का बहुमत लेकर आई है, उस राजस्थान सरकार का, जिन डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स की इस बजट स्पीच में दुहाई दी गई, उसके दृष्टिकोण से क्या राजस्थान की सरकार के सामने दूसरा रास्ता नहीं है कि वह बराबर राजस्थान के विकास के खर्च को बढ़ाते हुए जारी रख सके और इस प्रकार के साधन भी जुटा सके जो इसको मीट कर सके। उसके लिए भी बोल्डनेस की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज्यादा बोल्डनेस की जरूरत है, बनिस्बत इसके कि जो हमारे वित्त मंत्री ने दिखाई है। और वह इस बजट से फाइनेन्स मिनिस्टर नहीं दिखा सके जो कि उस विचार-धारा के अन्दर विश्वास करते हैं और जो कि सोशलिस्टिक पैटर्न के लिए अलाइन है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता के सामने कोई निराशा की बात नहीं है, राजस्थान सरकार के सामने निराशा की बात नहीं है। अगर राजस्थान सरकार चाहे, और बोल्ड पालिसीज बनाना चाहे तो कन्जरवेटिज्म को छोड़े। लेकिन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

राजस्थान की जनता के प्रति जो आपने जिम्मेदारी सम्भाली है और उसको पूरा करने के दृष्टिकोण से काम सम्भाला है तो आपको कन्जरवेटिज्म को छोड कर नया रास्ता अपनाना पडेगा । दुनिया के इतिहास में यह बात लिखी है कि अगर सोशलिज्म के लिए, विकास के लिए, प्लानिंग के लिए काम करना चाहते हैं और उसके लिए इन्वेस्टमेन्ट ढूंढना चाहते हैं तो या तो आपको वेस्टेड इन्ट्रेस्ट को एक्सप्रोप्रियेट करना पडेगा, या जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हैं, उनसे आपको केपिटल लेना पडेगा जहां पर केपिटल हैं और कुछ आप बोरोइंग के ऊपर भी निर्भर कर सकते हैं लेकिन टैक्सों के ऊपर चल कर आप प्लानिंग नहीं कर सकते क्योंकि जनता की टैक्स पे करने की एक सीमा है, जो उस बर्डन को सह सकती है । उस जनता पर जो बेचारी मूक, चुप है, जब टैक्स सीमा से ज्यादा बढ जाते हैं और उसके बाद आप फरदर टैक्सेशन करते हैं तो वह बगावत का अलम, झंडा खडा करने का सूचक होता है । मैं राजस्थान सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि राजस्थान की इकानामी जिस तरह की है, जो जमीन पर हमने टैक्सेज लगाये हैं, वे टैक्सेज इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि अगर आप फरदर टैक्सेशन करेंगे तो राजस्थान की जनता आपकी नीतियों के खिलाफ विद्रोह करके उठ सकती है । और अगर आप अपनी नीतियों को नहीं बदलेंगे तो जनता आपको बदल देगी । . . .

श्री मथुरादास माथुर (गृह-मंत्री) : २८ तारीख को कर रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो सरकारी आंकडे दिये गये हैं, उसी के अनुसार इस बात को माना जाय कि डाइरेक्ट टैक्सेज, जिनका कि उनके अनुसार बडे आदमियों के ऊपर बोझ पडता है, १९६३-६४ के बजट में पुराने टैक्सों के अनुसार ४१.२ परसेन्ट हैं और जो इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन है, जो कि आम जनता के ऊपर पडता है, वह ५८.८ परसेन्ट है । लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसमें भी एक फालेसी है, जो डाइरेक्ट टैक्स हैं लैंड रेवेन्यू उस को इनडाइरेक्ट टक्स में गिना है । टैकनीकली सही ढंग का टैक्स है वह किसानों से लिया जाता है लेकिन जो आमफहम तरीका है, उसमें डाइरेक्ट टैक्स का मतलब बडे बडे लोगों पर टैक्स से है और इनडाइरेक्ट टैक्स का मतलब गरीब लोगों पर टैक्स से है । इस रूप से देखें और लैंड रेवेन्यू को इसमें से निकाल दें तो डाइरेक्ट टैक्सेशन १७.३ परसेन्ट रह जाता है । इसका मतलब यह है कि राजस्थान सरकार ८६.७ परसेन्ट इनडाइरेक्ट टैक्स गरीब लोगों से वसूल कर रही है । आप यह कहें कि इन एग्रीकल्चरिस्ट्स में भी मालदार लोग है, निहित स्वार्थ वाले लोग हैं तो उसको भी मैं स्वीकार कर लेता हूं । आपके आंकडों के अनुसार, जितने आपने आंकडे दिये हैं, जितने आपने फिगर्स दिये हैं, उनके अनुसार १६ एकड से अधिक जमीन वाले लोगों की आपने इस बजट में सेस से आमदनी आंकी है, वह करीब २५ लाख आंकी है और दो करोड सामान्य किसान, जिन के पास १६ एकड से कम भूमि है, आंकी है । इसका मतलब यह हुआ कि लैंड रेवेन्यू के हैड में १२ परसेन्ट बडे लोगों से आता है और साढे सत्यासी परसेन्ट इन छोटे छोटे लोगों से आता है . . .

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : ये फिगर्स कहां से दे रहे हैं ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ये आंकड़े आप किसमें से ले रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपके ही दिये हुए फिगर्स हैं जिनमें से दे रहा हूं। आपने लैंड रेवेन्यू की इन्कम को ८ करोड ८० लाख माना है अगर इसको आप निकाल दें तो डाइरेक्ट टैक्स से तो आपके डाइरेक्ट टैक्सेज का परसेन्टेज १७.३ रह जाता है।

श्री विजयसिंह झाला : आप यह दूसरी बात कह रहे हैं।

• **श्री रामानन्द अग्रवाल** : ८ करोड ८० लाख में से १ करोड ३० लाख रुपया बड़े जागीरदारों से मान लेते हैं कि उनसे वसूल होंगे तो भी तीन करोड रुपया साधारण किसानों से आता है जो किसी भी हालत में उचित नहीं कहा जा सकता है। इसमें से २० परसेन्ट फिगर्स आवेगें डाइरेक्ट टैक्सेस से और ८० परसेन्ट आपको आमदनी होगी इनडाइरेक्ट टैक्सेस से। इससे गरीब लोगों पर ज्यादा टैक्सों का बोझा पड़ेगा। इस तरह की हालत में जब कि ८० परसेन्ट इन्कम इनडाइरेक्ट टैक्सेस से वसूल होगी और इसका भार पड़ेगा गरीब लोगों पर न कि अमीरों पर इसलिए जहां से ज्यादा आमदनी प्राप्त हो सकती हो उन पर ज्यादा टैक्स होने चाहियें गरीब लोगों पर तो पहले से ही करों का भार बहुत है और अगर आप और ज्यादा करों का बोझ उन पर डालने की कोशिश करेंगे तो उनकी कमर टूट जाएगी। यह आप खुद सोच सकते हैं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जरूरी नहीं कि यही एक तरीका है जिससे कि आमदनी के साधन उपलब्ध किये जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं, जिनसे काफी पैसा इकट्ठा किया जा सकता है और हमने अपनी पार्टी की तरफ से पहले भी अर्ज किया है और फिर भी दुबारा इस सदन के समक्ष मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं जिस पर अगर इस सरकार ने गंभीरता से विचार किया तो काफी आमदनी हो सकती है। सरकार गंभीरता से उस पर विचार करें और गंभीरता से विचार करने के बाद उसके संबंध में कदम उठाये तो इस दिशा में, जिसमें वे चल पड़े नजर आते हैं चलने से उसको रोका जा सकता है और हम इसमें इन्ट्रेस्टेड भी हैं राजस्थान सरकार जिस दिशा में चल पड़ी है उस दिशा में जाने से एक दम रुके और अपने कदम को अबाउट टर्न करदे और इन सुझावों पर ध्यान दें। मैं जो आपके सामने बात रख रहा हूं वह ऐसी बात है जिसको कि शायद आप इस रूप में लें और यह कहें कि यह कम्युनिस्टों के कहने की बात है और उनकी तरफ से सुझाव है इसलिए उसे मंजूर नहीं किया जाए तो यह अलग बात है लेकिन मैं यह कहूंगा कि जिस तरह हमारा प्रान्त पिछड़ा हुआ है और जिस मंजिल पर हमें पहुंचना है और देश को जिस मंजिल पर हमें पहुंचाना है अगर उस मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं तो हमें इस बात को दोहराना होगा हमने पहले कही थी कि जो नरेशों को प्रीवीपर्स दे रही है सरकार उसके बारे में बुनियादी तौर पर उसे सोचना होगा। राजस्थान के किसानों के ऊपर जब हम ज्यादा कर लगाने की बात सोचते हैं तो आप इन राजाओं, जो भूतपूर्व नरेश हैं, को ६६ लाख रुपया प्रीवीपर्स के रूप में क्यों देते हैं? इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यह प्रीवीपर्स राजाओं को राजस्थान सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता यह तो उन्हें सेन्टर की तरफ से दिया जाता है इसलिये इसका

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

असर राजस्थान के बजट पर नहीं पड़ता है। मगर मैं यह कहूंगा कि राजस्थान सरकार इस बात पर सोचे। मैं समझता हूं कि स्वतन्त्र पार्टी के नेता भी इस बात की चुटकी काट चुके हैं और कह चुके हैं कि इसको लेने की आपमें हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत हो तो आप इसको भी ले लीजिये। आपको मना कौन करता है। राजस्थान सरकार इस तरह के कदम उठावे कि जिससे ५० परसेन्ट तो स्केल डाउन होनी चाहिये। ५० परसेन्ट स्केल डाउन होने से ३३ लाख के ३३ लाख सरकार को बच जावेंगे और ३३ लाख की राशि हमारी राजस्थान सरकार को मिल जावेगी और जो ३३ लाख बचेंगे उनके लिए हम कुछ राजाओं से मांगेंगे और वे हमारे मांगने पर दे देंगे और कुछ से प्रार्थना करके लेंगे और अगर कोई मांगने और प्रार्थना करने से नहीं मानेगा तो उनको मनावेंगे और कुछ ऐसे हैं जो कानून बना देने से मान जावेंगे। यों नहीं मानेंगे तो कानून से मान जावेंगे। आप उनसे कम्पल्सरी लोन के रूप में ले लीजिये। इस प्रकार ६६ लाख रुपया आपको इधर से मिल सकता है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): How it comes in our economy ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : It is borrowing.

दूसरा सुझाव जो हमने दिया वह यह कि जागीरदारों को मुआवजा देने के लिए आपने बजट में ३ करोड़ २० लाख रुपयों का प्रावधान रखा है। आपने इसके लिए उनको बोन्ड्स दिये हैं कि इस साल में इतने बोन्ड्स मेच्योर होंगे जिनका जागीरदारों को आपकेश में पेमेन्ट देंगे। जो छोटे छोटे जागीरदार हैं उनके लिये तो हमारे दिलों में भी हमदर्दी है और हम यह चाहते हैं कि वे रिहेबिलिटेट हों। मैं यह कहना चाहता हूं कि पांच हजार रुपयों तक के जिन जागीरदारों के बोन्ड्स मेच्योर होते हों उनको रुपये दे दिये जावें लेकिन उससे ऊपर वाले जागीरदार हैं और जिनके बड़े बड़े अमाउन्ट्स हैं जो इस साल मेच्योर होते है उनको आप कानून से रोक दीजिये आप उसको पोस्टपोन कर दीजिये। इस सम्बन्ध में मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे करने की कोशिश की। मुझे पता लगा कि केवल ८६० जागीरदार ही ऐसे हैं जिनको ५ हजार से अधिक कम्पेन्सेशन अमाउन्ट मिलता है और उनकी किश्तें मेच्योर होती हैं। और यह ८६० लोग इस कम्पेन्सेशन की रकम को ४० परसेन्ट एक्सप्रोप्रियेट करते हैं। अगर ८६० आदमियों को थोड़ी दिक्कत भी पहुंचे तो भी सरकार को उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। संकटकालीन स्थिति में गवर्नमेंट ५० परसेन्ट सेविंग की बात कह सकती है जब वह दूसरे कर्मचारियों से कम्पलसरी सेविंग की बात कहती है तो राजस्थान सरकार जागीरदारों को यह रकम १० वर्षों के लिये देने से रोक सकती है। इसको १० वर्षों तक के लिये पोस्टपोन करने की बात कहें तो मैं समझता हूं कि कोई अनुचित बात नहीं होगी। इससे आपको १ करोड़ २८ लाख रुपया बच सकता है। आप इतना इससे बचा लेंगे।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जो आपने सेन्टर से मदद लेने के सम्बन्ध में रवैया अपनाया है और उसको लोन और इन्ट्रेस्ट वापस देने के संबंध में नीति अपनाई है, हम उसे एक सही नीति नहीं समझते हैं। हम यह समझते है कि राजस्थान सरकार सेन्टर से अपने हिस्से का फेयर डील

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं ले पाई, जिस प्रकार कि दूसरी रियासतें ले पाई हैं । हमारा राजस्थान एक पिछडा हुआ प्रान्त है । इसलिये राजस्थान जैसे पिछडे हुए प्रान्त को अच्छा हिस्सा मिलना चाहिये था, मगर जैसा हिस्सा पिछडे हुए प्रान्त होने के नाते मिलना चाहिये वह हिस्सा हमारी सरकार सेन्ट्रल सरकार से नहीं ले पाई । हम राजस्थान केनाल बनाने जा रहे हैं और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं उन सबका खर्चा हमने हमारे बजट में डाल दिया है । बडे बडे डेम जिनका खर्चा हमारे राजस्थान प्रान्त पर नहीं डाला जाना चाहिये वह खर्च हमने अपने सिर पर डाल दिया है । वास्तविकता यह है कि वह सारा खर्चा सेन्टर को को देना चाहिये । हमारे चीफ मिनिस्टर को इसके लिये लडना चाहिये था और इस हद तक लडना चाहिये था कि अगर उनको राजस्थान के हित के लिये इस्तीफा तक देने की नौबत आती तो वह भी दे देते । जिस प्रकार आसाम के चीफ मिनिस्टर तेल के लिए अपने प्रान्त के वास्तविक हितों के लिए लडे और अन्त में सेन्ट्रल गवर्नमन्ट से इस बात के लिये मनवा कर छोडा और केन्द्रीय सरकार को उनकी वाजिब बात को मानना पडा उसी प्रकार वे भी अपनी बाते मनाते क्योंकि राजस्थान हिन्दुस्तान में बहुत पिछडा हुआ प्रान्त है और खास तौर से यह बोर्डर पर भी आया हुआ है । बोर्डर पर होने के नाते लाखों रुपया हर साल बोर्डर की सुरक्षा में खर्च होता है जो भारत सरकार को देना चाहिये । मगर सुरक्षा और नहरों का खर्चा भी राजस्थान सरकार पर डाला गया है जोकि नहीं होना चाहिये । इतना आप नहीं करा सके आपको इतना तो कराना ही चाहिये था कि बडे बडे प्रोजेक्ट्स, जैसे चम्बल, राजस्थान नहर, भाखरा आदि हैं उसके लिये कर्जा लिया है उसके रीपेमेन्ट का सवाल अभी फौरन नहीं उठना चाहिये । जब ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं और रिटर्न देने लगते और अपना खर्चा अपने आप चला सकते और केपिटल फॉर्मेशन से लोन को रिटर्न कर सकते उस तरह का लोंग टर्म लोन ग्रान्ट करवाना चाहिये था ।

आप कहते हैं कि वे हमसे नहीं माने, हम आपसे भी कहना चाहते हैं क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार सेन्टर में है और आप भी कांग्रेस की तरफ से मंत्रिमण्डल बनाये हुए हैं कि वास्तव में राजस्थान जैसे पिछडे हुए प्रान्त का विकास करना है तो इतना खर्चा अपने सिर पर डालने के बाद अब भी राजस्थान सरकार गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से एग्रीमेन्ट करे कि जो बडे बडे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका ४७५ लाख इन्ट्रेस्ट दे रहे हैं और भी रिटर्न्स दे रहे हैं, ७ करोड रुपया इनके रिटर्न में गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को देने का इस बजट में प्रोविजन किया है, इसको पोस्टपोन करा जाय । १९७० के बाद जब कि आप कहते हैं कि चम्बल से और इन बडे बडे प्रोजेक्ट्स से पूरा फायदा मिलेगा तभी से यह देना शुरु करना चाहिये । राजस्थान गवर्नमेन्ट को दुबारा गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से बात करनी चाहिये क्योंकि इस तरह से काम नहीं चलेगा, जिस तरह वित्त मंत्रीजी ने कहा कि पिछले बकाया भी दे दें, चालू साल का भी दे दें । अगर ऐसा करते हैं तो फिर डवलपमेन्ट से हाथ धो लें ।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, टैक्सेज के बारे में, जो टैक्सेज लगाये हैं, उनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, सुझाव दूंगा कि मनी लैंडर्स को, कन्ट्रेक्टर्स को टैक्स कीजिये ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पढ़ी तो मालुम हुआ कि ३ परसेन्ट के अलावा तमाम क्रेडिट मनी लैंडर्स प्रोवाइड करते हैं और वास्तविकता तो यह है कि ३ परसेन्ट कोआपरेटिव सोसायटीज का भी मनी लैंडर्स को ही जाता है तो आप इनको टैक्स कीजिये । आपको इससे १ करोड रुपया मिलेगा । इनको लाइसेन्स कीजिये इन लाइसेन्सज पर हैवी कर रखिये तो एक करोड के करीब आपको इससे आमदनी होगी । चालीस-पचास हजार के करीब लाइसेन्सीज मनीलैंडर्स मिल सकते है, इनको टैक्स करें तो आपको एक करोड रुपया मिल सकता है । इसी तरह कान्ट्रेक्टर्स को टैक्स करें तो आपको आमदनी हो सकती है । आप २५ करोड रुपया कान्ट्रेक्टर्स के जरिये खर्च करते हैं । इसमें यदि १५ परसेन्ट रामनामी का कमाते हैं, १० परसेन्ट डिपार्टमेन्ट को, पी. डब्ल्यू. डी. को देने के बाद १५ परसेन्ट रामनामी का होता है । यदि किसी मिनिस्टर से दोस्ती हुई तो ज्यादा भी बना लेता है पर १५ परसेन्ट तो है ही । दो परसेन्ट एन्युअल टर्न ओवर पर आप टैक्स करें तो ५० लाख रुपया आपको कान्ट्रेक्टर्स से मिल सकता है । इस तरह से डेढ करोड की और आमदनी आपको हो सकता है । इसके अलावा हमारा सुझाव है कि अरबन प्रोपर्टी है, बडे बडे लोगों ने इन्फलेटेड लैंड वेल्यू का फायदा उठाया है, राजाओं, जागीरदारों, सेट साहूकारों की बडी बडी जायदादें शहरों में हैं एक मयाद से उनको टैक्स कीजिये, उनकी रेन्टल वेल्यू को टैक्स कीजिये । जैसा आसाम ने किया है, वैसा आप भी करें तो आमदनी बढ सकती है ।

अब मैं एक खास चीज पर आऊंगा । हमारा यह सजेशन है कि अब वह वक्त आ गया है कि सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्टरी को नेशनेलाइज करें । वीवियन बोस की रिपोर्ट आने पर जिसमें सीरियस चार्जेज इस कन्सर्न्स के प्रति लगाये गये हैं कि किस तरह मेनुपुलेट करके शेअर होल्डर्स को और जनता को धोखा देते हैं । वीवियन बोस की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सवाई माधोपुर का सीमेन्ट कारखाना पहले और नाम से था, दो दिन में ही इसे जयपुर उद्योग के नाम से बना दिया गया । इसके ६० लाख के डिबेन्चर्स सरकार द्वारा खरीदे हुए हैं, ६० लाख पावर का दिया हुआ है, ७ लाख साइडिंग वगैरह के लिये दिया हुआ है । ५ लाख स्याही से और बढा दिया गया है । यह तो सरकार का प्राईवेट तरीका है, जिस तरह काटना चाहे काट दें । मैं चाहता था, मुख्य मंत्री होते तो मुख्य मंत्री को सुनाता कि वे अगर शान्तिप्रसाद जैन का कारखाना नेशनेलाइज भी कर लेंगे तो भी कलकत्ता में उनके ठहरने के लिये वहां स्टेट गेस्ट हाउसेज हैं, वहां ठहर सकते हैं . . . .

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : वहां ४ लाख मारवाडी हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : शान्तिप्रसाद जैन, हो सकता है ज्यादा सुविधा दे सकते हैं । पिछली मर्तबा गये थे तो ४ दिन वहां महमान रहे थे, वहां कारें ज्यादा मिलती हैं, बंगला भी बडा है . . . . .

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सुना है कि आपने भी चिट्ठी लिखी थी वहां ठहरने को . . . . .

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने किसी गटर प्रेस में पढा होगा ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : माननीय सदस्य ......

श्री अध्यक्ष : Order Please! Shri Jwalaprasad Dont disturb !!

श्री रामानन्द अग्रवाल : वीवियन बोस की रिपोर्ट पढने के बाद ऐसा महसूस होता है कि राजस्थान सरकार का इस उद्योग में जितना पैसा जमा है, वह पैसा भी खतरे में है। शान्तिप्रसाद जैन ने अपने नाम से मुआवजा दिखा कर जैसा दूसरी जगह किया वैसा हमें यहां भी खतरा है । राजस्थान सरकार को फौरन इस फैक्टरी को नेशनेलाइज करना चाहिये । इसके अतिरिक्त ......

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता था कि नेशनेलाइजेशन ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट के लिये पिछले सेशन में अर्ज किया था, उसमें २७ लाख के रिटर्न्स आपको हुए हैं । अगर १५ प्रतिशत आपने इन्वेस्टमेन्ट पर रिटर्न माना है तो बजाय इसके कि इस फैक्टरी को रुपया देते हैं जहां से १ परसेन्ट, दो परसेन्ट मिलता हैं, आपको नेशनेलाइजेशन ऑफ रोड ट्रान्स्पोर्ट को एक्स्पेन्ड करना चाहिये और वह इसी बजट में करें । यह ओन दी होल मेच्योर हो जाय तो तीन करोड की आमदनी यह आपको दे सकता है। पिछले सेशन में यू. पी. और पंजाब की मिसालें रखी थी कि कहीं ४ करोड और कहीं ५ करोड का मुनाफा हुआ है तो कोई वजह नहीं कि राजस्थान में नहीं हो । इस पर ध्यान दीजिये तो आपको मुनाफा हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता लेकिन ऐसे ऐसे इन्कम के सोर्सेज आपके पास हैं जिनसे आपको अच्छी इन्कम हो सकती है । फलाना कोल, सोडियम सल्फेट का कारखाना, जैसा कि पहले निवेदन किया था—इनसे आप आमदनी बढा सकते हैं । बजाय बिडला और पूंजिपतियों के देने के इनका राष्ट्रीयकरण कीजिये, इनसे आपको आमदनी हो सकती है । यदि आप इन तरीकों को अपनाये तो मैं समझता हूं इस रास्तों पर जिस पर कि आप आज चल रहे हैं उस पर आपको चलना नहीं पडेगा ।

इसके अलावा इकोनोमी, मितव्ययता भी कर सकते हैं । इसमें कुछ अपने लोगों को पटाने की बातें करते हैं, इसको छोडना पडेगा । यह नहीं करेंगे तो इसका बडा डीमोरेलाइजिंग इफेक्ट आज पड रहा है, उससे भी कहीं ज्यादा पडेगा ।

(२.म० प०)

हमें आश्चर्य हुआ इस बात को देख कर कि टौंक राज्य के परिवार में किसी सदस्य के ऊपर सन् १९११ का लिया हुआ कर्जा था, सन् १९११ का लिया हुआ कर्जा और सन् १९४७ तक फर्म ने मांगा नहीं और जब टौंक राजस्थान में मिल गया तो उसकी दरख्वास्त ले ली गई कि इस कर्ज को चुकाये । लीगल डिपार्टमेन्ट ने यह राय दे दी कि सरकार के कोई रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं है इस कर्ज को चुकाने की लेकिन हमारी इस सरकार ने ५९ हजार रुपया किसी फर्म को पेमेन्ट कर दिया जिसका कोई लीगल बैसिस नहीं था लेकिन हमारी यह सरकार लीगली न मानते हुए भी उसको मोरेली मानती है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह-मंत्री) : यह कब हुआ ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : १९५९ में हुआ।

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : आडिट रिपोर्ट में देख लें ।

श्री मथुरादास माथुर : वह भी देख लेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह अन्कन्फर्म्ड है, कुछ लोगों ने बताया कि कोई इम्पोर्टेन्ट व्यक्ति है । गफूरन के नाम से उसको पेमेन्ट किया गया । अनकन्फर्म्ड तौर पर कहता हूं । जानकारी करने में लगा हूं और जानकारी मिल जावेगी तो बता दूंगा ।

श्री मथुरादास माथुर : गफूरन को आप जानते हैं या मुखियाजी जानते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं उस गफूरन को जानता हूं जो आपके पास रहती है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): न आप जानते हैं न वे जानते हैं, मुख्य मंत्रीजी जानते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसी प्रकार धौलपुर की एक ग्लास फैक्टरी है । उसको पावर हाउस से बिजली दी गई इस बिना पर कि बिजली की कोस्ट प्राइस पडेगी उस रेट पर दी जायगी । चार आना कोस्ट प्राइस बनी लेकिन सरकार ने ३॥ आने का बिल बनाया फिर भी उसने पेमेन्ट नहीं किया । इसको सन् १९४३ से बिजली दी गई थी । इसने १९५० के बाद पेमेन्ट नहीं किया । १,३६ हजार रुपया इसकी तरफ बाकी है । धौलपुर ग्लास फैक्टरी की तरफ १,३६ हजार रुपया बाकी है । हमारी सरकार ने ५५.५६ में फैसला किया कि ३॥ आने के बजाय ३ आने दे दो । फिर भी एक पैसा नहीं चुकाया । अपना पावर हाउस लगा लिया, कुछ पैसा नहीं दिया । सन् १९६१ में उसके खिलाफ पी. डी. आर. में कार्यवाही होने लगी तो स्टे ओर्डर मिल गया । कहने लगे कि सरकार दुबारा विचार करना चाहती है, कारखाने की हालत को देखते हुए यह रेट अधिक मालूम पडती है इसलिए पेमेन्ट रोक दिया गया । यह तरीका आप अपनायें और १ लाख ३६ हजार रुपया १९४९ से बाकी है उसे वसूल न करें और सन् १९११ का ५९ हजार का पेमेन्ट करें, इस तरीके के मौरेल्स इस तरीके के राज्य चलाने के तरीके, अध्यक्ष महोदय, मैं अदब से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनाते हैं तो राजस्थान की जनता, पर आपके भाषणों का, आपकी अपीलों का, इमर्जेन्सी का कोई असर नहीं होता है बल्कि आपकी सब बातों को धोखे की बात समझती है, धोखेबाज समझती है और कहती है कि ऊपरी मन से कहने की बात कुछ और है और करने की बात कुछ और है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में यह जान लूं कि टौंक में, कहा गया, किसी को ५९ हजार का लोन माफ कर दिया गया और यह नाम लिया गया कि कोई गफूरन बाई है जिसके बारे में मैं परिचित हूं या किसी प्रकार नाम लिया गया मेरे से सम्बन्धित है, इस पर मैं सख्त ऐतराज करता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : आपका नाम नहीं लिया है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : टौंक में ऐसा फैसला हुआ है यह कहा गया है·····

श्री रामानन्द अग्रवाल : आडिट रिपोर्ट १९५९ की है उसमें बताया गया है कि पेमेण्ट किया गया है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसके बारे में ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अनकन्फर्म्ड तरीके से पता लगा है कि गफूरन है । इसको कन्फर्म कर रहा हूं । अगर इन्सिस्ट करें तो मैं यह अनकन्फर्म्ड बता रहा हूं । मैंने संकेत मात्र किया है । यह अमाउन्ट दिया है यह सही है ।

Page No.59

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नाम लिया है। आपने कहा या किसी माननीय सदस्य ने कहा कि मुख्य मंत्री भी परिचित हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कौन है, कब फैसला किया क्या इसके फैक्ट्स है; यह जानकारी तो होनी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मैं कन्टीन्यू करूं। मैंने तो कहा नहीं है, मैंने कहा नहीं कि आप परिचित हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : हांडा साहब ने कहा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फर्म जो है, गफूरन फर्म है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : टैक्सैशन प्रपोजल्स है जो सरकार की ओर से रखे गये हैं, अब मैं उनके ऊपर आता हूं। सरकार ने चार करोड के टैक्स लगाने की बात दिखायी। हमारे वित्त मंत्री बहुत चालाक मालूम पडते हैं। चाहे उनकी उम्र कितनी ही हो, होशियारी में बूढे नहीं हुए हैं। ये टैक्स एक्चुअली ४.९० लाख का है उसको भाषण में चार करोड लिख कर कि चार करोड के ही टैक्स लगा रहे हैं। इस तरह कहना जनता के साथ धोखा करना है। ९० लाख रुपया यदि पंचायत समितियों को देंगे तो आखिर वे जनता की ही जेब से तो निकल जावेंगे। आपने जनता पर टैक्सों का बर्डन तो ४.९० लाख का ही डाला है। दर असल आपके प्रपोजल्स पांच करोड के हैं। आपने अपने हाथ में आरबिट्रेरी पावर्स रख ली है कि आप इसको बाद में लगा सकते हैं क्योंकि आप इसको बजट में डिक्लेयर नहीं करना चाहते कि कौन से ५० लाख के टैक्स लगाना चाहते हैं और किस प्रकार इसको पूरा करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां जो आंकडे दिये हैं २। करोड के, वह अन्डर एस्टीमटैड हैं। करीब ८ करोड लैंड रेवेन्यू की आमदनी है। २५ परसेन्ट हर एक से लेंगे तो २ करोड तो वह हो जाती है। ३३ परसेन्ट या पचास परसेन्ट लगायें तो मैं समझता हूं कि कहीं ज्यादा आगे जावेगी। इस तरह से आपने यह टैक्स लगाये हैं यह बिलकुल नावाजिब है, टैक्सैशन के उसूलों के अनुसार भी यह गलत है। दरअसल ये टैक्स उस तरीके की किसान की आमदनी पर नहीं हैं जिसको सरप्लस कहा जा सके, डिफरेन्शियल आमदनी कह सकें, ऐसी आमदनी कह सकें कि जो जीवन स्तर को बढा रही हो। उस पर एब्सोल्यूट रेन्ट बढाना चाहते हैं, ग्राउन्ड रेट बढाना चाहते हैं यह आप ब्रिटिश गवर्नमेन्ट जैसा तरीका अपना रहे हैं और उसका जो नतीजा निकला वही इसका नतीजा निकलेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि आपने खुद ने यह स्वीकार किया है सीलिंग लगे। सीलिंग का स्टेन्डर्ड मुकर्रर किया है उस ३६०० तक की आमदनी टैक्स नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हमारी पार्टी का कहना है कि ३० स्टेन्डर्ड एकड तक की जमीन को एक्जम्प्ट करना पडेगा। इस तरह से सारी बुनियाद को देखते हुए जो टैक्स आपने लगाये हैं हम उनका तीव्र विरोध करते हैं। इसी प्रकार एनीमल एक्स्पोर्ट टैक्स है। जो टैक्स आपने लगाया है वह उसी तरह का टैक्स है जो कस्टम्स कहलाता है। किसानों ने बडी मुश्किल से तो कस्टम्स से पीछा छुडाया, बडा भारी आन्दोलन किया। अब सेल्स टैक्स या परचेज टैक्स के नाम से आप इसको दुबारा ले आये हैं, आप दुबारा इसको इम्पोज करना चाहते हैं मैं समझता हूं कि राजस्थान का किसान इसको कभी गवारा नहीं करेगा।

इसी प्रकार सेल्स टैक्स में ५ से ७ परसेन्ट और ७ से १० परसेन्ट की बढोतरी की है और जिस तरह से और माननीय सदस्यों ने

(श्री रामानद अग्रवाल)
कहा कि जब दिल्ली के मार्केट में ४ परसेन्ट सेल्स टैक्स लग कर कोई चीज मिलेगी तो आपके मार्केट से कौन खरीदेगा ? दिल्ली से ले आवेंगे, आपकी इससे आमदनी भी ज्यादा नहीं होगी और जनता पर भी भार पड़ेगा।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अन्त में समाप्त करता हुआ यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से टैक्सों का भयंकर नतीजा होगा। मैं एक विख्यात नेता के शब्दों में ही बता देना चाहता हूं कि इसका क्या नतीजा होने वाला है। उन्होंने कहा है ऐसी सरकार के बारे में जो इस प्रकार के कार्य अपनायेगी.........

श्री मथुरादास माथुर : नेता का नाम ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अन्त में बताऊंगा।

"If an indigenous Government took the place of the foreign Government and kept all the vested interests intact this would not be even the shadow of freedom. The whole basis and urge of the National Movement came from a desire for economic betterment to throw off the burdens that crushed the masses and to crush the exploitation of the Indian people. If these burdens continue and are actually added to, it does not require a powerful mind to realise that the fight must not only continue but grow more intense. Leaders and individuals may come and go, they may get tired and slacken off, they may compromise or betray, but the exploited and suffering masses must carry on the struggle for their drill sergeant is hunger. Swaraj or freedom from exploitation for them is not a fine paper constitution or a problem of the hereafter. It is a question of here and now of immediate relief."

यह किसी लेनिन या स्टालिन ने नहीं कहा। ये बातें पं० जवाहर लाल नेहरू ने लिखी हैं और आजादी से पहले लिखी हैं और उन्होंने यह बात कही थी। राजस्थान सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि जिस पालिसी को आप अपना रहे हैं यह बिल्कुल उसी तरह की है। आप इस तरह से जहां से बर्डन घटाया जाना चाहिये उसको घटाने के बजाय बर्डन बढ़ाते जा रहे हो। आप इस तरह से जनता का विश्वास खोते जा रहे हो, जनता को विट्ट करते जा रहे हो यदि इसी प्रकार की आपकी नीति रही तो जैसा पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा है वही होकर रहेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय मुख्य मंत्री चाहें तो वह आडिट रिपोर्ट का पैरा जिसका जिक्र अभी आया था पढ़कर सुना दूं। आडिट रिपोर्ट १९६२ के पेज ५७, पैरा ७९ में लिखा हुआ है :

"The State Government made an ex-gratia payment of Rs. 57,000 in May, 1959 to a firm bankers in final settlement of its dues against loans which had been advanced by it to a member of the former royal family of the Tonk State during the period 1911 to 1917. It appears that the firm did not raise the question of repay-

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नाम लिया है। आपने कहा या किसी माननीय सदस्य ने कहा कि मुख्य मंत्री भी परिचित हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कौन है, कब फैसला किया क्या इसके फैक्ट्स हैं; यह जानकारी तो होनी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मैं कन्टीन्यू करूं। मैंने तो कहा नहीं है, मैंने कहा नहीं कि आप परिचित हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : हांडा साहब ने कहा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फर्म जो है, गफूरन फर्म है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : टैक्सैशन प्रपोजल्स है जो सरकार की ओर से रखे गये हैं, अब मैं उनके ऊपर आता हूं। सरकार ने चार करोड के टैक्स लगाने की बात दिखायी। हमारे वित्त मंत्री बहुत चालाक मालूम पडते हैं। चाहे उनकी उम्र कितनी ही हो, होशियारी में बूढे नहीं हुए हैं। ये टैक्स एक्चुअली ४.९० लाख का है उसको भाषण में चार करोड लिख कर कि चार करोड के ही टैक्स लगा रहे हैं। इस तरह कहना जनता के साथ धोखा करना है। ९० लाख रुपया यदि पंचायत समितियों को देंगे तो आखिर वे जनता की ही जेब से तो निकल जावेंगे। आपने जनता पर टैक्सों का बर्डन तो ४.९० लाख का ही डाला है। दर असल आपके प्रपोजल्स पांच करोड के हैं। आपने अपने हाथ में आरबिट्रेरी पावर्स रख ली हैं कि आप इसको बाद में लगा सकते हैं क्योंकि आप इसको बजट में डिक्लेयर नहीं करना चाहते कि कौन से ५० लाख के टैक्स लगाना चाहते हैं और किस प्रकार इसको पूरा करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां जो आंकडे दिये हैं २। करोड के, वह अन्डर एस्टीमेटेड है। करीब ८ करोड लैंड रेवेन्यू की आमदनी है। २५ परसेन्ट हर एक से लेंगे तो २ करोड तो वह हो जाती है। ३३ परसेन्ट या पचास परसेन्ट लगायें तो मैं समझता हूं कि कहीं ज्यादा आगे जावेगी। इस तरह से आपने यह टैक्स लगाये हैं यह बिलकुल नावाजिब है, टैक्सेशन के उसूलों के अनुसार भी यह गलत है। दरअसल ये टैक्स उस तरीके की किसान की आमदनी पर नहीं हैं जिसको सरप्लस कहा जा सके, डिफरेन्शियल आमदनी कह सकें, ऐसी आमदनी कह सकें कि जो जीवन स्तर को बढा रही हो। उस पर एबसोल्यूट रेन्ट बढाना चाहते हैं, ग्राउन्ड रेट बढाना चाहते हैं यह आप ब्रिटिश गवर्नमेन्ट जैसा तरीका अपना रहे हैं और उसका जो नतीजा निकला वही इसका नतीजा निकलेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि आपने खुद ने यह स्वीकार किया है सीलिंग लगे। सीलिंग का स्टेन्डर्ड मुकर्रर किया है उस ३६०० तक की आमदनी टैक्स नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हमारी पार्टी का कहना है कि ३० स्टेन्डर्ड एकड तक की जमीन को एक्जम्प्ट करना पडेगा। इस तरह से सारी बुनियाद को देखते हुए जो टैक्स आपने लगाये हैं हम उनका तीव्र विरोध करते हैं। इसी प्रकार एनीमल एक्स्पोर्ट टैक्स है। जो टैक्स आपने लगाया है वह उसी तरह का टैक्स है जो कस्टम्स कहलाता है। किसानों ने बडी मुश्किल से तो कस्टम्स से पीछा छुडाया, बडा भारी आन्दोलन किया। अब सेल्स टैक्स या परचेज टैक्स के नाम से आप इसको दुबारा ले आये हैं, आप दुबारा इसको इम्पोज करना चाहते हैं मैं समझता हूं कि राजस्थान का किसान इसको कभी गवारा नहीं करेगा।

इसी प्रकार सेल्स टैक्स में ५ से ७ परसेन्ट और ७ से १० परसेन्ट की बढोतरी की है और जिस तरह से और माननीय सदस्यों ने

(श्री रामानद अग्रवाल)
कहा कि जब दिल्ली के मार्केट में ४ परसेन्ट सेल्स टैक्स लग कर कोई चीज मिलेगी तो आपके मार्केट से कौन खरीदेगा ? दिल्ली से ले आवेंगे, आपकी इससे आमदनी भी ज्यादा नहीं होगी और जनता पर भी भार पड़ेगा ।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अन्त में समाप्त करता हुआ यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से टैक्सों का भयंकर नतीजा होगा । मैं एक विख्यात नेता के शब्दों में ही बता देना चाहता हूं कि इसका क्या नतीजा होने वाला है । उन्होंने कहा है ऐसी सरकार के बारे में जो इस प्रकार के कार्य अपनायेगी . . . .

श्री मथुरादास माथुर : नेता का नाम ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अन्त में बताऊंगा ।

"If an indigenous Government took the place of the foreign Government and kept all the vested interests intact this would not be even the shadow of freedom. The whole basis and urge of the National Movement came from a desire for economic betterment to throw off the burdens that crushed the masses and to crush the exploitation of the Indian people. If these burdens continue and are actually added to, it does not require a powerful mind to realise that the fight must not only continue but grow more intense. Leaders and individuals may come and go, they may get tired and slacken off, they may compromise or betray, but the exploited and suffering masses must carry on the struggle for their drill sergeant is hunger. Swaraj or freedom from exploitation for them is not a fine paper constitution or a problem of the hereafter. It is a question of here and now of immediate relief."

यह किसी लेनिन या स्टालिन ने नहीं कहा । ये बातें पं० जवाहर लाल नेहरू ने लिखी हैं और आजादी से पहले लिखी हैं और उन्होंने यह बात कही थी । राजस्थान सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि जिस पालिसी को आप अपना रहे हैं यह बिल्कुल उसी तरह की है । आप इस तरह से जहां से बर्डन घटाया जाना चाहिये उसको घटाने के बजाय बर्डन बढ़ाते जा रहे हो । आप इस तरह से जनता का विश्वास खोते जा रहे हो, जनता को बिट्टे करते जा रहे हो यदि इसी प्रकार की आपकी नीति रही तो जैसा पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा है वही होकर रहेगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय मुख्य मंत्री चाहें तो वह आडिट रिपोर्ट का पैरा जिसका जिक्र अभी आया था पढ़कर सुना दूं । आडिट रिपोर्ट १९६२ के पेज ५७, पैरा ७९ में लिखा हुआ है :

"The State Government made an ex-gratia payment of Rs. 57,000 in May, 1959 to a firm bankers in final settlement of its dues against loans which had been advanced by it to a member of the former royal family of the Tonk State during the period 1911 to 1917. It appears that the firm did not raise the question of repay-

(श्री भैरोंसिंह)

ment of the loan with the Ruler till just before the merger of the State. The payment sanctioned from the State revenues in May, 1959 has been justified on the ground of moral obligation of Government, although it had been held that Government were not legally bound to repay the amount".

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : इसमें नाम कहां है ?

श्री रामानंद अग्रवाल : नाम अगर होता तो वह कह नहीं दिया जाता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, जो एक्सट्रेक्ट इसमें दिया गया है उस एक्सट्रेक्ट के बेसिस पर बात कहना एक बात होती है और उस बात के साथ में कोई और चीज जोड कर के कहना और उसके साथ यह जोडना कि अमुक व्यक्ति उनको जानते हैं, इससे इस प्रकार का इम्प्रेशन देना कि जान पहिचान वालों को रुपया दे दिया गया इस वजह से मैंने ऐतराज किया था। जिस फर्म के बारे में उल्लेख है मैं समझता हूं वह बुद्धमल बाफना फर्म के बारे में है। ऐसी बात को किसी के साथ जोडकर चलना उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अगर नाम के लिये कन्टेस्ट करें तो नाम भी वही मिलेगा जो माननीय सदस्य ने बताया है। टौंक की रूलिंग फेमिली के मेम्बर को दिया गया जो माननीय सदस्य ने कहा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं शायद उस समय पैदा ही नहीं हुआ हूंगा।

श्री भैरोंसिंह : पैदा होकर कोई मर भी जाय तो क्या। आखिर जो नाम होता है वह तो रहता ही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लेकिन उसके साथ यह जोडना कि मैं उनको जानता हूं जिनको रुपया दिया गया। जिस फर्म को रुपया दिया गया उसके बारे में फैक्ट रखे जाते। उनको तो फर्म के नाम से रुपया मिलने का सवाल ही नहीं।

श्री रामानंद अग्रवाल : मुझे आश्चर्य यह होता है, अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मुख्य मंत्री अफसोस जाहिर करते कि स्टेट का जो पैसा है उसका इस प्रकार स्केन्डल किया जा रहा है। नाम में मतभेद हो सकता है किन्तु जहां तक स्टेट के रुपये को देने का सवाल है वह तो दिया गया। इसमें जो मेटिरियल बात है वह यह कि स्टेट फन्ड में से यह क्यों दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : स्केन्डल है या नहीं, इसका तो जवाब दिया जायगा।

एक माननीय सदस्य : तो गफूरन के नाम से क्यों देते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस तरह से जबरदस्ती हवा क्रिएट करना चाहते हैं ?

श्री रामानंद अग्रवाल : हवा तो बनी हुई होती है, जबरदस्ती क्रिएट नहीं होती।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट १९६३-६४ पर कल से विचार विनिमय हो रहा है। जिस परिस्थिति में माननीय वित्त मंत्री ने यह बजट प्रस्तुत किया है वास्तव में यह

(श्री तेजाराम गहलोत)

संकटकालीन परिस्थिति का बजट है। जब देश में संकटकालीन परिस्थिति है यह स्वाभाविक है कि हमारे इस प्रान्त में भी इस संकटकालीन परिस्थिति का इस बजट पर असर पडे बिना नहीं रहेगा। जहां तक इस स्थिति का ताल्लुक है सदन के सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे। इस स्थिति में यह देखना भी हमारा फर्ज है कि जो घाटा माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट में बताया है वास्तव में वह घाटा किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है–इस बात पर भी विचार करना हमारा फर्ज हो जाता है। जहां तक हमारे सामने ४॥ करोड रुपये के घाटे का प्रश्न है उसके बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हम राजस्थान के ट्रान्सपोर्ट, रेवेन्यू और माइनिंग इन तीनों विभागों से होने वाली आय का विश्लेषण करें तो मैं यह कहूंगा कि ट्रान्सपोर्ट विभाग के अन्दर जितना टैक्स वसूल होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। जो स्टेट रोडवेज चल रही है उसके अन्दर जितना प्रोफिट दिखाया गया है, अगर स्टेट रोडवेज को सुचारू रूप से चलाया जाय और सुव्यवस्था की जाय तो सरकार द्वारा जितना प्रोफिट इस बजट में बताया गया है उससे कहीं अधिक प्रोफिट हो सकता है। जो व्यक्तिगत रूप से बसें चलाते थे, आर्थिक साधन न होते हुए हायर पर्चेज पर जो बसेज चलाते थे वे नफा कमाते थे और हमारी सरकार को घाटा होता है। अभी सरकार की ओर से स्टेट रोडवेज को, क्योंकि ज्यादा बसेज चलाती है, दस परसेन्ट कन्सेसन दिया हुआ है। फिर भी इतन महत्वपूर्ण मार्ग, जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया है, पर भी कम मात्रा में नफा दिखाया गया है। जब ये ही मार्ग व्यक्तिगत नागरिकों के पास थे तो वे एक हजार डेढ डेढ हजार रुपया महीने का नफा कमाया करते थे। साथ में मैं यह भी आपके जरिये निवेदन कर दूं, जहां पर स्टेट रोडवेज और प्राइवेट बसेज दोनों चलती हैं वहां स्टेट रोडवेज के जो कर्मचारी हैं क्या वे सही मायने में अपने कर्तव्य को निभाते हैं न तो इस ओर विभाग के अधिकारी ध्यान देते हैं और न कभी उन्होंने ध्यान देने की जरूरत ही समझी है। उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं कि जोधपुर से सिरोही स्टेट रोडवेज की बसेज चलती हैं वहां रोडवेज के कन्डक्टर अपने थोडे से स्वार्थ के लिये दो तीन रुपये का लाभ देखकर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की प्राइवेट गाडियां जाने के दस मिनिट बाद अपनी बस चलाते हैं और उसके साथ साथ चलकर रास्ते में पडने वाले पेसेन्जर्स को लेते नहीं हैं और डाइरेक्ट चले जाते हैं। उसी रूट पर जोधपुर और पाली बस सर्विस चलती है उसमें प्राइवेट बसेज से सौ डेढ सौ आदमी ट्रेवल करते हैं जब कि स्टेट रोडवेज में केवल चार पांच पेसेन्जर मुश्किल से बैठते हैं। क्या कभी माननीय मंत्री महोदय ने कोशिश की है या करेंगे जहां अपने प्रान्त के बजट के घाटे का सवाल है, सभी माननीय सदस्य इस पर गंभीरता से विचार करेंगे जब इस अव्यवस्था के कारण सरकार की आमदनी में हर्जाना होता है तो इसको मैं समझता हूं कोई भी माननीय सदस्य बर्दाश्त नहीं कर सकेगा।

साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूं कि ट्रान्सपोर्ट का जो डिपार्टमेन्ट है और आर. टी. ओ. का जो आफिस है वह भी अपने कर्त्तव्य को निभाने में असफल रहते हैं मैं यह निवेदन करूं कि जोधपुर टू ब्यावर जो बसेज चलती हैं उनका परमिट आर. टी. ओ. ने पाली टू ब्यावर रिन्यू किया है। पर वे बसेज

(श्री तेजाराम गहलोत)

आज भी ब्यावर से जोधपुर चलती हैं और कोई उनको रोकने की कोशिश नहीं करता है जब कि परमिट में कन्डीशन है कि वह पाली टू ब्यावर रिन्यू किया गया है । और ट्रान्सपोर्ट विभाग उनको रोकने की कोशिश करता है तो जोधपुर से सिरोही चलने वाली बसों को फायदा हो सकता है । आप जब आज इस तरह के भारी टैक्स लगाने पर विचार कर रहे हैं उसके साथ ही अगर अपनी आमदनी को बराबर वसूल करने की ओर ध्यान दें तो अधिक भारी टैक्स लगाने की आपको आवश्यकता ही अनुभव न हो । साथ ही जो लोड लॉरियां हैं, प्राईवेट कैरियर्स हैं उनका भी न तो आप प्रोपरली टैक्स वसूल करते हैं न उसके प्रति बराबर जागरूक ही हैं ।

इसी तरह से मैं रेवेन्यू विभाग के सम्बन्ध में भी कुछ अर्ज करना चाहूंगा । जहां तक राजस्थान में रेवेन्यू वसूली का सवाल है हिन्दुस्तान में शायद यहां सबसे ज्यादा लैंड रेवेन्यू है । लेकिन इतना ज्यादा लैंड रेवेन्यू होते हुए भी आज मैं यह कहूंगा कि हमारे यहां रेवेन्यू के मामलों में लाखों रुपयों का घोटाला होता है यह कहना अनुचित नहीं होगा । जहां तक जागीर रिजम्पशन का सवाल है उसका मुआवजा दिया गया कानून के अनुसार । लेकिन वह वास्तव में कानून के अनुसार हुआ या नहीं इसको देखने की सरकार को फुरसत ही नहीं है । इस कानून का आज बहुत दुरुपयोग किया गया है और किया जा रहा है । सरकारी रकम का बहुत ही गोलमाल किया जा रहा है । मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी गम्भीर संकटकालीन परिस्थिति में, जब कि हमारे बजट में ४।। करोड का घाटा है, ऐसी चीजों को अधिक गौर से छानबीन करके देखा जाय तो मैं विश्वास दिला सकता हूं कि एक पाली जिले से ही ८।१० लाख की ऐसे मामलों में बचत कराई जा सकती है । इसमें मैं सहयोग दे सकता हूं । इस तरह से जब हमारे रेवेन्यू का दुरुपयोग होता है और दूसरी तरफ हम टैक्स लगाते हैं तो यह उचित प्रतीत नहीं होता ।

आज हम राजस्थान की प्रगति की बातें बहुत बार करते हैं पर आज से तीन साल पहले पास किये गये सीलिंग के कानून का इम्प्लीमेन्टेशन नहीं कराया गया अभी तक, न इसका बजट में कोई प्रोवीजन है । इसलिए मैं यह मानकर चलता हूं कि ६३-६४ में भी इस कानून को इम्प्लीमेन्ट करने की सरकार की मंशा नहीं है । मैं पूछता हूं फिर इस तरह का कानून पास करने का मक्सद सरकार का क्या है ? आज बातें बडी प्रगतिशीलता की करते हैं कि हम भूमिहीन काश्तकारों को भूमि देना चाहते हैं और इस के लिये सीलिंग के कानून को पास भी किया, पर सरकार उसको इम्प्लीमेन्ट नहीं करना चाहती । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस सीलिंग के कानून को ६३-६४ में लागू करके भूमिहीन काश्तकारों को भूमि दिलाने की व्यवस्था करें ।

इसके अलावा आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सदन में यह आरोप लगाया कि जातिवाद का आज की सरकार में बोलबाला है और उन्होंने इस बात की डींग हांकी कि न तो वे जातिवाद में विश्वास रखते हैं और न नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं वे जागीरदारों का । पर मैं उदाहरण पेश करूं कि उन्होंने जागीर रिजम्पशन एक्ट की धाराओं का किस तरह से अपने खुद के स्वार्थ दुरुपयोग किया तो शायद यह अनुचित नहीं होगा । कानून हमने बनाया । अगर वह सभी

(श्री तेजाराम गहलोत)
जागीरदारों के लिये एक सरीखा इम्प्लीमेन्ट होता है तो ठीक बात है। पर एक के साथ पक्षपात और दूसरे के साथ नाराजगी तो यह प्रजातन्त्र के खिलाफ बात है। पाली जिले में जागीर रिजम्पशन के वक्त जागीरों का सैटलमेन्ट नहीं हुआ था, उस सैटलमेन्ट के दौरान में से चल रहा था और उस दौरान यह कहा गया कि लटाई के आधार पर उनको मुआवजा मिलेगा। पर एक को कमिश्नर ने लटाई के आधार पर मुआवजा दिलाया दूसरों को नहीं दिलाया।

(२. म.पं.)

(राव श्री नारायणसिंह उपाध्यक्ष, पदासीन)

जब कि इन सारे जागीरदारों के केस एक ही आधार पर खडे होते हैं। जागीर कमिश्नर ने फैसला दिया, हमारी सरकार ने रेवेन्यू बोर्ड में अपील भी की पर जितना अफसोस जागीर कमिश्नर के फैसले से हुआ, उससे अधिक अफसोस इस बात से हुआ कि बाद में हमारी सरकार ने अपनी अपील अनकन्डीशनली विथड्रा कर ली। समझ में नहीं आया कि क्या बात थी ऐसी कि जिसकी वजह से पहले तो अपील की और फिर किस बात ने सरकार को मजबूर कर दिया उसे अनकन्डीशनली विथड्रा करने के लिये। तो इस तरह से हमारे रेवेन्यू के पैसे का दुरुपयोग होता है। और इससे हमें दुख होता है।

मैं माइनिंग विभाग की बात बताता हूं। राजस्थान मिनरल्स के मामले में अच्छा रिच है। यहां अच्छी से अच्छी खाने हैं। पर उनका आज प्रोपर युटिलाइजेशन नहीं होता है। सरकार के माइनिंग विभाग का रवैया इस मायने में बडा खतरनाक है। मिसाल के तौर पर मैं निवेदन करूं, जोधपुर डिवीजन में लाइम स्टोन है। सरकार ने एक तरह से उसकी मोनोपोली को बनाये रखने में अपनी सारी ताकत खर्च कर दी। संविधान में मोनोपोली बनाये रखना वर्जित है। पर फिर भी कानून के जरिये मोनोपोली न रखते हुए अपने हुक्म के जरिये तो आज भी मोनोपोली बहाल कर रखी है इस सरकार ने। गोटन के लाइम की लीज स्टेट के वक्त १,८१०००)हजार म थी पर अब उस रायल्टी को सरकार ने ९६ हजार की है। जब कि इस युग में रायल्टी बढानी चाहिये, पर बजाय बढाने के रियायत दी गई। सोजत रोड में लाइम की रायल्टी स्टेट के वक्त १,१००००) हजार थी, आज उसको भी ६४ हजार कर दिया इस सरकार ने। सन् १९५० से लेकर आज दिन तक इस इन्डस्ट्री में इस एरिया में सरकार के इस विभाग ने किसी दूसरे को घुसने नहीं दिया। सोजत रोड के ठेकेदार ने दस मील का एरिया ले रखा है। दूसरे ने ऊंची रायल्टी पर उस एरिया को लेने के लिये प्रयत्न किया, यहां तक भी प्रयत्न किया कि सब एरिया न सही, उसका एक हिस्सा दे दिया जाय और रायल्टी भी उससे अधिक आफर की, पर उसको भी सरकार ने उस एरिया में घुसने नहीं दिया और उस दस मील के एरिया को १,२० हजार में उसी पार्टी को दे दिया। अगर उस एरिया की मोनोपोली को तोड कर छोटे छोटे हिस्सों में सरकार देती कानून के अनुसार तो सरकार को अधिक आमदनी होती और बहुत से लोग उससे लाभ उठाते। पर जब इस प्रकार की चीजें सरकार स्वयं चलाती है चन्द आदमियों के फायदे के लिये माइन्स रिजर्व कर देती है, दूसरों को मौका नहीं देती तो मैं यह समझता हूं कि सरकार, इस खनिज

(श्री तेजाराम गहलोत)
उद्योग से जो भी पैसा मिल सकता है, उसको लेने की कोशिश भी नहीं करना चाहती।

जहां तक डिसेन्ट्रेलाइजेशन का सवाल है, मैं यह कहने में कतई नहीं हिचकिचाऊंगा कि यह स्कीम बिलकुल ही फेल्योर हुई है और जो स्कीम फेल होती है तो या तो उसको बन्द कर देना चाहिये या नये मोड देने चाहिये। हमनें इसे इस भावना से शुरू किया कि गांव के लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने इलाके की प्रगति में और बढोतरी में योग दें। हमने उनको टैक्स लगाने का भी अधिकार दिया। पर अधिकांश पंचायत समितियों ने टैक्स नहीं लगाये। आज वित्त मंत्रीजी ने प्रावधान रखा है कि हम इस सदन के जरिये टैक्स लगाकर उनको देंगे। मैं कहता हूं कि जो संस्थायें निकम्मी हो गई हैं उनमें व्यर्थ में जान डालने की कोशिश सरकार न करे। प्रधान और उप-प्रधान को ४.१७ हजार देने का प्रावधान है, प्रमुखों के लिये ६० हजार का है और जिला परिषदों के लिये ४४० हजार की एडहॉक ग्रान्ट का प्रोविजन है और पंचायत समितियों के लिये ५ लाख का प्रावधान है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, जो इंस्टीट्यूशन अपने यहां बिलकुल फेल्योर सिद्ध हुआ है और जो गांवों के अन्दर सिवाय पार्टीबाजी बढाने के और कोई तरक्की नहीं कर सका है तो मैं चाहूंगा कि ऐसे एमरजेन्सी के समय में ऐसे एक्सपेरीमेंटल खर्चे बन्द कर देने चाहिए और जो जरूरी जरूरी स्कीम्स हों वे ही लागू की जानी चाहिए।

जहां तक सरकार की इस नीति का सवाल है कि आज जितने पिछड़े हुए इलाके हैं उनकी उतनी ही अधिक तरक्की करनी चाहिए, यह नीति भी सरकार की सफल नहीं रही है। अरबन और रूरल के अन्दर सरकार आए साल भेदभाव रखती है। जहां तक वाटर सप्लाई का सवाल है रूरल एरिया के लिए सिर्फ २० लाख रुपए रखे हैं और अरबन एरिया के लिए ९० लाख रखे हैं। इसी तरह से जहां तक ग्रान्ट-इन-एड का सवाल है अरबन एरिया में सरकार ने ज्यादा दी है और रूरल एरिया में कम दी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके जरिये जो माननीय वित्त मंत्रीजी ने टैक्स लगाये हैं उनके बारे में अपने विचार रखूंगा। जहां तक व्हीकल्स पर टैक्स लगाया है उसमें एक बात मैं यह महसूस करता हूं कि यह टैक्स वित्त मंत्री महोदय ने कोई रेशनेलाइज्ड आधार पर नहीं लगाया है। जो प्राइवेट गाडियां हैं उनके ऊपर टैक्स बढाया है वह २९ परसेंट बढाया है और जो पब्लिक केरियर्स हैं उनके ऊपर ३० परसेंट बढाया है और जो छोटी गाडियां हैं उनके ऊपर २५ परसेंट बढाया है। तो इन मोटर व्हीकल्स के ऊपर अगर ३३ परसेंट यूनीवर्सल बढा देते तो कोई अनुचित नहीं था। जहां तक राजस्थान पैसेंजर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन का सवाल है उसका जूरिस्डिक्शन अगर प्राईवेट कैरियर्स और प्राईवेट कार्स तक बढा देते तो सरकार को अच्छी आमदनी हो सकती थी। जहां तक प्राईवेट कैरियर्स का सवाल है वह या तो बड़े बड़े व्यक्तियों या मिल्स ओनर्स के हैं जिनके खुद के धंधे चलते हैं और वह इस तरह के टैक्स पे करने की क्षमता रखते हैं। मेरे ख्याल से तो कोई भी ऐसा नागरिक

(श्री तेजाराम गहलोत)

नहीं होगा जो अपना खुद का धंधा न रखता हो और अपनी प्राईवेट गाडी रखता हो। एक आदमी दो रुपया मील का किराया देकर अपना सामान ले जाता है लेकिन पाली मिल की खुद की गाडी है और वह कपास लाती है उनको एक पैसा भी टैक्स का नहीं देना पडता तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजस्थान पैसेंजर्स एण्ड गुड्स टेक्सेशन एक्ट का जूरिस्डिक्शन उन तक भी बढाने की कृपा करें। जहां तक सेल्स टैक्स का सवाल है सिवाय खाद्यान्न और लाइव स्टाक के जो सेल्स टैक्स लगाया है वह दूसरी रियासतों के बनिस्वत अपने यहां पर कम है। मैं आपके सामने निवेदन करूं कि जो स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड की गयी है उसमें राजस्थान की आमदनी सेल्स टैक्स के जरिये २.८८ है जब कि आंध्र में ३.९० है और गुजरात में ६.३० है। तो खाद्यान्न और लाइव स्टाक को छोडकर दूसरी चीजें हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स बढाया जा सकता है और बढाया जाना चाहिए। जहां तक माइनर मिनरल्स के ऊपर रायल्टी के बढाने का प्रावधान रखा है उसमें बहुत गुंजाइश है और सरकार को उसके ऊपर रायल्टी बढानी चाहिए। जहां तक लैण्ड रेवेन्यू सेस का सवाल है मैं इस सेस को, उपाध्यक्ष महोदय, उचित नहीं समझता बल्कि मैं अनुचित समझता हूं। क्योंकि जब राजस्थान में हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों से अधिक लेण्ड रेवेन्यू है और हम यह मानते हैं कि यहां का काश्तकार केवल कुदरत की मेहरबानी पर निर्भर करता है, यहां सिचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं, अकाल पडते रहते हैं, यहां प्रॉडक्शन में इतनी डिस्पेरिटी है कि कहीं कहीं एक ही जगह दो फसलें होती हैं और कही एक साल में एक भी मुहैया नहीं होती, यहां पर भूमि में तरह तरह के भेदभाव हैं ऐसी सूरत में इस इलाके में, इस प्रान्त में यह लेण्ड रेवेन्यू सेस इस मौके पर लगाना कतई उचित नहीं है। इसके बजाय मैं यह सुझाव दूंगा कि अरबन एरिया में जो प्रापर्टी है उसके ऊपर लगाने की कोशिश करें। इसके अलावा जो गांवों में और शहरों में मनी लेन्डिंग का काम करते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहां के काश्तकार बतौर ब्याज के रुपया उनसे लेते है और वह मनी-लैंडर्स न तो इनकम टैक्स पे करते हैं क्योंकि वह अनपढ लोग होते हैं, न वह हिसाब रखते हैं। ऐसी सूरत में वह इनकम टैक्स की चोरी करते हैं और उधर जनता का शोषण करते हैं। इसलिये उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि यह तीन टैक्स लेण्ड रेवेन्यू, सेस, लाइव स्टाक और फूडग्रेन्स के ऊपर आपने प्रपोज किये हैं मैं उनको अनुचित समझता हूं वह तो आप वापिस ले लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बैठता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह १९६३-६४ के बजट पर जो अब तक विचार प्रकट किये गये हैं और माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट रखा है मैं समझता हूं कि इस पर जो विचार प्रकट कर दिये गये हैं, जो सुझाव दिये गये हैं उनको मैं नहीं दोहराऊंगा। लेकिन वित्त मंत्रीजी ने जो शुरुआत की है, उस बजट भाषण में यह बताया है कि हमारे आयोजनों के लिए धन की जरूरत है और चीन के संकट के कारण

Page No.69

(श्री रामकिशन)

यह जरूरी हो गया है कि हमें धन मिले, हम कर लगायें और इसके लिए किसी तर्क की जरूरत नहीं है । वित्त मंत्री महोदय का तमाम बजट भाषण पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो टैक्स लगाये गये हैं यह इस कारण लगाये गये हैं कि आयोजनों के लिए पैसा जरूरी है और दूसरा कारण यह है कि हमारे देश पर संकट आया है इसलिये सुरक्षा के लिए पैसा चाहिए । तो जहां तक वित्त मंत्री की जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को मैं समझता हूं और यह उनका विचार सही है कि पैसे के बगैर न तो मुल्क की सुरक्षा होगी, न हमारा उत्पादन ही बढ़ेगा । लेकिन हम चाहे राजस्थान के वित्त मंत्री का भाषण पढ़ें, चाहे केन्द्र के वित्त मंत्री का बजट भाषण पढ़ें और चाहे गुजरात के वित्त मंत्री का बजट भाषण पढ़ें सभी वित्त मंत्रियों ने एक ही तरीका अपना लिया है कि विकास के लिए हमें पैसा चाहिए । मैं समझता हूं कि सारे भाषणों में इस पर जोर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह तो साधारण तर्क है कि पैसे के बगैर विकास नहीं होगा । लेकिन प्रश्न यह है कि यह पैसा कहां से आये ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या हमारे आयोजन में, हमारी योजना में तो कहीं मूलभूत कमजोरी नहीं है जिसकी वजह से जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं वह पूरे नहीं होते, जो आशायें करते हैं वह पूरी नहीं होतीं ? एक तरह से इस सारे बजट भाषण को पढ़ने के बाद और आयोजनों पर जो वित्त मंत्री महोदय के विचार हैं उनके ऊपर विचार करके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ लक्ष्य निर्धारित किये थे । हमने चाहा था कि सारे देश में पहली पंचवर्षीय योजना में हमारी राष्ट्रीय आय १५ परसेन्ट बढ़ जाये, दूसरी पंचवर्षीय योजना में वह २२ परसेन्ट बढ़ जाय और बड़ा लक्ष्य यह रखा गया कि १९७२ तक हर नागरिक की आय, चाहे वह राजस्थान का हो चाहे भारतवर्ष व अन्य राज्य का हो, उसकी आमदनी दुगुनी हो जाय । हम सोचते थे कि यह लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया तो हम तरक्की के रास्ते पर पहुंच जायेंगे । वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में इसी बात का जिक्र किया है कि राजस्थान विकास कर रहा है । इसके बारे में कहीं तो उन्होंने संतोष व्यक्त किया है और कहीं असन्तोष व्यक्त किया है, कहीं आगे बढ़ने का विश्वास दिलाया है । इसी इसी तरह के फिकरे हैं जिससे मैं उनकी मनोदशा को समझ गया हूं, लेकिन एक चीज जिसकी तरफ मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान दिलाऊंगा वह यह है कि यह हालत जो आपने पैदा की है आप लगातार टैक्स लगा रहे हैं सन् १९५१ से आपकी योजनायें चल रही हैं और आज सन् १९६३ है ११ साल हो गए लेकिन जो आपने अन्दाजा लगाया है सरकार को उतना रिटर्न क्यों नहीं हो पाता ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट निवेदन कर दूं कि वित्त मंत्री महोदय ने संतोष व्यक्त किया है लेकिन मैं सारे देश के हिसाब से और राजस्थान के हिसाब से उनके सामने एक चित्र रखता हूं । हमारे विकास की गति संसार के सभी देशों से कमजोर है । गोरे मुल्क तो एक आदमी के पीछे १५० से २५० रुपये बढ़ा रहे हैं । लेकिन अगर हम काली और रंगीन दुनियां को भी देखें इस कन्टैक्स्ट में हिन्दुस्तान की योजना के कन्टैक्स्ट में घाना एक देश है जो कि प्रतिवर्ष २५ से ३० रुपये प्रति व्यक्ति अपनी आमदनी बढ़ा रहा है । और चीन जैसे देश ने ६०) और ७०)

Page No.70

(श्री रामकिशन)

रु० आमदनी बढाई है। लेकिन हिन्दुस्तान की हालत यह है कि एक व्यक्ति की आमदनी केवल ८ रु० प्रति वर्ष बढी है और इस पर भी योजना आयोग और वित्त मंत्री संतोष करते हैं तो मैं कहूंगा कि न तो हम चीन के आक्रमण से देश को बचा सकते हैं और न ही हम देश को भर पेट रोटी दे सकते हैं। इस सबसे बडी कमजोरी की तरफ जब तक योजना आयोग और हिंदुस्तान के विचारकों का दिमाग नहीं जायगा तब तक मामला पार होने वाला नहीं है।

दरअसल में हमारी कमजोरी क्या है? इस बारे में हमारे यहां के जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं उन्होंने कुछ बातें कहीं मैं उनमें नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा कि हमारी आयोजना ठीक है लेकिन उसको क्रियान्वित करने का तरीका ठीक नहीं है। मेरा इस संबंध में निवेदन है वह यह है कि हमारा आधार भी गलत है और उसको कार्यान्वित भी गलत ढंग से किया जाता है। दूसरी बात यह है कि हिन्दुस्तान की सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो उनका पूंजीवादी उत्पादन का तरीका है। समाजवादी उत्पादन प्रणाली को बिना लाये यह कार्य चल नहीं सकता। क्योंकि यदि हम यूरोप और इंगलैन्ड की तरफ का तरीका अपनाने की सोचेंगे तो सोचना पडेगा कि वहां एक आदमी के पीछे क्या खर्चा होता है। हमने हमारी तीसरी योजना में २ अरब ८ करोड का प्रावधान किया है, विकास में इतना खर्चा पडेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि राजस्थान में एक नागरिक के लिये १००) दे रहे हैं उत्पादन के लिये जब कि हिन्दुस्तान में एक आदमी के पीछे १५०) रखे हैं। मैं बाहर के देशों की बात तो छोडता हूं लेकिन राजस्थान में जो १००) की व्यवस्था है वहां हमारी गति निश्चित तौर से कमजोर होगी।

एक दिक्कत हमारे सामने और आ रही है योजना कमीशन ने भी यह बात साफ नहीं की है, वह यह है, कि हमारे देश में श्रम शक्ति है, श्रम है लेकिन पूंजी निर्माण की गति धीमी है। जैसा कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना में कहा है हमारी इच्छा है कि ६ परसेन्ट पूंजी निर्माण करें और उसे नये उद्योगों में लगादें यह इच्छा व्यक्त की है लेकिन इतनी पूंजी लग नहीं पाती। हमारे बचत की रफ्तार अन्य प्रदेशों से, आसाम को छोड कर, सबसे कम है। यदि इस योजना की रफ्तार में सबके साथ चलना है तो हमें दो बातों की ओर जोर देना पडेगा एक तो प्रति व्यक्ति पूंजी की राशि बढानी पडेगी, ज्यादा इन्वेस्टमेन्ट करना पडेगा-पर अमेरिका, यूरोप और कम्युनिस्ट मुल्कों की तरह नहीं। हमको इस तरह से चलना पडेगा जिससे कि छोटी मशीनें ज्यादा लगा सकें और ज्यादा आदमियों को काम पर लगा सकें। ये दोनों हालतें हिन्दुस्तान और खास कर राजस्थान मे हैं जो भी आमदनी का जरिया है, राजस्थान सरकार उसको बढाने की कोशिश नहीं करती। राजस्थान सरकार के कई वित्त मंत्री आये, मौजूदा वित्त मंत्रीजी ने बजट रखा है, उनसे पहले के जो वित्त मंत्रीजी थे उन्होंने भी जो बजट रखा था और उनसे पहले के वित्त मंत्रीजी ने भी जो बजट रखा था उन सब में दो बातें पकड रखी थीं--एक तो मोटरों पर टैक्स लगा देना और दूसरे सेलस टैक्स बढा देना। कभी उनका दिमाग इस बात

(श्री रामकिशन)

की ओर नहीं जाता है कि राजस्थान में कौन से सींगे से कितनी आमदनी हो सकती है, खानों से कितनी आमदनी हो सकती है, पशुधन से कितनी आमदनी हो सकती है। मैं एक ही बात बता देना चाहता हूं। ४ करोड़ के नये टैक्सेज लगाने के लिए वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा है। उनके शब्दों में यह समस्या उन्हीं ने ही पैदा की है, कांग्रेस शासन के कुशासन का प्रभाव है कि लगातार टैक्स बढाते जा रहे हैं। जब इस प्रकार की समस्या उनके सामने है तो हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। वे पशुधन बढाने के लिये कोशिश करते तो हमको ४ करोड रुपये पशुधन से मिल सकते हैं। आज अंदाज यह है कि हमारे पशुधन से ७६ करोड रुपयों का उत्पादन राजस्थान में होता है, यह मोटी बात है। यदि मुख्य मंत्रीजी कांग्रेस की पार्टीबाजी से अपना दिमाग हटा कर पशुधन के विकास के लिए प्रयत्न करते तो टैक्स लगाने की की जरूरत ही नहीं पडती।

इसी तरह से उड़ीसा और राजस्थान हिन्दुस्तान में दो ऐसे प्रान्त हैं जहां असीम खनिज सम्पदा है। यदि आगामी चार वर्षों में खानों की ठीक तरह से व्यवस्था हो सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट के बजाय सरकार सब खनिजों को अपने हाथ में ले ले तो ४ करोड रुपये अकेले खनिज विभाग से हमको मिल सकते हैं। मेरा अनुमान है कि पशुधन, वन संपदा और खनिज संपदा इन तीनों के विकास के लिए राजस्थान सरकार अपना इरादा पक्का बना ले तो इस योजना में ही नहीं बल्कि चौथी योजना में भी राजस्थान सरकार को टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पडेगी। जैसा कि अभी अभी मुरारजी ने कहा है हर साल टैक्स बढाने पड़ेंगे तो सरकार यदि इन मामलों में सतर्क हो जाय तो चौथी योजना में भी टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पडेगी। एक तरीका यह है जो समाजवादी समाज के लिये आसान है लेकिन मुश्किल यह है कि भाषण में मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी समाजवादी समाज का नाम छोड़ेंगे नहीं। भाषणों में समाजवाद का नाम और गांधीवादी सिद्धान्तों का नाम लेते हैं लेकिन उनके जो कर्म होते हैं वे पूंजीवादी तरीके के होते हैं। यह हमारा देश राजनीतिक, आर्थिक और इकॉनॉमिक मामलों में पूंजीवादी तरीकों पर चलता है। वित्त मंत्रीजी ने कहा कि टैक्स लगाना जरूरी है लेकिन यह समझ में नहीं आता कि समाजवादी सरकार कैसे टैक्स लगावे। वित्त मंत्रीजी फरमाते हैं कि हम टैक्स केवल धन प्राप्त करने के लिये ही नहीं लगाते हैं बल्कि इसलिये लगाते हैं कि गरीब और अमीर में भेद कम हो। वित्त मंत्रीजी नहीं मानेंगे और मुख्य मंत्रीजी तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे और अपने भाषणों और वक्तव्यों में समाजवादी समाज बनाने का नाम अवश्य लेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके टैक्स लगाने से अमीर और गरीब में भेद कम हुआ है? मैं बता दूं कि आपने टैक्स क्यों लगाया है, मैं ६ एकड़ जोत पर टैक्स न लगाने के मामले में बोल चुका हूं इसलिए मैं इस मामले में ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। लेकिन आप जो टैक्स लगाने जा रहे हैं उसका इफैक्ट किस पर पड़ेगा?

इन ४ करोड़ के टक्सों का भार गरीब किसानों पर पड़ेगा। आपने तो अनाज पर भी

Page No.72

(श्री रामकिशन)

टैक्स लगाया है। गरीब किसान साल भर तक अनाज इकट्ठा करके नहीं रख सकते। राजस्थान में ७० लाख किसान हैं जो अपना अनाज साल भर में सहूलियत के अनुसार बेचते थे लेकिन अब उनको फसल के समय सस्ते भाव में अनाज बेचना पड़ेगा। आपने अनाज पर टैक्स लगाया है। बाजरा और मक्का पर टैक्स लगाया है। इस टैक्स के द्वारा आप गरीब को और गरीब बनाना चाहते हैं। राजस्थान को भू-राजस्व से ८।।। करोड़ रुपये वसूल होते हैं उसका एक चौथाई कर और बढा दिया इसका मतलब यह हुआ कि १५ लाख जोत के किसानों को २ करोड़ रुपये और देने पड़ेंगे। ये २ करोड़ रुपये गरीब किसान कहां से प्राप्त करेंगे। समाजवाद का जो खास लक्ष्य अमीर और गरीब के बीच के भेद को कम करना होता है वह इससे नहीं होगा। पैसा छोटे लोगों से लेते हैं, गरीबों से और गांव के किसानों से लेते हैं व मजदूरों से लेते हैं लेकिन उसका लाभ कहां पहुंचता है। आपने योजना में बताया कि सारे देश में १००० करोड़ रुपये हमने मकानों पर खर्च किये हैं लेकिन आप इससे संबंधित रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका तीन चौथाई भाग अफसरों के बंगलों पर खर्च हो गया है। पैसा लिया गरीबों से, किसान और मजदूर क्लास से और जो लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं उनका एक बडा वर्ग पैदा हो गया है उनके लिये सारे साधन जुटाते चले जा रहे हैं पैसा गरीबों से वसूल करते हैं और उसका फायदा मालदारों को पहुंचता हैं। वित्त मंत्रीजी पैसा टैक्स का फिर लेलें लेकिन भाषण में ये जो शब्द लिखे गये हैं कि दूसरा लक्ष्य अमीर और गरीब के भेद को कम करने का है कम से कम इस जुमले को अपने भाषण से निकाल दें तो अच्छा होगा क्योंकि दूसरे लोग इस बात को मानेंगे नहीं इसलिये आप इस जुमले को निकाल दें ताकि समाजवाद के बारे में भ्रान्त धारणा नहीं फैले।

जहां तक पैसे का जिक्र किया है मैं और मेरी पार्टी कई बार कह चुके हैं कि अमीर क्लास पर इसका भार नहीं डालेंगे दो ढाई लाख लोगों की एक नई क्लास बन गई है उनमें वितरण नहीं करेंगे और गरीबों में वितरण करेंगे। इसका कोई परसेन्ट निकालने वाला नहीं है। राजस्थान की आमदनी, सारी आमदनी और खर्च मिला कर देखें तो राजस्थान में ढाई तीन लाख लोग हैं, चाहे वे सरकारी अफसर हों, चाहे वे मंत्री हों, चाहे विधान सभा के मेम्बर होंगे—जिनका एक बडा वर्ग बन गया है इस देश में, उनकी सुख-सुविधा में सारा पैसा खर्च हो जाता है जो पैसा गरीबों से आता है जो अपनी बात को कह नहीं पाते हैं और इनकी बात को समझ नहीं पाते हैं। यह ऊंचा वर्ग, ऊंची जाति, अंग्रेजी भाषा बोलने वालों, गला लंगोट पहनने वालों, टाई वाली जाति पैदा हो गई है। सारे देश का पैसा उनके पास चला जाता है। लेकिन मुश्किल यह है कि हमारे मंत्री हैं वे आज से दस साल पहले गांधीवादी थे, या जवाहरवादी थे या सुभाषवादी थे—यह मुझे पता नहीं, कोई वादी रहे हों लेकिन अब सेक्रेटेरियट में बैठ कर किसी सेक्रेटरी को टेलीफोन करते हैं और सुनते हैं—हुजूर, हुक्म। तो इस हुक्म की वजह से सोचते हैं हमारा यही स्थान है और जो

(श्री रामकिशन)

सेक्रेटरी ने सलाह दे दी है वह वाजिब है। लेकिन आप ऐतिहासिक महत्व के लोग नहीं हैं क्योंकि पांच साल से ज्यादा आपकी गद्दी सुरक्षित नहीं है। इसलिये आपकी वही जगह होनी चाहिए जहां से आप निर्वाचित होकर आये हैं। वहां नजर नहीं रखेंगे और अपने सेक्रेटरियों के जो चमत्कारपूर्ण शब्द हैं हुक्म, जो हुकुम, यस सर–इनको भूल कर वहां नहीं जायेंगे तो आपके यह आयोजन अधूरे रहेंगे और वे वास्तव में हिन्दुस्तान को ऊंचा नहीं उठाने वाले, गरीबी को नहीं मिटाने वाले और समाजवाद का गला घोंटने वाले होंगे। यह पहली स्थिति है, जो मैं निवेदन कर देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को।

दूसरी स्थिति यह देखता हूं कि सरकार अपने पुराने कर्ज वसूल नहीं करना चाहती है। आज से कुछ दिन पहले इस सदन में एक प्रश्न पूछा गया था कि खानों पर कितना बकाया है ? हमारे वित्त मंत्रीजी कहते हैं कि हमें पैसा लाने की जगह बताओ। उनको मैं जगह बताता हूं कि उस प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि करीब ६१ लाख रुपया खानों के मालिकों पर सरकार का बकाया है। अब इसमें से यह भी मान लें कि करीब २० परसेन्ट झगडे-तलब होगा, और दो, पांच प्रतिशत ऐसे भी लोग भी होंगे, जिनकी आर्थिक हालत खराब हो, जो बकाया देने लायक नहीं हों तो भी पैंतीस, चालीस लाख रुपया आप वसूल कर सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप उनसे वसूल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ? अगर आप उनसे वसूल करेंगे तो किसी न किसी का आपके पास टेलीफोन आ जायगा, दबाब आ जायगा, जिन्होंने चुनाव के लिये आपको चन्दा दिया है, कि इस पार्टी को छोड दीजिये और हो सके तो किसी दूसरी पार्टी से ले लो। ऐसी स्थिति में आप राजस्थान का निर्माण कैसे करेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता ? आप बकाया रकम वसूल नहीं चाहते, जमीदारों और जागीरदारों को मुआवजा देना बन्द करना नहीं चाहते, राजाओं की पेंशन को कम करना नहीं चाहते, पांच लाख माहवार जागीरदारों को देना बन्द करना नहीं चाहते-इन सारी बातों को आप करना नहीं चाहते, और फिजूल खर्ची को घटाना नहीं चाहते। अभी बम्बई में अर्थ शास्त्रियों का सम्मेलन हुआ, उसमें उन्होंने सुझाव दिया। वह सुझाव यह था कि प्रशासन में अगर २० प्रतिशत की कटौती कर दी जाय तो बजट में ८ अरब की बचत कर सकते हैं। भारत की सुरक्षा के लिए जो आठ अरब की जरूरत है, उसके लिये उन्होंने सुझाव दिया है कि टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। आज हिन्दुस्तान और राजस्थान सरकार और सारी सरकारें ग्यारह करोड रुपया रोज खर्च कर रही हैं। उस ग्यारह करोड रुपये में से अगर २० प्रतिशत की कटौती कर दी जाय तो हमें देश की सुरक्षा के लिये पैसा मिल जायगा और नये टैक्स हमें नहीं लगाने पडेंगे ......

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : जो लोग बेकार हो जायेंगे उनका क्या होगा ?

श्री रामकिशन : आप सुनते जाइये। आप बेकार नहीं होने वाले हैं। सुनिये आप। आप डरते क्यों हैं, सरकार आप पर हाथ नहीं डालना चाहेगी।

तो माननीय सदस्य ने पूछा कि जो बेकार हो जायेंगे, उनका क्या होगा आप क्या समझते हैं कि हमें उसकी चिन्ता

(श्री रामकिशन)

नहीं है ? क्या आपके ही आदमी बेकारी के शिकार होंगे, हमारे नहीं होंगे ? आपके जो बेकार होंगे, वे तो तब भी आपकी सिफारिश से बच जायेंगे । लेकिन, खैर, मैंने उसका भी इलाज सोच रखा है । मेरे सुझाव आप मान लें, जो अर्थ शास्त्रियों ने सुझाव दिये हैं उन्हें मान लें, तो लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य के रिश्तेदार तो वैसे ही बच जायेंगे, क्योंकि वे उनकी लिस्ट दे देंगे कि इनको नहीं हटायें, इनका नम्बर नहीं आये । लेकिन जो बाकी के बच जाते हैं उनके लिए मैं यह सुझाव देता हूं, कि आपको शिक्षा का प्रसार करना है, आपको राजस्थान के निर्माण के लिये टैक्निशियन चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन योजनाओं में नई भर्ती करके इन लोगों को काम दिया जा सकता है । यह रोजगार देने का एक तरीका है । इसके अलावा मैं निवेदन कर दूं कि बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिया जा सकता है, इसके लिये दूसरे भी तरीके हैं जिनको अपना कर बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं । इससे योजना के लिये पैसा भी बचा लेंगे, जनता के ऊपर टैक्स नहीं लगेंगे, और सुरक्षा के लिये भी पैसा दे सकेंगे । सिर्फ वित्त मंत्री महोदय को साहस से काम लेना चाहिये । सदन के सदस्य कह रहे हैं कि वित्त मंत्रीजी साहसी हैं, किसी ने कहा है वित्त मंत्रीजी को कृपा की जरूरत नहीं है, इसलिए किसी की परवाह नहीं है, किसी की चिन्ता नहीं है इसलिये वित्त मंत्रीजी जो चाहें कर सकते हैं । यह मेरी जानकारी में नहीं कि वित्त मंत्री जी जवाहर लाल नेहरू की वजह से आये हैं, या मुरार जी भाई की दुहाई देकर आये हैं या उन्हें सुखाडियाजी बुला कर लाये हैं, मुझे इसका पता नहीं लेकिन इतना मालूम पड़ता है कि हमारे वित्त-मंत्री में साहस है । और जैसा मैंने पहले कह दिया कि हमारे सदन के नेता में साहस नहीं है इसलिए वित्त मंत्री जी साहस दिखायें । मैं उनको कहता हूं कि आप एक परम्परा बना दीजिये, आप वित्त मंत्री तो पांच साल रहेंगे, शायद वित्त मंत्री के रूप में आपका नाम याद नहीं रहेगा । वैसे कौल साहब को सब जानते हैं । आपके त्याग और साहस के लिए सब जान पायें, इसके लिए आप इस बात पर अड़ जाइये कि आप किसान से कोई टैक्स नहीं लेंगे, अनाज पर आप टैक्स नहीं लेंगे । जिनकी आमदनी ज्यादा है, जो बड़े बड़े लोग हैं इनसे ही आप टैक्स वसूल करेंगे । इस तरह की कार्यवाही करना शुरू करें और इस तरह का प्रयास करें तो राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान का कल्याण होने वाला है । वैसे यह देखते हैं कि सरकार की सारी कार्यवाही और योजना में कोई सामंजस्य नहीं है । इसलिए जो सुझाव जयपुर से आने वाले और आमेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने दिये हैं कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स और तहसीलों को कम कर सकते हैं, और २० परसेन्ट प्रशासन में कटौती करने का सुझाव अर्थशास्त्रियों ने दिया है-इनमें कमी करके उससे बचत कर सकते हैं ।

इसके अलावा चूंकि शिक्षा के बारे में अलग से बहस नहीं होगी, इसलिए मैं शिक्षा के संबंध में निवेदन कर देना चाहता हूं । इस संबंध में कहा गया है कि हम तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो सैंकड़ों वर्षों से पिछड़े हुए थे, उस क्षेत्र में अब आगे बढ़ जायेंगे । एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्राईमरी स्कूल अब खोले न जायं । उन्होंने कहा,

(श्री रामकिशन)

वह भी सच कहा और हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा वह भी सच कहा। मेरा निवेदन है कि शिक्षा के मामले में कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं की जानी चाहिये। जहां तक यह बात है कि कोई प्राईमरी स्कूल किसी मंत्री के कहने से या किसी एम. एल. ए. के कहने से खोल दिया गया है और उसमें फिजूलखर्ची हो रही है तो उसको भले ही हटा दें। लेकिन राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है, यह मेरा एक सुझाव है। दूसरा सुझाव मैं यह देता हूं कि बेकार लोगों को रोजगार देने के लिए एक निरक्षरता विरोधी सेना की भर्ती की जानी चाहिये जिस तरह से आज जर्मनी ने किया, स्विटजरलैंड ने किया कि लोगों को सौ रुपये तनख्वाह पर भर्ती कर लिया और उस सौ रुपये में से पचास रुपये उनको दे दिये और पचास रुपये के बौंड दे दिये। इस तरह जर्मनी का निर्माण हो रहा है और इसका नतीजा क्या हुआ कि वहां की सारी जनसंख्या शिक्षित हो गई ......

श्री मानसिंह ग्हार (आमेर): कौन सी जर्मनी ?

श्री रामकिशन: वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी की बात मैं नहीं कर रहा हूं जहां ऐसी स्थिति है।

इसलिए इस सुझाव को मान कर आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं और साथ ही साथ शिक्षा का प्रचार भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने शिक्षा के संबंध में यह बताया है कि शिक्षा पर हम २० प्रतिशत खर्चा कर रहे हैं। यह बिल्कुल सही बात है। लेकिन चूंकि शिक्षा मंत्री यहां नहीं है, इसलिए इस संबंध में मैं अधिक निवेदन नहीं करना चाहता सिर्फ इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप शिक्षा संस्थाओं की संख्या बढ़ाने पर ही संतोष प्रकट न करें, जैसा कि आपने गिनाया-इतने प्राइमरी स्कूल खोल दिये हैं, इतने मिडिल स्कूल खोल दिये हैं, इतने हायर सैकेन्डरी स्कूल खोल दिये हैं। यह संख्या आपको जरूर बढ़ी है लेकिन संख्या के साथ साथ गुण बढ़ाने पर जोर नहीं दिया जा रहा है। मैं अपने मित्र के यहां आदर्श नगर रोटी खाने जाता हूं। वहां मैंने परसों एक इतिहास देखा, जो सातवीं कक्षा में पढ़ाया जाता है। उनकी लड़की सातवीं कक्षा में पढ़ती है। उसे देख कर मुझे ताज्जुब हुआ। पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हो गया है, और किताब स्वीकृत करने के लिए बोर्ड बने होंगे लेकिन उसमें लिखा है— राजस्थान पर मुगलों ने हमला कर दिया। मैं नहीं कहता कि मुगलों ने हमला नहीं किया। लेकिन वे कौन मुगल थे ? आज हमें इतिहास नये ढंग से बताना पड़ेगा। एक मुगल बाबर था, जो विदेशी था। एक मुगल अकबर था जो इस देश का था। हमें अगर राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना है, राष्ट्रीय विचारधारा को पक्का करना है तो यह बात हिन्दुओं को साफ करनी पड़ेगी कि अकबर, रजिया बेगम, टीपू सुल्तान हिन्दुस्तान के थे और हमारे पुरखे थे इसी प्रकार देश के मुसलमानों को बतलाना होगा कि बाबर, गोरी, गजनी, विदेशी आक्रमणकारी थे। इस तरह से जब तक हम बात साफ नहीं करेंगे, इस तरह का इतिहास का निर्माण नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रीय निर्माण का कार्य अधूरा रह जायगा।

इसके अलावा अगर राष्ट्रीयकृत पुस्तकों में गलतियां देखी जायं, तो वैसे तो हमारे उप शिक्षा मंत्री भी करीब करीब शिक्षा शास्त्री

(श्री रामकिशन)

हूं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें लिखा गया है- मत्स्य की राजधानी धौलपुर थी। इस तरह के इतिहास का क्या ज्ञान करा रहे हैं। जबकि मत्स्य की राजधानी अलवर थी, उस किताब में लिखा है कि मत्स्य की राजधानी धौलपुर थी। इसी तरह की किताबें स्कूलों में चलती हैं। मैं समझता हूं कि हम जो जोर दे रहे हैं कि संस्थाओं की संख्या बढे, उसके बजाय गुण बढाने के ऊपर जोर दें और देश का निर्माण नये ढंग से करें। इसी तरह अनुशासन का मामला है, जो देश का निर्माण करने के लिये आवश्यक है। हमने समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य निश्चित कर दिया लेकिन समाजवादी समाज क्या है, यह आपके मास्टरों को पता नहीं है। जब कि दूसरे मुल्कों में जिस विचारधारा को स्वीकार किया जाता है, जबरदस्ती की बात नहीं करता, मैं रूस और चीन की बात भी नहीं करता; लेकिन दूसरे मुल्कों में वहां की विचार धारा का साहित्य दिया जाता है। समाजवादी व्यवस्था क्या है, समाजवाद में शिक्षा कैसी होगी, समाजवादी समाज में शादी कैसे होगी, समाजवाद में खेत कैसे होंगे-इस सबको जानकारी करानी होगी। आज अगर किसी मंत्री के भाषण में समाजवाद का नाम आ गया तो उन्होंने समझ लिया कि समाजवाद सब जगह आ गया। मैं समझता हूं कि जब तक हम इस तरह का साहित्य सृजन नहीं करेंगे तब तक लोगों के अन्दर समाजवाद के प्रति एक विचारधारा नहीं बना सकते हैं, एक विश्वास पैदा नहीं कर सकेंगे। इस तरह का प्रयास शिक्षा के अन्दर करना चाहिये। इस तरह का प्रयास नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम राष्ट्र निर्माण करने की अधूरी कोशिश कर रहे हैं और इससे हमारे मुल्क का कल्याण नहीं होने वाला है इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। हो सकता है कि इससे लोगों को अक्षर ज्ञान हो जाय लेकिन आपका आयोजन नाकामयाब हो रहा है, असफल हो रहा है। इसका कारण क्या है, मैं उसे छोड देता हूं मैं मास्टरों की बात नहीं करता मैं दूसरों की बात नहीं करता लेकिन आपके सचिवालय में जो सचिव बैठे हैं, जो कलेक्टर बैठते हैं, जिनसे आप अपनी नीति पूरी कराना चाहते हैं, उनसे पूछा जाय कि समाजवाद का अर्थ क्या है, तो वे हंस जायेंगे। एक कलेक्टर साहब हैं, उनका नाम मैं क्यों लूं, वे मेरे परिचित हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा-यह बच्चों का खेल है। पता नहीं समाजवाद क्या है। अब आप सोचिये कि जहां कलेक्टर और नाजिम इस तरह का उत्तर देते हों तो दूसरों से क्या उम्मीद की जा सकती है।

श्री रामकिशन (लुणकरणसर) : यह आपकी पार्टी की कमजोरी है।

(३.० म० प०)

श्री भीमसेन : मेरी पार्टी का नाम तो यों ही बेकार में ले रहे हैं।

तो मेरा शिक्षा शास्त्रियों से अनुरोध है कि वे पहले साहित्य का निर्माण करें यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि आप इस तरफ अधूरा प्रयास कर रहे हैं।

टैक्सेज के बारे में यह निवेदन कर दूं कि आपने जमीन पर टैक्स लगाये हैं और कांग्रेस पार्टी में जहां तक हमारी जानकारी है, कुछ लोगों ने इस टैक्सेशन का विरोध किया है। मैंने स्टेट्समैन आदि पत्रों में पढा है कि कांग्रेस के ३६ या ३२ विधान सभाई सदस्यों ने इसका विरोध किया है मगर मैं यह कहूंगा कि कांग्रेस में कोई जीवन नहीं है यह तो एक प्रकार की मृत प्राय

Page No.77

(श्री रामकिशन)

संस्था रह गई है। आप जानते हैं कि निश्चित तौर से गुजरात सरकार ने भी जमीन पर टैक्स लगाया था और जब उसका विरोध हुआ तो उन्होंने जमीन पर से टैक्स को हटा लिया। आपके पडोसी राज्य पंजाब ने भी टैक्सों में, जो जमीन से लिए जाते हैं उसमें मिर्चों की पैदावार होती है उस पर और ईख पैदा होती है उस पर कुछ टैक्स रखा है बाकी पर नहीं। मगर राजस्थान सरकार की यह हालत है कि चाहे बाजरा, ज्वार, मक्की पैदा हो या चाहे उस जमीन में घास ही पैदा क्यों न हो वह तो २५ प्रतिशत लगान ले लेगी। मैं आपके सामने पंजाब और गुजरात सरकार के उदाहरण पेश करता हूं कि पंजाब सरकार और गुजरात सरकार ने सारे जमीन के टैक्स वापिस ले लिये हैं और अगर आप भी अपना नाम इतिहास में ठीक ठीक लिखवाना चाहते हैं तो आपने भी यह जो जमीन पर टैक्स लगाया है उसको दुरुस्त कर लें। आपने यह मान लिया है कि १५ एकड जमीन हो उस पर टैक्स लगाया जावेगा चाहे वह जमीन कैसी भी क्यों न हो चाहे वहां पर घास ही पैदा क्यों न हो चाहे कचरे ही पैदा क्यों न हो। हम अभी गंगानगर गये थे। मैंने तो कम से कम वहां एक बात देखी, वहां जमीन में कचरे पैदा होते हैं क्या आप उस जमीन का भी लगान लेंगे। इसलिए मैं एक निवेदन करूंगा कि जिस जमीन में कुछ नहीं पैदावार होती है उस पर कोई लगान नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): लगान है।

श्री रामकिशन: दूसरा सिद्धान्त यह है कि फिजूलखर्ची को रोकना चाहिये। मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया है कि एक फ्रेन्च कम्पनी है उसको एक लाख रुपया का भुगतान विदेशी मुद्रा में सोडा एश के लिये दिया गया है। उसने यहां क्या काम किया है यह मालूम नहीं। मैंने सुना है कि भारत सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मंत्री हैं उनकी इसमें दिलचस्पी थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): कोई भारत सरकार के मंत्री की दिलचस्पी का प्रश्न नहीं है।

श्री रामकिशन: मेरी जानकारी में आया और मैंने आपसे अर्ज किया है। मैंने कोई आपको परेशान करने के लिये नहीं कहा है जिस प्रकार आपको दूसरे परेशान करने के लिये कहते हैं। मैं परेशान नहीं करता हूं। मैंने यह सुना कि उसको सोडा एश के लिये एक लाख रुपया मिला है। जिस समय हमारे चीफ मिनिस्टर यह कहेंगे कि यह सूचना गलत है, मैं उसे एक दम वापिस ले लूंगा और अगर चीफ मिनिस्टर कहते हैं वह सत्य है तो सत्य मान लूंगा।

हमारे मुख्य मंत्री इन्डस्ट्रीज के भी मिनिस्टर हैं इसलिये मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में पीतल और तांबे के काम करने वाले हैं उनको पीतल बनाने के लिये तांबा और जस्त का जो कोटा दिया जाता है इनकी संख्या १ से ५ के आस पास है यह सुना है कि यह किसी रोलिंग मिल के लिये दे रहे हैं। उसको १८ लाख का नफा होता है एक साल में। उनका यह कहना है कि आपको सर्किल सीट मिलेंगे। ढलाई का काम रोलिंग मिल से होगा। इससे बहुत से दूकानदार बेकार हो जावेंगे और बहुत

(श्री रामकिशन)
से दुकानदारों ने आपके पास रिप्रेजेन्टेशन भेजा है। जिस समय भरतपुर में उप-मंत्री, उद्योग आये थे उनको बताया गया था कि जो चीज ४.७७ पैसे में मिल देगी वह दुकानदार ३.८७ पैसे में देने के लिये तैयार हैं। यह कोई जोधपुर की रोलिंग मिल है। इससे १०५ लोगों का रोजगार छिन जाएगा और ५ आदमियों के हाथ में आ जायगा। इसलिये उसके संबन्ध में भी सरकार को सोचना और समझना चाहिये।

फाइनेंस मिनिस्टर ने सेल्स टैक्स बढ़ाया है, उसके लिये कोई विशेष जानकारी उनको नहीं है। उन्होंने कहा तिलहन की पैदावार बढ़ी है जिससे विदेशी मुद्रा देश को मिले। यह कहां बढ़ी है। अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर में बढ़ी है। मगर मैं यह कहूंगा कि सरसों की पैदावार अलवर और भरतपुर में तो घटी है। भरतपुर में पानी ज्यादा आता है इस कारण वहां सरसों की पैदावार घटी है। मैं यह कहूंगा कि अब जो टैक्स लगाये जावेंगे, उनसे उनके यहा से बाहर के जो व्यापारी लोग खरीद कर ले जावेंगे उनको दो परसेन्ट टैक्स देना होगा। मिल मालिकों को ३ परसेन्ट देना होगा। तेल बेचेगा तब भी टैक्स देना होगा और सरसों पर भी उनको टैक्स देना होगा। उनको दो परसेन्ट देना होगा। बिजली की रेट यहां ज्यादा है इसलिए भी यहां के व्यापारियों को ज्यादा रेट देनी होगी और बाहर के लोगों को कम रेट देनी होगी। इसलिए जितना यहां श्रम लगेगा उसका लोगों को फायदा नहीं होगा। सीधा बाहर के व्यापारी खरीद कर ले जावेंगे और जो तेल बना कर भेजेगा उसको फायदा नहीं होगा। भरतपुर जिले में जानकारी की है यहां १० लाख मन सरसों का तेल हर साल निकलता है और बाकी की सरसों बाहर चली जाती है। कलकत्ता आदि स्थानों को जाती है। यहां के मिल्स सेल्स टैक्स के कारण बन्द हो गये हैं और हमारी सरकार ने इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया।

एक बात मैं केवल जानकारी के लिये पूछना चाहता हूं कि फाइनेन्स मिनिस्टर ने यह कहा कि लग्जरी गुडस पर १० प्रतिशत टैक्स बढा दिया गया है। संभव हो तो यह २० परसेन्ट लगे मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि मेरे एक ऑस्ट्रेलियन मित्र हैं पीटर उनकी पत्नी ने मुझे एक बात पूछी है। उसने मुझे पत्र में लिखा है, उसके लिये पूछना चाहता हूं..

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा): कह दीजिये हमारी तो कोई सुनता नहीं। हमारा कोई संबन्ध नहीं है।

श्री रामकिशन: ये टैक्सेज तो अब लगे हैं। मगर हमारी जान-पहिचान बहुत समय से है। हम इलाहाबाद गये थे तब से है। उसने पूछा काजल की शुरूआत कहां से हुई है। उसको कोई थिसिस लिखने का शौक है। उन्होंने कहा कि यूरोपियन समाज में काजल और साड़ी हिन्दुस्तान की नई देन है तो आपने कोई काजल को भी उसमें शुमार नहीं किया है। क्योंकि भारतीय संस्कृति मे काजल तो सुन्दरता को बढाने वाला है। मैंने सूची नहीं देखी है कि किन किन चीजों पर यह लग्जरी टैक्स लगा है। मैं फाइनेन्स मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर बड़े लोगों पर टैक्स लगावें तो उससे ज्यादा आमदनी हो सकती है। इसके अलावा पुरानी बकाया को जरूर वसूल

Page No.79

(श्री रामकिशन)

करें चाहे चीफ मिनिस्टर की सिफारिश की चिट्ठी भी उसको रोकने के आए तो भी बकाया को अवश्य वसूल करें। पूंजी वाद और सम्यवाद जीवन नहीं, दे सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अभी साम्यवादी दल के एक माननीय सदस्य ने जवाहरलालजी का उदाहरण देकर यहां कहा था कि क्रांति हो जावेगी। जवाहरलाल नेहरू के प्रति हमारे दिलों में बहुत सम्मान है आज मगर जवाहरलालजी के कारण ही हमको डंडे खाने पड रहे हैं। आज उनकी इच्छा के अनुसार कार्य होता है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों में अलिखित समझौता हो गया।

एक माननीय सदस्य : स्वतन्त्र पार्टी से हुआ है।

श्री रामकिशन : समझौता, मैं समझता हूं कि कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीच हुआ है। यह अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है। कम्युनिस्ट इस बात को जानते हैं कि जब तक कांग्रेस का राज्य रहेगा तब तक गरीबी और भ्रष्टाचार दूर नही होंगे और कम्युनिस्टों को क्रांति की संभावना रहेगी। इसीलिये कॉम्युनिस्ट हमेशा कांग्रेस का समर्थन करते हैं। कांग्रेस वाले भी जानते हैं कि कम्युनिस्ट हमेशा सही सिद्धान्त की बात के विरोध में रहेंगे और वे यह भी जानते हैं कि वोटों के द्वारा कम्युनिस्टों ने राज्य कहीं प्राप्त किया नहीं है। तो दोनों यहां एक जगह आ जाते हैं। उन्होंने जवाहरलालजी की दुहाई दी। मैं कहता हूं कि जवाहरलालजी ने देश की गिरावट की है जवाहरलाल नेहरू के कारण ही तो देश की यह सारी गिरावट हुई है। वैसे मेरे दिल में जवाहर लाल नेहरू के लिए सम्मान है, स्वतन्त्रता संग्राम में देश को आगे बढाने में जो काम उन्होंने किया उसके लिये हमारे दिलों में उनके प्रति सम्मान है पर हिन्दुस्तान को बिगाडने में जितने काम उन्होंने किये हैं वहां हमें उनसे विरोध है। तो हम जवाहर लाल नेहरू की चिन्ता नहीं करते, जो सही बात है वही कहते हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : १९४७ में क्या था ?

श्री रामकिशन : वह समय बदल गया, वे बदल गये। सुखाडिया साहब की हिम्मत नहीं कि जवाहरलालजी और मुरारजी देसाई की मंशा के खिलाफ चलें शान्तिप्रसाद जैन से उनकी दोस्ती है पर बिडला, टाटा के बडे दोस्त पं० नेहरू दिल्ली में वहां बैठे हैं। जवाहर लालजी का एक इशारा हो जाय तो दूसरे दिन ही शान्तिप्रसादजी से बात भी नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि इनके ये सम्बन्ध कितने जल्दी बदलते हैं। इशारों से बदलते हैं। मुझे तो सुझाव देना है कि जवाहर लालजी के कारण देश की गिरावट हुई है, आर्थिक गिरावट हुई है, चरित्र की गिरावट हुई है ....

श्री निरञ्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा) : On a point of order Sir, the point of order is that measures not the persons are to be discussed. This is not relevant to the debate.

एक पर्सनलिटी को डिस्कस, जिसका सदन से सम्बन्ध नहीं और यह सदन का विषय भी नहीं, कर उन पर रिफ्लेक्शन डालना उचित नहीं।

श्री रामकिशन : मेरी यह मंशा कतई नहीं थी जो उप मंत्रीजी ने रखी। कम्युनिस्टों का फिकरा उन्होंने सुना नहीं। मैं बतला देना चाहता हूं कि जवाहर लाल जी के प्रति हमारे दिल में सम्मान है, आपके दिल में तो नकली सम्मान है, हमारे दिल में असली सम्मान है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपके सम्मान को समझना और न समझना दोनों ही विषम है।

श्री राम किशन : इसलिये कि आप दार्शनिक नहीं हैं।

इसलिये मवेशी पर टैक्स, जमीन पर टैक्स, जिस जमीन में मुनाफा नहीं होता उस पर टैक्स लगा कर सरकार ने अन्याय किया है। पंजाब सरकार ने ३ प्रतिशत टैक्स, मिर्ची की खेती पर, ३ प्रतिशत टैक्स गन्ने की खेती पर लगाये हैं लेकिन राजस्थान सरकार ने यह टैक्स लगा कर उचित नहीं किया। गुजरात सरकार ने तो यह टैक्स वापिस ले लिये हैं, आप भी इन्हें वापिस ले लें। आप मेरा निवेदन नहीं माने तो जो बडे बडे शहरों में मकान हैं, जो पक्के मकान हैं, उन पर टैक्स लगायें और इन करों को वापिस लें।

आस्ट्रेलिया ने तो एक नया टैक्स लगाया है, सौन्दर्य का जितना प्रदर्शन करेंगे, उस पर टैक्स लगेगा। आप भी अगर यहां इस प्रकार का टैक्स लगायें तो इससे आपको बडी अच्छी आमदनी हो सकती है। मैं नारियों का सम्मान करता हूं पर आप सौन्दर्य प्रदर्शन पर टैक्स लगादें तो आपको अच्छी आमदनी हो सकती है।

तो अन्त में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार करेंगे, वरना सुझावों से कोई काम नहीं होने वाला है। हर टैक्स के लिये कहते रहेंगे कि हमें पैसे की आवश्यकता है और बगैर पैसे के निर्माण कुछ नहीं होगा।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुल प्रसाद शर्मा।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (मांडल) : माननीय उपाध्यक्ष, बजट भाषण पढने के बाद दो दिन से इस पर बहस हो रही है। बजट जो गत वर्ष रखा गया था उससे इसके रखने के तरीके में जरूर हेर फेर की गई है, समझा तो यह गया था कि आयन्दा बजट रखा जायगा उसे और खुलासा करके रखेंगे जिससे समझने में आसानी होगी पर इसके बदले यह हुआ कि मिनिस्टोरियल स्टॉफ और फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स सबका पहले अलग दिया था, इसमें सब एक ही जगह लिख दिया है। इससे कोई पता नहीं लग पाता जितना पिछले साल मालूम हो सकता था। इससे पता लगता है कि बजट बनाने वालों ने गुंजायश रखी है कि मर्जी चाहें उस पर खर्च कर दें। हमें कोई कहने वाला नहीं है इस प्रान्त में। इस तरह से यह बजट आया है। टैक्सों की बात अलग है। बजट रखने का तरीका है उससे स्पष्ट मालूम नहीं पडता।

पहले बजट में बताया था कि रोडवेज से २४ लाख का फायदा मिलेगा, इसमें २७ लाख बताया है। ६-१-६२ तक ५ लाख का घाटा बता रहे हैं और रोडवेज वाले अपनी रिपोर्ट में १२ हजार का घाटा बता रहे हैं तो कौनसे हिसाब को सही मानें एवं कौनसे को गलत ? तो इन हिसाबों को तो व्यवसायी

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)
ढंग से ही रखना पड़ेगा। मुझे याद है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसी जगह खड़े होकर आपने बजट के मामले में कहा था कि जब तक कामर्शियल बेसिस पर हमारा बजट नहीं बनता तब तक हम आगे नहीं बढ सकते · · ·

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-शिक्षा, मंत्री): On a Point of Order Sir, He should not give a reference of the Chair here....

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैंने नारायण सिंह जी साहब मसूदा के लिये कहा है। आपकी तो आदत है, बीच में गडबड करने की · · · · · · · · ·

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is reflection about the Chair...

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आपमें तो वही आदत अपनी पडी हुई है लडाने की। मैंने डिप्टी स्पीकर साहब नहीं कहा, नहीं कहा।

हमने करोडों रुपया बिजनेस में लगा रखा है, इसका हिसाब नहीं मिल रहा है इस बजट से। यह बजट रखने का तरीका पुराने जमाने का है जब शासन केवल प्रशासन करता था, व्यापार नहीं करता था। पटवारी कलेक्शन करते थे और हिसाब आमद खर्च का रख दिया जाता था। पर आज हम व्यापार करते हैं, २ करोड रुपया हमने रोडवेज में लगाया है, गत साल १२ हजार का घाटा जो फाइनल अकाउन्ट्स रोडवेज के हैं, उनमें बताया गया है और आप ५ लाख का घाटा बता रहे हैं, दोनों में से सही का मालूम नहीं पडता। इसी प्रकार जिस जिस व्यापार में चले जाइये आप अन्दाज नहीं लगा सकते कि किस में नफा है, किसमें कितना घाटा है। नमक हम खरीदते हैं जितने में खरीदते हैं उससे दूना हम लेते हैं पर फिर भी इसमें जितनी बचत होनी चाहिये उतनी नहीं होती है। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह के ये सारे हिसाब व्यवसायी ढंग से रखेंगे तभी हमारा बजट सही मायने में बजट होगा और हम आगे बढ सकेंगे। हमेशा यह चाल चलने वाली नहीं है। यह लगान घाटे के लिये नहीं विकास के लिये है, कर लगाते हैं घाटे की पूर्ति के लिये, नहीं विकास के लिये हैं पर आप कर लगाते हैं घाटा बढाने के लिये।

जहां कर नीति की बात है, करों का आम तौर से लोग विरोध करते हैं। हमें अगर विकास करना है तो देश में निश्चय ही कर बढेंगे, कोई रोक नहीं सकता। पर कर बढाने का तरीका होगा और उन तरीकों से ही कर बढेगा। इस तरह से काम नहीं चलेगा हमें इस पर विचार करना होगा। कर बढाइये उन पर जो कर देने की क्षमता रखते हैं। जिन लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं से लाभ उठाया है, दो पंचवर्षीय योजनाओं से लाभ उठाया है और तृतीय पंचवर्षीय योजना से लाभ उठा रहे हैं।

कर बढाने के साथ साथ फिजूल खर्चियां जो हम करते हैं उन्हें कम करना पडेगा। बहुत सी जगह नाम के लिये फिजूल खर्चियां कर देते हैं। मैं उदाहरण रखूं, समाज कल्याण में इतना फिजूल पैसा खर्च करते हैं, वित्त मंत्री खुद अपने जवाब में बता दें कि यहां भिक्षा गृह चला रखा है, उसमें ५ आदमी भी किसी दिन नहीं रहे, वहां पर ४५ हजार रुपयों का खर्च है। छात्रावास कन्याओं का चला रहे हैं। उसमें ८ मील दूर की आनी चाहिये कन्याएं पर यहीं की कन्याएं हैं, जो दिन भर अपना काम धंधा इधर उधर करती

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

रहती हैं और दोनों टाइम खाना खाने आ जाती हैं। ४ लड़कियों के लिये ३६ हजार रुपया साल का खर्च होता है और मकान अलग किराये ले रखा है।

फिजूल खर्चियां हमें बिलकुल कम करनी पड़ेगी। जहां पर सरकारी मकान हैं, क्योंकि आप बजट मुख-बंद करके पास करवा लेते हैं, इस कारण से हमारे अधिकारी हैं वे समझते हैं कि बजट पास होगया, सरकारी मकान होते हुए भी अच्छे से अच्छा मकान किराये पर लेकर वे लोग रहते हैं और रुपया आफिस बनाने के नाम पर ले लेते हैं। भीलवाड़ा की बताऊं। पुरानी अच्छी शानदार इमारत है जहां पर पटवारी आदि आज कल रहते हैं जहां पर कई विभाग रह सकते हैं वे खाली पड़े रहते हैं और उनके अन्दर सिवाय चौकीदार के और कोई नहीं रहता है जहां कि पहले तहसील और कलेक्टर का आफिस था और वे लोग रहा करते थे। यही हालत सहकारी विभाग की है और यही हालत भू-रक्षण विभाग की है। कोई टूटी हुई जगह नहीं है। अच्छी जगह है। आपने मुख-बंद लगा कर बजट पास कर लिया यह तो पास हो गया पब्लिक कुछ कह नहीं सकती। बजट की रकम लेप्स न हो इस कारण से उसको खर्च जल्दी से जल्दी किसी न किसी प्रकार से कर लेना है। फरवरी महीने में देखा है कि ज्यादा से ज्यादा खर्चा होता है हर विभाग में। अजमेर गये सामान लेने के लिये। क्यों भाई? इसलिए कि बजट लेप्स हो रहा है और यह खर्चा हमें करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र में मंत्री इसीलिए होते हैं कि जनता के पैसे के वे संरक्षक हैं। जो अधिकारीगण काम करते हैं, हमेशा से अपने तरीके से काम करते आये हैं, उनकी यदि बुराई करूं तो चलने वाली नहीं है जब पहले की हुकुमतें थीं, राजाओं की या अंग्रेजों की वे उनके वफादार थे प्रजातन्त्र आया तो वे यहां भी इसके अन्तर्गत वफादारी से काम करते हैं। हो सकता है उनमें बेईमान हो, होंगे बेईमान। आप हममें कई खराब हो सकते हैं, उनमें भी हो सकते हैं या हैं लेकिन सारे के सारे खराब हैं यह मैं नहीं मान सकता। केरल में देखा कि जब कम्युनिस्टों की हुकुमत आयी तो जिस प्रकार केरल में कम्युनिस्ट शासन ने चलना चाहा उसी प्रकार वे वफादारी के साथ काम करते रहे और चलते रहे। वे तो रथ के दो पहियों का काम करते हैं। यदि ठीक तरह से देखें तो खर्चे में काफी कमी आ सकती है। लेकिन आज हम उसको देख नहीं रहे हैं। आज इस तरह के टैक्स लगाने की बात नहीं करते तो फिजुल खर्चियों की कटौती इस मोटी किताब में नजर आती रहती। आपने यह देख लिया है। मैं आपको नमूना बताता हूं। गवर्नमेन्ट होस्टल में ६२-६३ में किसने मुफ्त में खाना खाया? गवर्नमेन्ट होस्टल में २५ हजार रुपये लिखे हैं खाने के। अप्रेल में हम आये। किसने खाना खाया? आप इसको ठीक करें। इस प्रकार का खर्चा बता कर यह किया वह किस कारण से?

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विद्युत) एम. एल. एज. का।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : खाना खुराक के हैं। ठेकेदार है वहां पर। उससे गवर्नमेन्ट को कोई लेना-देना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वित्त मंत्री इसको साफ करें कि किस बात के हैं। इसका स्पष्टीकरण हो जाय।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : जवाब में आ जावेगा।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : पिछले वर्ष जो बजट दिये हैं और दूसरे साथ में दिये हैं जिनमें एस्टीमेटेड और रिवाइज्ड आंकड़े दिये गये हैं। एस्टीमेट का एस्टीमेट के आंकड़ों से मिलान नहीं होता। इसमें कुछ लिखा है और उसमें कुछ लिखा है। तमाशा देखने के लिए है यह

श्री बालकृष्ण कौल : एस्टीमेट से रिवाइज्ड नहीं मिलते।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : इतना तो मुझे भी ज्ञान है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि एस्टीमेट से एस्टीमेट नहीं मिलते।

श्री बालकृष्ण कौल : आप बता दें।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : बतला दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण प्रारम्भ करें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर न दें।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : इस निजाम को चलाने के लिए उत्तर देना जरूरी है। उनको बताना पड़ेगा।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मुख्य शीर्षक ११, मांग संख्या ३ उनके जो पुराने एस्टीमेट दिये हैं और अब जो एस्टीमेट दिये हैं दोनों नहीं मिलते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : पेज नम्बर।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : पेज नम्बर पिछले का ४७-४८ और अब ६८ और ६९।

हर आइटम में फर्क डाला है। कर्मचारियों में फर्क, अधिकारियों में फर्क हुआ है। रिवाइज्ड में कुछ भी फर्क कर दीजिये। असली चीज में कहां फर्क रहता है? जो परिशिष्ट दिया है, जितनी रकम रखी है वह भी नहीं मिलती। परिशिष्ट में कुछ कम है और इसमें ज्यादा लिख दी गई है।

श्री बालकृष्ण कौल : एपेंन्डिक्स कौनसा?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं बता दूंगा तो आप इतना ही देखेंगे, बाकी नहीं देखेंगे।

एपेंन्डिक्स 'जी' पेज २५०-२५१। टोटल आता है १,९५ हजार और देते हैं २,१५ हजार।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : फिर वही घोटाला है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : परिशिष्ट इसी 'जी' में २५२-२५३ पेज पर फिर फर्क है। आप या तो बजट देख कर नहीं लाये हैं या अन्धाधुन्ध काम किया है। इस ओर मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं कि एल. डी. सी. लोग कागज बना देते हैं और अधिकारी और मंत्री ऊपर तक उसको वैसा ही देख लेते हैं। उसके अन्दर जाने की कोशिश नहीं करते हैं तो यह एल. डी. सी. बजट है। शानदार बजट बनना चाहिये वैसा बजट नहीं है। वैसा होता तो गलतियां नहीं होतीं। प्रान्त की जो सही हालत है उसको लोगों को सही ढंग से समझाने में इस प्रकार की गलतियां दिक्कत पैदा करती हैं। बजट में और कई जगह गलतियां हैं। सारी गलतियां बताने लग जाऊंगा तो कई दिन लग जावेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, ६१-६२ के खर्चे का एक्चुअल अकाउन्ट दे दिया है ६३-६४ में। एक्चुअल अकाउन्ट में जितनी डिमान्ड पेश की है, तीन सप्लीमेन्टरी बजट हुए हैं। २ पहले वाले वित्त मंत्री और १ पिछले मंत्री के बाद कौल साहब आये, तो उन्होंने किया।

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

तीन दफं के बाद भी २,२३,७४ हजार रुपये जो राशि है वह खर्च कर दी गई बिना डिमान्ड स्वीकार कराये हुए। जब आपने सदन से इसको पास नहीं कराया तो यह आपको रखना नहीं चाहिये था। आपको चाहिये था कि जब अकाउन्ट पेश किये जाते तब इसे रखा जाता जैसे कि आपने ५८-५९ की एक्सेस डिमान्ड अभी थोड़े दिन पहले हाउस के सामने रखी थी।

इस बजट को पास करने के बाद हम यह मान कर चल सकते हैं कि १९६१-६२ का अकाउन्ट स्वीकार कर लिया गया...

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, वित्त): एक्सेस डिमान्ड्स मांग ली जायंगी।

श्री भैरोंसिंह: एक्सेस डिमान्ड्स आ जायंगी इसका मतलब यह हुआ कि एक्चुअल्स से ज्यादा खर्च कर दिया गया?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: एक्चुअल्स से ज्यादा खर्च हो जाय तो कोई बात नहीं। सवाल यह है कि अनुपूरक मांग में डिमान्ड क्यों नहीं आयी? यह बजट जो रखा गया है १९६२-६३ का उस वक्त यह भी रखा जा सकता था। आप कहते हैं मांग बाद में करली जायगी। मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता। लेकिन यह देख लिया जाता तो कमी का रख दिया गया होता। आपने स्टाफ्स में भी ज्यादा बता दिया, अदर एक्सपेन्सेज में भी ज्यादा बता दिया।

श्री बालकृष्ण कौल: आप रिसीट्स बता दें।

श्री उपाध्यक्ष: Order please! मैं माननीय सदस्यगण को सूचित करना चाहता हूं कि यह जो बातचीत कर रहे हैं यह हमारी परम्परा के प्रतिकूल है। अगर किसी माननीय सदस्य को भाषण के दौरान में कुछ कहना हो तो पोइन्ट ऑफ आॅर्डर या पोइन्ट ऑफ इनफोर्मेशन के जरिये राइज हो सकते हैं और विवाद कर सकते हैं। इस प्रकार से बातचीत चलती रही तो कोई नियन्त्रण नहीं हो सकेगा।

श्री मानसिंह महार: मंत्रीगण ही कर रहे हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: इस प्रकार से जो खर्चा कर लेते हैं और डिमान्ड स्वीकार नहीं कराते और इस प्रकार डिमान्ड में बताते हैं कि इस प्रकार यह खर्चा किया जायगा तो इससे सही आंकड़े बजट में नहीं मिल पाते। पहले से इसको ठीक करने की कोशिश की गई है, एरेटा भी निकाला गया, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें रह गई हैं। बजट जो बनाया जाता है उसमें यह देखा गया है कि विभाग के जो अधिकारी हैं जिस प्रकार का बजट बनाकर रख देते हैं उस पर बराबर दस्तखत होते जाते हैं लेकिन मंत्रीगण की इसको देखने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उनके नहीं देखने से गलतियां रह जाती हैं, उन गलतियों का सुधार करना चाहिये। अब मैं टेक्सेज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

इस बजट में चार करोड़ रुपये के टैक्स लगा दिये। टैक्स आपने इसलिये लगाये हैं कि आमदनी कम होगी और खर्चा ज्यादा होगा। लेकिन इसके लिये मेरा निवेदन है कि जितने भी फालतू खर्च हैं उनको कम करना होगा। टैक्सेज जो बताये गये हैं उसके अनुसार स्टाम्प पर ड्यूटी लगाने से ५० लाख, वाहनों से २० लाख, विज्ञापन-कर से ४ लाख। इसके अलावा बाकी जो कर बताये गये हैं उनसे १ करोड़ ८२ लाख की आमदनी बताई गई है।

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, दो मद हैं; बिक्री कर जहां सात प्रतिशत लग रहा है उसकी जगह अब दस प्रतिशत कर दिया गया और इससे ४५ लाख की आय बतलाते हैं। सामान्य दर जो पांच प्रतिशत थी उसके बजाय ६ प्रतिशत कर दिया, उससे ३५ लाख की आय होगी। इस तरह से तीन प्रतिशत के हिसाब से ४५ लाख की आय बनती है तो एक प्रतिशत से १५ लाख की मान ली जाय तो १०५ लाख की आमदनी जो पहले लगायी और अब १७५ लाख-इस तरह से अब तक २८० लाख इससे मिल पाया है। लेकिन बजट में बतलाया गया है ६.८० लाख मिलता है। सेन्ट्रल सेल्स टैक्स से ९६ लाख रुपये के करीब है वह भी बढ़ाया है। जहां २८० लाख रुपये की आय होना बताया गया है उस हिसाब से एक करोड़ की आय अनुमान से ज्यादा हुई, केवल दो चीजों पर बिक्री कर लगाने से।

मुक्त वस्तुओं के कर से भी २४ लाख की आमदनी बताते हैं। ये दोनों जोड़े जायं तो १.८० लाख की आय होगी। इस तरह से एक करोड़ की पूर्ति हो जाती है।

इतना होते हुए भी आप भूमि पर टैक्स लगा रहे हैं, पशुओं पर टैक्स लगा रहे हैं। आज राजस्थान के ८० प्रतिशत किसान गांवों में रहते हैं, जो किसान जागीरी गांवों में थे और राजाओं के राज्य में तो सभी थे। उस जमाने में किसी प्रकार का दूसरा कर नहीं था। लैन्ड रेवेन्यू के रूप में गवर्नमेन्ट वसूल करती है, उस समय लेन्ड रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा लगा रखा था। हमारे यहां एक-एक बीघे पर १९ रुपया लैन्ड रेवेन्यू का था। उसके बाद आज २५ प्रतिशत, ३३ प्रतिशत और बढ़ जायगा और उसको किसान दे नहीं पायगा। यदि बुद्धिमानी से सोचा जाय तो और भी रास्ते निकाल सकते थे कर उपजाने के। यह बड़ा बुरा स्टेप है। यह सोचने की फुर्सत कहां? बैठे-बैठे किसी अधिकारी ने कह दिया, जमीन पर टैक्स लगादो, इससे इतनी आमदनी बढ़ जायगी। बस बुद्धिमानी से तो काम लेने का कौन सोचे . . .

श्री मानसिंह महार (आमेर): बुद्धि तो है ही नहीं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: पशुओं पर कर लगाना, जमीन पर कर लगाना उचित नहीं। वह नहीं लगना चाहिये। यह मेरी दरख्वास्त है। आप यह कहेंगे कि फिर आमदनी किस प्रकार से हो सकती है? मैं उसके लिये आपको बताऊं कि अपने बजट में ७॥ करोड़ रुपया जो हमने कर्ज लिया है उस पर ब्याज देने का प्रावधान किया है। उसके विपरीत हम जिनको कर्जा देते हैं उनसे ब्याज नहीं लेते हैं। हमने ७० करोड़ रुपया कर्ज में दे रखा है जिसका ब्याज १ करोड़ ४ लाख बताया गया है। अगर सही जोड़ लगाई जाय तो यह ब्याज तीन करोड़ रुपये से ज्यादा होगा। पांच प्रतिशत ब्याज से किसी को कम पर कर्ज नहीं दिया जाता। इस तरह से हम केलकुलेट करते हैं तो दो करोड़ रुपया आ सकता है और जो कर्जा दिया है उसका सूद भी बराबर वसूल करते रहें तो जानवर, जमीन और अनाज पर कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनसे तो ब्याज वसूल नहीं करते बस लगा दिया कर जमीन पर ताकि तहसीलदार पटवारी को कहें और पटवारी जोर जबरदस्ती किसानों से वसूल करता रहे। मेरा आपसे निवेदन है कि जिनको आपने कर्ज के रूप में रुपया दिया है उनसे बराबर वसूल क्यों नहीं करते।

हमसे यह कहा जायगा, उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक उनसे रुपया आया नहीं जब आयगा

Page No.86

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

तब जमा कर लेंगे। यदि आप ऐसा ही समझते हैं तो २०० करोड रुपया बांट दीजिये, उधार दे दीजिये और उसकी पूर्ति के लिये जनता पर कर लगाते जाइये और कर्जा लेते रहिये। आप जितनी मुस्तैदी से लोगों को विकास के लिये कर्जा देते हैं उतनी ही मुस्तैदी से आपको वसूल कर लेना चाहिये। आज हम देखते हैं यहां पर लोगों ने बडे बडे मकान बना लिये और वे किराये पर चलते हैं लेकिन सरकार की बकाया वे देते नहीं, उनसे आप वसूल नहीं करते। आप इन टैक्सेज को तो माफ करिये और जो कर्जा आपका दिया हुआ है उसको सख्ती से वसूल करिये।

इसी प्रकार मैंने एक दिन पहले भी निवेदन किया था कि राजस्थान रोडवेज के लिये हमारे यहां बहुत बढ़िया गैराज बना हुआ है अपने मोटर गैराज में केवल ७८ गाडियां हैं। इस साल कुछ और खरीदी हैं और भी ३ लाख की गाडियां खरीदना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये गाडियां ज्यादा से ज्यादा बीस आदमियों के लिये काम में आती हैं २१ वें आदमी को गाड़ी नहीं देते। इस मोटर गैराज के बजाय हमारा जो रोडवेज का फर्स्ट क्लास गैरेज है उसमें इन गाडियों को रखा जाय। इसके अतिरिक्त हमारे मोटर गैराज की बकाया है वह भी करीब १ करोड के आसपास है। मोटर गैराज से गाडियां किनको मिलती हैं? या तो बडे बडे अधिकारी हैं उनको या बड़े लोगों को। उनमें जो यह बकाया है वह भी वसूल नहीं कर पा रहे हैं। उनसे पैसा वसूल करना चाहिये जो एक करोड के आसपास है। आप वाजिब उगाही किये जाने वाले पैसे को वसूल नहीं करते और हमसे कहते हैं कि टैक्स बढ़ाओ।

आप अपनी फिजूलखर्ची और शासन का कमर तोडने वाला खर्चा कम कर दें। आप अपनी मोटर गैराज का खर्चा कम कर दीजिये। राजस्थान रोडवेज के गैराज में इसे मिला दीजिये। उसका बहुत बडा गैराज है। बाहर जाना हो आपको तो ।) मील वाइज जुडवा कर जाइये। इससे यह तो मालूम पडेगा कि कितने मील चले हैं आप दौरों में। माइलेज की बात मैं पहले कह गया हूं। बार-बार नहीं दोहराऊंगा। पर आपको इस पर कन्ट्रोल करना होगा। मैं मंत्रियों से भी निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी से भी ज्यादा दौरों पर जाना और गाडियों को तोड लाना बन्द करें। यह नहीं चलने पावेगा।

(विराम)

खर्चों को इस तरह से कम करना ही होगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): वे कौन से मंत्री हैं जो गाडी ले जाते हैं और तोड लाते हैं?

श्री माणकचन्द सुराणा (कोलायत): नाम बता दीजिये उनका। आपने तो जनरल रिमार्क दे दिया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: मैंने जनरल रिमार्क नहीं दिया। गाडियों पर चढ़ने वालों की लिस्ट में कुल बीस आदमियों के नाम हैं और उनके लिये ८० गाडियां गैराज में रख रखी हैं। यह ठीक नहीं है। पहले साधन नहीं थे इसलिये किसी हिसाब से वाजिब कहा जा सकता था पर, आज तो आपका रोडवेज है। अब साधन है, आपका अपना विशाल कारखाना है मरम्मत का और मेन्टीनेन्स का। आप सारा प्रबन्ध उनको दे दीजिये।

श्री भैरोंसिह : आपने कहा न कि मुख्य मंत्री से ज्यादा भी मंत्री ने टूर किया । वे कौनसे मंत्री हैं ।

X X X X

श्री उपाध्यक्ष : Order Please, order ! माननीय सदस्य बजट पर भाषण कर रहे हैं, न कि परस्पर एक दूसरे सदस्य पर कोई आक्षेप कर रहे हैं । इस तरह से आक्षेप करना सदन की परम्परा के प्रतिकूल भी है कि वैयक्तिक रूप से किसी माननीय सदस्य के ऊपर आक्षेप किया जावे । तो इसलिये इससे बचना चाहिये और जो पॉलिसी का विषय है उसी पर वक्तव्य देना ज्यादा उचित होगा ।

श्री भैरोंसिह : पर, उपाध्यक्ष महोदय, जो कह दिया है, उसके लिये क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो कुछ भी माननीय सदस्य के लिये गाडी में जाने के बारे में कहा है वहां तक वह एक्सपन्ज किया जाता है ।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री उद्योग) : इसका मतलब यह है कि माननीय सदस्य किसी गाडी में गये नहीं ?

श्री भैरोंसिह : हां, मैं नहीं गया सिवाय शहर के । जो मैंने किया है मंजूर किया है ।

श्री चन्दनमल वैद : मेरे साथ गये हैं ।

श्री भैरोंसिह : यह सरासर झूठ है ।

श्री चन्दनमल वैद : आप जयपुर शहर में मेरे साथ गये हैं ।

श्री भैरोंसिह : जयपुर शहर की मैंने बात पहले कह दी है ।

---

xxxxअध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री उपाध्यक्ष: Order Please, order ! जो विषय सदन में चल रहा है उसके अलावा मैं दूसरे विषय की बातों में माननीय सदस्यों को जाने देना नहीं चाहता ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जो आपने आज्ञा दी, उपाध्यक्ष महोदय, वह शिरोधार्य है ।

श्री भैरोंसिह : रॉक सॉल्ट से यों पीछा नहीं छूटेगा ।

श्री चंदनमल वैद : I object to it Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I am not prepared to listen to any other discussion. Shri Gokul Prasad, Please continue.

श्री भैरोंसिह : इन बातों से असर थोडे ही होगा । नमक निकल निकल कर बाहर आ रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण प्रारम्भ रखें ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जहां तक करों की बात है मैंने निवेदन किया है कि कुछ कर ऐसे है कि जिनके लगाने से हम बच सकते है और उनके बिना भी हमारा बजट ठीक से चल सकता है । उनके बदले हम अपना बजट किस तरह से ठीक कर सकते है, उनमें से कुछ के बारे में मैंने निवेदन कर दिया ।

इसके बाद जैसा मैं बतला रहा था अभी, उधर से कल से आज तक रात दिन एक ही बात अधिक जोर से आ रही है और वह है भ्रष्टाचार की बात । मैं फिर निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार कहां से उत्पन्न होता है और किस तरह से फैलता है । हर व्यक्ति जो

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

सरकार की नौकरी करता है, भ्रष्ट नहीं हो सकता। उसी तरह से हर आदमी जो यहां पर बैठा है अच्छा नहीं हो सकता। सब तरह के लोग संसार में रहते हैं। भ्रष्टाचार क्यों फैलता है, इसका एक तरीका है एक ढंग है। किसी भी सरकारी नौकर को हम उसका यहां नाम लेकर बदनाम करते हैं, उसकी बातें करते हैं, उसको बरा भला कहते हैं और उसको वहां अपने इलाके में डराते हैं यह कहकर कि अगर तुमने हमारा फला काम नहीं कर दिया तो हम असेम्बली में यह प्रश्न तुम्हारे खिलाफ उठवा देंगे और तुम्हें बदनाम करेंगे। वह यहां बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता और इस तरह से वह कमजोर पड़ जाता है और अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह अदा नहीं कर सकता और यहां यह हालत होती है कि यहां बैठकर तो उनकी बुराई कर देंगे और उधर सिविल लाइन्स में बैठकर या सेक्रेटेरियट में जाकर कहेंगे कि फलां काम कर दीजिये हमारा। वहां उनसे बेजा काम करवाते हैं। अब यह मिनिस्टर लोगों का या सेक्रेट्रियों का कर्त्तव्य है कि उनको मजबूत होना चाहिये, उनमें इतना आत्मबल होना चाहिये कि इस तरह के काम करने को कहें तो साफ इन्कार कर दें। पर यह कमी उनकी भी है और वे रोब में आकर उनका काम कर देते हैं। वहां उनका सिक्का जम जाता है और सर्विस को इस तरह से ये लोग कमजोर करते हैं। तो ये ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाले हैं। अगर कोई यह कहे कि कांग्रेस के लोग करते हैं तो गलती है। आप मन्त्रियों की नोट बुकें मंगवा कर देखें लें कि वे ऐसे काम कितने करवाते हैं। इस तरह के काम ज्यादा से ज्यादा वे लोग करवाते हैं जो यहां पर उनकी बुराइयां करते हैं। वे ही भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं। कइयों को मैंने देखा है जो यहां बुरा भला कहते हैं और वहां उन्हीं के साथ कमरे में बैठकर वे उनसे काम करवाते हैं आपमें। यहां बैठकर शिकायतें करते हैं-फलां ने यह काम नहीं किया, उसको यहां से बदल दो, उसको रख दो। पर इसमें भी कुछ कमजोरी तो सरकारी अधिकारियों की है ही। उन सरकारी अधिकारियों में और सरकारी कर्मचारियों में आत्मबल नहीं रहा। आत्मबल उनमें अगर रहे और मजबूत रहें वे तो भ्रष्टाचार कम होगा, नहीं तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा और फलेगा फूलेगा। वह आत्मबल कमजोर उनका तब नहीं रहेगा जब हम यहां स्वयं अपना आत्मबल मजबूत रखेंगे। हमें अपने दिलों को भी मजबूत करना होगा और साफ कहना होगा कि इस तरह की बातें हम नहीं करने देंगे। आप साफ कहदें टैक्सों के मामले में भी कि टैक्सों को किसी की बातों से डर कर कम-ज्यादा नहीं करेंगे। उनकी बातों से डर कर टैक्स लगाने की बात छोड मत दीजिये। पर ठीक से अपनी बुद्धि से सोच कर टैक्स लगावें, कोई गलत टैक्स भी मत लगाइये। ये दो तरह की बातें मैंने सदन के सामने रक्खीं।

कुछ लोग यहां कुछ और कहते हैं, बाहर मीटिंगों में कुछ और कहते हैं। कहते हैं आज की संकटकाल की स्थिति में भी हमें टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका पैसा देता है। अमेरिका से पैसा ले लेना चाहिये और उससे हमारा सारा काम चल जावेगा। एक तरफ से यह आवाज आती है कि टैक्स इसलिये लगाया जाता है क्योंकि एक दूसरा दुश्मन हमारे सामने खड़ा है। नहीं लगावेंगे तो तुम्हारी जैसी ही फीलिंग लिये

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

दुश्मन सामने खड़ा है ? तो मैं पूछता हूं यह कौनसी देशप्रियता है ? यहां आकर यह कह दें कि यह टैक्स न लगाओ, अमेरिका से पैसा ले लो। तो वे इसलिये ऐसा कहते हैं कि यदि हम अमेरिका से पैसा ले लें और हमारे देश में से दुश्मन चला जाय तो भी देश के अन्दर जो विकास हम करना चाहते हैं, निश्चय ही इससे उसमें बाधा पड़ेगी। क्योंकि जिस प्रकार और देशों में अमेरिका ने इस पैसे के बल पर कब्जा जमा रखा है, उसी तरह से वह यहां भी कोशिश करेगा। हां, हम उसको और ब्रिटेन को दाद देते हैं जो उन्होंने हमारी मदद की है उसके लिये।

उन्होंने बहुत उपयुक्त समय पर हमारी मदद की लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिकन राजदूत यह कहें कि हिन्दुस्तान की स्वतंत्र पालिसी अच्छी है तो हमारे लिए, अमेरिकन एजेन्ट हैं वे यह कहेंगे कि नहीं, हमको तो अमेरिका से पैसा मिल जाना चाहिए। वे टैक्स लगाने के संबंध में सस्ती लीडरशिप लेने के लिए तैयार हो जायेंगे और कहेंगे कि टैक्स मत लगाओ और अमेरिका से पैसा ले लो। इससे होगा क्या कि मजदूरों और किसानों का शोषण होगा। हमें याद है वे दिन जब सुबह ४ बजे से लेकर रात तक लोगों से काम करवाया जाता था। लेकिन आज सन्डे भी विद पे मिलती है, आज मजदूरों के कल्याण के अलग अलग कानून हैं, उनको राहत देने के लिये कानून हमारे सामने आये हैं। कहीं उनके कहने के चक्कर में आ जायें तो यह सारा रफू हो जायेगा। इसलिये हमारी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने के साधन भी हैं। यहां हमें बातों के चक्कर में नहीं आ जाना चाहिये। एक कहता है कि अमेरिका ठीक है और दूसरे कहते हैं कि दूसरा ठीक है। दोनों हमें नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हैं। लेकिन हमने निश्चय कर रखा है कि हमें देश को आगे बढ़ाना है इसलिए बातों में नहीं आना चाहिये। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

श्रीमती सुमित्रा देवी (झुन्झुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, घाटे का बजट एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए शुभ लक्षण है और उसी रीति को निभाते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यह ४।। करोड़ रुपये के घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। लेकिन आपने उर्दू शैली का पुट देकर इस बजट भाषण को जो मौलिकता प्रदान कर दी है उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद देती हूं।

वैसे राजस्थान के निर्माण और बहबूदी के लिए टैक्स लगाने पड़ेंगे, कोई न कोई जरिया इस तरह का ढूंढना पड़ेगा कि जहां से आय के साधन हम जुटा सकें और एक ऐसे सुन्दर राजस्थान का निर्माण कर सकें, जिससे हमारी आगे वाली पीढ़ियां उस पर गर्व और फक्र कर सकें। इसलिये मैं मानती हूं कि जो बजट में घाटा उन्होंने दिखाया है उसकी पूर्ति के लिए कर लगाये हैं वह भी बहुत जरूरी थे किंतु इन सब के साथ ही साथ माननीय वित्त मंत्री महोदय को एक बात का ध्यान दिला देना चाहती हूं कि उन्होंने बार बार अपने बजट भाषण में समाजवादी समाज व्यवस्था का नारा लगाया है। मेरी समझ में नहीं आता कि समाजवादी समाज का जो सुन्दर नाम है इसकी आड के अन्दर उन लोगों को किस तरह की प्रवंचना और धोखा दिया जा रहा है जो

(श्रीमती सुमित्रा देवी)

लोग सचमुच में समाजवादी समाज में निष्ठा रखते हैं। इसलिये कि राजस्थान का किसान और गरीब मजदूर समाजवादी समाज व्यवस्था के नाम पर कुछ बोलेगा नहीं ? इसलिये उस पर यह जो टैक्स लगाये गये हैं इसके लिए मैं वित्त मंत्री महोदय को एक बार पुनः याद दिलाना चाहती हूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण में शुरू ही शुरू में यह कहा है कि यह बजट चीनी हमला-आवरी के स्याह साये में पेश किया जा रहा है। जिस समय मैंने यह शब्द सुने उस समय मैं महसूस कर रही थी कि हमारे वित्त मंत्री महोदय शायद इस पृष्ठभूमि में कुछ ऐसी बातों का जिक्र करेंगे और ऐसे लोगों को कुछ राहत मिलेगी कि जिन लोगों ने सचमुच में इस राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्दर दिल खोलकर पैसा दिया है और उन लोगों को राहत मिलेगी जो सचमुच इस एमरजेन्सी के पीरियड में तकलीफ में हैं और मैं समझती थी कि उन लोगों की तकलीफों को महसूस किया जायेगा तथा उन लोगों की तकलीफ को कम किया जायेगा, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने उनका पूरा भाषण सुना, मुझे लगा कि यह तो सिर्फ एक प्रवंचना ही थी, एक शब्द था जिसकी हम लालसा लगाये बैठे थे और सोच रहे थे कि वित्त मंत्री महोदय ऐसे लोगों के लिए न जाने क्या क्या बातें रखेंगे।

उन्होंने शुरू ही शुरू में यह भी कहा है कि राजस्थान की औरतों ने भी, खासकर गंगानगर जिले की किसान औरतों ने, मुल्क की हिफाजत के वास्ते अपने प्यार से संजोये सुनहले जेवरात खुदबखुद भेंट करके भामाशाह की रीति निभाई है। मैं वित्त मंत्री महोदय को यह याद दिलाना चाहती हूं कि उन्होंने सिर्फ अपने प्यार से संजोये हुए जेवरात ही नहीं दिये बल्कि राजस्थान की वीरता की गौरवशाली परम्परा को निभाने के लिए फौलादी नौजवान भी दिये हैं। माताओं ने अपनी गोदें सूनी की हैं और अनेक पत्नियों ने अपने सुहाग लुटाये हैं और सुहाग लुटाने के बाद में अपने सुहाग चिन्ह को, जो वह विधवा होने के बाद पहन नहीं सकती थी, खुशी-खुशी सुरक्षा कोष में दे दिया। लेकिन मुझे बहुत दुःख होता है और मैं ऐसा समझती हूं कि शायद बजट पेश करने के बाद इस सरकार का कोई भी मंत्री गांवों में नहीं गया है। मुझे, बदकिस्मती से समझिये, जब यह छुट्टियां पड़ी तो गांव में जाना पड़ा और मैंने गांव के लोगों को यह कहते सुना, मुझे माफ करेंगे, सदन के सभी माननीय सदस्य, क्योंकि यह मेरी खुद की भावना नहीं है बल्कि यह सब लोगों ने मुझसे कहा था इसलिये मैं उनके शब्दों को दोहरा रही हूं। यह मैंने इसलिये कहा कि कहीं सदन मुझे गलत न समझ जाये। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वहां के लोगों ने यह कहा कि यह हमको इनाम बख्शा है राजस्थान की सरकार ने, जिस सरकार को इस तरह से खुशी खुशी अपना धन दिया, अपने सोना और चांदी के जेवरात दिये, अपने खून को दिया, अपनी गोदें सूनी कीं, अपना सुहाग लुटाया, क्या उस सरकार ने यह हमको इनाम बख्शा है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को यह इनाम की बात इसलिये कह रही हूं कि बजट में जो बहुत बड़े कर लगाये हैं वह किसानों के ऊपर लगाये हैं, लैन्ड रेवेन्यू के ऊपर एक अधिभार लगाया है। मैं एक बात पूछना चाहती हूं सरकार से कि जब ३००० रुपये तक की इन्कम पर किसी प्रकार का इन्कम टैक्स आपने नहीं लगाया है, उसको इन्कम टैक्स से महरूम रखा है तो

(श्रीमती सुमित्रा देवी)

किसान, जिनको आप अन्नदाता कहते हैं जो सर्दी की परवाह नहीं करता, गर्मी की परवाह नहीं करता, कठिन परिश्रम करके आपको अन्न पैदा करके देता है, आपका पेट पालता है, को अन्नदाता कहकर उसका गौरव तो बढ़ाते हैं लेकिन उसकी तकलीफों को महसूस नहीं करते कि किस प्रकार कठिन परिश्रम करके आपको अन्न देता है। आपने कभी सोचा कि एक समाजवादी समाज व्यवस्था का नारा लगाते हैं लेकिन जिन लोगों के पास बहुत कम जमीन है, जो अपने परिश्रम से अनाज पैदा करते हैं, उन लोगों के पास अनइकॉनॉमिक होल्डिंग्स हैं उनको आपको लैन्ड रेवेन्यू से मुक्त रखना चाहिये। लेकिन वह सब कुछ तो दूर रहा, उसके विपरीत आप उनके ऊपर अधिभार और लगाते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि एक तरफ तो आप समाजवादी समाज व्यवस्था का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ उन लोगों को तकलीफ देते हैं जो कि सचमुच में समाजवादी समाज में निष्ठा रखते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह ठीक है कि कर-भार लगाये जायें परन्तु उन लोगों के ऊपर लगाया जाये जिनकी आर्थिक क्षमता है। इस एमर्जेन्सी में, जिस समय राष्ट्र एक संकटकाल से गुजर रहा है, आपको इतना बोझ गरीबों पर नहीं डालना चाहिये था लेकिन इसके विपरीत लैन्ड रेवेन्यू के ऊपर अधिभार लगाया है। वैसे तो इसके पीछे कोई साइन्टिफिक बेसिस भी नहीं है और वह इसलिये नहीं है कि राजस्थान के हर जिले के अन्दर अलग अलग रेट्स हैं। आपने अभी तक उनका कोई स्टेन्डर्डाइजेशन नहीं किया इसलिये समझ में नहीं आता कि इसके पीछे कौन सा जस्टीफिकेशन है ?

दूसरी बात यह है कि यदि पहले कम से कम सारे राजस्थान की लैन्ड रेवेन्यू की रेट्स को रिवाइज किया जाता तो उसके बाद इस बात को सोचा जा सकता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ एक नम्र निवेदन और करूं कि १९५१ के जो आंकड़े हैं उस समय एक गरीब और अमीर के वेतन का बीच का रेशो १:११० था लेकिन आज वह रेशो बढ़कर १:३०० हो गया है।

(४ म०प०)

मैं पूछती हूं कि क्या यह समाजवाद है ? क्या आप १० साल के अर्से की इस तरक्की को समाजवाद का नाम देते हैं ? क्या लगातार अमीर और गरीब के बीच की खाई घटने के बजाय बढ नहीं रही है ? (करतल ध्वनि)

इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की रिपोर्ट के उल्लेख आधार पर भारत में कृषि के क्षेत्र में लगे हुए लोगों में से ३२ परसेन्ट महिलाएं हैं और उन ३२ प्रतिशत महिलाओं की प्रति दिन की आय सन् १९५१ में ६८ नये पैसे थी लेकिन आज यह आय घट कर ५९ नये पैसे प्रति दिन हो गई है। महिलाओं को रोजगार की ओर प्रवृत्त करनेवाली सरकार के लिये क्या ये आंकड़े चुनौती नहीं हैं ?

इसके साथ ही साथ माननीय वित्त मंत्री महोदय ने २ आना प्रति यूनिट के हिसाब से एग्रीकल्चरिस्ट को बिजली देने का जो ऐलान किया है उसके लिये तो मैं उनको मुबारकबाद देती हूं। लेकिन मुझे एक शक है और वह यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं किया जा रहा है कि २ आना प्रति यूनिट का नाम लेकर एग्रीकल्चरिस्ट, जो सही माने में आते हैं, उन किसानों को न देकर जो बड़े बड़े लोग हैं, सेठ साहूकार, पैसे

(श्रीमती सुमित्रा देवी)

वाले, राजा महाराजा, जागीरदार है या बडे बडे नेतागण है जिन्होंने जयपुर के आस पास या अन्य कहीं किसी शहर के आस पास कृषि फार्म्स ले लिये है (शेम, शेम) उनमें बिजली ले जाने के लिये यह प्रावधान रखा है ? इसमें मुझे शक होता है । माननीय वित्त मंत्रीजी से मैं पूछना चाहती हूं कि आप उत्तर देते समय बतावें कि कितने किलोवाट बिजली काश्तकारों को देने का निर्णय किया है ? कितनी किलोवाट बिजली काश्तकारों को अब तक दे पाये हैं और यदि दे पाये हैं तो कितनी जगह ? मुझे शक होता है, शायद ही आप किसी एग्रीकल्चरिस्ट के खेत में बिजली दे पाये हों। क्योंकि भाखरा से जो बिजली झुन्झुनूं जिले के नगरों में दी गई है वही सन् १९६३ में बगड शहर में भी आई है और सदन के माननीय सदस्यों को सुनकर शायद ठेस पहुंचेगी जब मैं बताऊंगी कि वहां बिजली सिर्फ सेठों की बडी बडी हवेलियों को जगमगा रही है । वहां जो खटीक रहते है उनकी बस्ती को बिजली से महरूम रखा है, हरिजन बस्ती को बिजली से महरूम रखा है । इसे देख कर मुझे बडा अफसोस होता है । यह बात हमारे बिजली मंत्रीजी के ध्यान में भी लाई गई थी और उनको कहा था कि यह समाजवादी समाज व्यवस्था के खिलाफ बात है, जो लोग गरीब है और जो उम्मीद लगाये बैठे थे, एक ही शहर में, एक ही नगर में रहते हुए भी उनकी बस्तियों को महरूम रखा जाय और सिर्फ ऐयाशी के लिये उसका उपयोग करें तो लोक कल्याणकारी राज्य के लिये यह शर्म की बात है।

इसके साथ ही साथ डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्र-लाइजेशन के नाम पर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने हिन्दुस्तान में नेतृत्व किया है, उनकी शोहरत फैली है इससे तो मुझे भी बहुत खुशी है लेकिन मैं यहां पर इसको इसलिये मेन्शन कर रही हूं कि एक तरफ जहां हमारी सरकार और हमारे वित्त मंत्रीजी हमसे हमारे पेट पर पट्टी बांधने की अपेक्षा रखते हैं वहां मैं यह बताना चाहती हूं कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन में लाखों ही क्या शायद करोडों रुपयों का गबन पडा है। मैं नजीर के लिये बताना चाहती हूं कि हमारे झुन्झुनूं जिले में एक बुहाना पंचायत समिति है। उस अकेली पंचायत समिति में १ लाख २५ हजार रुपयों का एम्बेजलमेन्ट है। (शेम,शेम) पता नहीं वह फाइल कहां दबी है ? क्यों और किस कारण से दबी है ? क्यों उसकी जांच नहीं होती ? जब वहां के विकास अधिकारी ने इस बात को सरकार के ध्यान में लाने की चेष्टा की तो उसका वहां से ट्रान्सफर कर दिया गया। सिर्फ इसलिये कि वह वहां रहेगा तो प्रोपेगन्डा करेगा । उसको तो दूसरी जगह भेज दिया लेकिन पता नहीं कागज किस जगह पडे हैं ? मैं इतना तो दावे के साथ कह सकती हूं कि न तो उसकी जांच हुई और न जांच होने की कार्यवाही ही शुरू हुई . . .

श्री मानसिंह महार (आमेर) : होगी भी नहीं ।

श्रीमती सुमित्रा देवी : सरकार गरीबों पर इस तरह का टैक्स लगाना चाहती है, जिनकी टैक्स देने की हैसियत नहीं है। सरकार यदि प्रशासनिक खर्चे में कटौती नहीं कर सके तो कम से कम जो गबन और फिजूलखर्ची के मामले हैं उन पर तो ध्यान दे जिससे सरकार को बचत हो सके। वैसे तो एक परिवार के बजट की तरह ही सरकार का बजट होता है । परिवार में शादी-विवाह होते हैं, आकस्मिक खर्चे आते हैं, बीमारी आती है चोरी होती है तो क्या उस समय किसी पर टैक्स लगाया जाता है ? नहीं । बल्कि मितव्ययता के जरिये उसको पूरा किया जाता है। ऐसी

(श्रीमती सुमित्रा देवी)

मितव्ययता के जरिये जिसे साधारण तौर पर कर सके। घर में रहने वाले लोगों की रोटी बंद नहीं की जाती है, कपडों पर कम खर्चा किया जा सकता है, लग्जरीज को कम किया जाता है। बच्चों का दूध बंद नहीं किया जाता वृद्धों की रोटी बन्द नहीं की जाती। इसी तरह सरकार को टैक्स लगाने के बजाय अपने प्रशासन में सुधार करना चाहिये था, प्रशासन के खर्च में कटौती करनी चाहिये थी, लेकिन इसका तो कहीं नाम भी नहीं है। माननीय वित्त मंत्रीजी से मैं नम्र शब्दों में दरख्वास्त करना चाहूंगी कि कम से कम आपको डेढ करोड की प्रशासन में कटौती करनी चाहिये थी फिर २।। लाख के टैक्स लगाते . . .

एक माननीय सदस्य: २।। लाख नहीं, ढाई करोड।

श्रीमती सुमित्रा देवी: ढाई करोड, I am very sorry, ढाई करोड के टैक्स लगाते।

साथ ही साथ बजट में हर पंचायत को वी. एल. डब्ल्यू. देने का प्रावधान है। इससे खर्चा तो काफी बढेगा लेकिन हमारे प्रजातंत्र की बुनियादी नीव है पंचायत वह शायद सुचारु रूप से काम कर सके। मुझे तो इसमें शक है। मैं तो यह भी महसूस करती हूं, हमारे प्रजातंत्र की बुनियादी नींव थी पंचायत उसको लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के बाद नुकसान हुआ है, कमजोर हुई है, क्षीण हुई है इसलिये यदि इसका प्रावधान करने से इसमें सुधार कर सकें तो सच्चे पंचायत राज्य की तरफ अग्रसर होंगे। हां, तो इसके साथ वी. एल. डब्ल्यू. की बात आई है। उससे खर्चा तो काफी बढ जायगा लेकिन एक बात और भी है वह भी कह देना चाहूंगी-डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन के बाद ब्लाक्स में काफी ऑफिसर्स थे। वैसे तो उनकी संख्या अब कम कर दी है और उम्मीद है कि ज्यों ज्यों सरकार धीरे धीरे महसूस करती जायगी त्यों त्यों और भी कमी करेगी। लेकिन मेरी मान्यता है कि ब्लाक एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर, एनिमल हस्बेन्ड्री एक्सटेन्श ऑफिसर और कोऑपरेटिव एक्सटेन्शनन ग्राफिसर है-इन तीनों के अलावा बाकी एक्सटेन्शन ऑफिसर्स की इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिसकी ओर खास तवज्जह देना चाहते हैं वह है एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन और उसके लिये ब्लाक में एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर को रख दीजिये। एनिमल हस्बेन्ड्री एक्सटेन्शन ऑफिसर को रख दीजिये और क्योंकि सहकारिता को जीवन के एक मूल मंत्र की तरह से अपनाना होगा इसलिये कॉपरेटिव एक्सटेन्शन ऑफिसर को भी रख दीजिये। वैसे तो कॉपरेटिव सोसाइटीज जो है उनके भी एक्सटेन्शन की हमारी नीति न होकर उनका जो भी एग्जिस्टिंग, सच्चे रूप से, उसमें सच्चे रूप में सही मायने में काम चलाये जाने की आवश्यकता है उनको रुपये मिलें—ऐसा होना चाहिये।

इसके साथ साथ एक बात और है जिसका बजट से ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि बार बार हर माननीय सदस्य और वित्त मंत्रीजी ने कम से कम १० बार समाजवादी समाज का नाम लिया होगा। वैसे तो उसूलतः हमारी सरकार समाजवादी समाज व्यवस्था के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही है। वह यों है, लोन को लीजिये, तकावी को लीजिये, यह उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो समर्थ हैं, जिनके पास पक्के मकान हैं या जमीन है।

(श्रीमती सुमित्रा देवी)

इसका मतलब यह कि जो लोग अपने पास से एड कर सकते हैं, योग दे सकते हैं आप अपने लोन और तकावियां उन्हीं लोगों को देते हैं । लेकिन जो जरूरतमन्द हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है— नियम के मुताबिक वे न कोई लोन पा सकते हैं और न तकावी पा सकते हैं । इसलिये उसूलतः तो आवश्यकता इस बात की है, यदि हम समाजवादी समाज व्यवस्था की स्थापना करने का नारा लगाते हैं, घोषणा करते हैं तो हमें रूल्स के अन्दर रिलेक्सेशन करना चाहिए, इन रूल्स को बदलना चाहिए जिनके आधार पर, आज जो बडे बडे इन्डस्ट्रीयलिस्ट्स हैं, जिनके पास लगाने के लिये पैसा है, वे सरकार से लाखों रुपया ले लेते हैं, उनको गवर्नमेंन्ट सब्सीडाइज करती है । लेकिन जिस आदमी के पास पैसा नहीं है वह कोई इन्डस्ट्री लगाना चाहता हो तो वह नहीं लगा सकता है । माननीय वित्त मंत्री जी, जो सामर्थ्यवान हैं, जिनके पास पैसा है, आपकी सरकार उन्हीं को पैसा देती है लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, जिन लोगों के पास अपने पैसों का योग देने की सामर्थ्य नहीं है, आपकी सरकार से वे एक पैसा भी प्राप्त नहीं कर सकते । तो मैं आपसे पूछती हूं कि आप बार बार समाजवादी समाज व्यवस्था की स्थापना करने का नारा क्यों लगाते हैं और लोक कल्याणकारी राज्य होने का दावा क्यों करते हैं ? इसलिए मैं बडे नम्र शब्दों के साथ माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि अपने ठंडे दिल, ठंडे दिमाग से विचार करें और जो नये टैक्स इस वर्ष के बजट में लगाये हैं, खासतौर से लैण्ड रेवेन्यू पर अधिभार लगाया है, उसके बारे में पुनः सोचें । किसान की क्षमता नहीं है देने की । आप ७५ एकड के बाद, जो रेट है, उसको बढा दीजिये लेकिन ७५ एकड के नीचे अधिभार मत लगाइये । मैं ७५ एकड की बात कह रही हूं, वह अनइर्रिगेटेड लैण्ड की बात कह रही हूं । इर्रिगेटेड की बात नहीं कह रही, इर्रिगेशन का तो मैंने स्वप्न लिया है । मैं बदकिस्मती से ऐसे इलाके में पैदा हुई हूं जहां इर्रिगेशन के साधन नहीं हैं । मैं किसान की तकलीफ को महसूस करती हूं, क्योंकि मैंने ऐसे ही घर में जन्म लिया है, जो खेती पर निर्भर करता है । मैं खुद खेती करती हूं । जिनके पास ७५ एकड अनइर्रिगेटेड एकड से कम लैण्ड है, उनकी क्षमता लैण्ड रेवेन्यू ही अदा करने की नहीं है । यह आपके सुरक्षा कोष में जो दिया था, वह अपनी हैसियत से बढ कर दिया था । यह भावना की बात थी, कर्त्तव्य की बात थी इसलिये लोगों ने जी खोल कर दिया था । वैसे उनकी क्षमता नहीं है । इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी खास तौर पर इस ओर ध्यान दें । वैसे तो गाय और भैंस पर भी जो सेल्स टैक्स लगाया गया है उसका सीधा भार किसानों पर पडता है, अनाज पर सेल्स टैक्स लगाया गया है, उसका साधारण आदमी के ऊपर भार पडा है । मैं उसूलतः इन करों के खिलाफ हूं । खैर, इन करों का बर्डन तो आदमी वहन कर सकता है और भार वहन कर जायगा लेकिन खास तौर से किसानों की लैंड रेवेन्यू के ऊपर अधिभार लगाया है, इसके लिए माननीय वित्त मंत्री को जरूर निवेदन करूंगी कि इस पर पुनः सोचें । इस बात को इसलिए सोचें क्योंकि यह समाजवादी समाज व्यवस्था के नारे के खिलाफ है । इसलिए इस पर ठंडे दिल से सोचें और इसको वापिस लेने की महरबानी करें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हांडा ।

(श्री हरदत्तसिह और श्री योगेन्द्रनाथ हांडा खड़े हुए)

श्री हरदत्तसिह: मेरा नाम लिया है, आप बिराजें। (विराम) हांडा योगेन्द्रनाथ से मतलब है या हरदत्तसिह से है ?

श्री उपाध्यक्ष: श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रार्यासहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, ८७.६७ करोड़ का एक रेवेन्यू और केपीटल अकाउन्ट्स का तखमीना माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर ने सदन में पेश किया है, जिसमें से ६३.१६ करोड़ रेवेन्यू रिसीट्स में से वसूल किया जायगा, जो कि अपने आंचल के अन्दर २.१० करोड़ का डेफिसिट भी समेटे हुए हैं। इसके अतिरिक्त १५.३६ करोड़ पब्लिक और सेन्ट्रल टैक्स से मीट करने की एक बात उन्होंने रखी है और ४.६६ करोड़ रुपया पब्लिक अकाउन्ट्स से आने वाला है। इसमें ४.०५ करोड़ के टैक्स जोड़ कर एक बैलेन्स शीट, एक तवस्सुम का बजट बड़े गौरव से समाजवादी समाज की दुहाई देते हुए, भारत पर हुए आक्रमण की काली शाया का जिक्र करते हुए फाइनेन्स मिनिस्टर ने सदन में पेश किया। न तो उसमें कोई काली परछाइयां हैं और न उस बजट के अन्दर उस समाजवाद तंत्र की ओर अग्रसर होने का कोई ठोस कदम है। हां, एक बहुत खूबसूरत हिसाब पेश किया गया है, रिजर्व बैंक के जो डेट्स (debts) थे, उनके ३५ करोड़ भारत सरकार के डेट्स से उस भयानक खड्डे को पाट कर और उस खड्डे के अन्दर हमारी सब कुछ आमदनी गिराने की बात फाइनेन्स मिनिस्टर ने इस सदन के अन्दर की है। वैसे तो जिस प्रकार से हमारी इकॉनॉमिक्स चल रही है, कांग्रेस सरकार की इकॉनॉमिक्स चल रही है, उसमें एक आदत सी बन गई है, जिसका कि जिक्र भारत सरकार की ओर से होता है, प्लानिंग कमीशन की ओर से हो चुका है। जब मार्च का महीना होता है तो ट्रेजरी बैंचेज के आगे बिल वसूल करने वाले खड़े हो जाते हैं। हमारी राजस्थान सरकार के पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल के बजट थे इस पंचवर्षीय योजना के। इस पंचवर्षीय योजना में जहां पर पहली साल ३१ करोड का बजट था, दूसरी साल ३४ करोड़ का बजट था, तीसरी साल ३५ करोड़ का बजट था–उनमें पहले आधे साल के अन्दर यूटीलाइजेशन पच्चीस परसेन्ट से कहीं भी अधिक नहीं होता है, बल्कि इस वर्ष तो २५ परसेन्ट से भी कम हुआ है। इस प्रकार सारे बजट लें, सारी पंचवर्षीय योजना को लें तो उसमें जो हमारा २०८ करोड़ का कोर एक्सपेंडीचर है, उसके अन्दर हम पहले तीन वर्षों के अन्दर १०८ करोड़ का एक्सपेंडीचर नहीं करेंगे बल्कि १०४ करोड का, बाकी दो वर्ष के अन्दर एक्सपेंडीचर करेंगे। ये इस तरह बढ़ते हुए कदम सरकार की प्लान्ड इकानामी की तरफ इशारा करते हैं। फाइनेन्स मिनिस्टर की ओर से ऐसी कोई दलील पेश नहीं की गई है जिससे नोन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाई जा सके। केवल इस समय उन्होंने इस बजट में एक कार्य जरूर किया है कि राष्ट्र के लिए उठी हुई भावना, हर एक आदमी का वह मॉरेल, जो कि अपनी पूरी शक्ति से राष्ट्र के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया था, गंगानगर जिला, जिसने पंडित जवाहर लाल, मुरार जी देसाई और इन्द्रा गांधी को तीन दफा तोला और सारे भारतवर्ष में एक रिकार्ड पैदा किया, वह राजस्थान, जिसने अपने जवान देकर भारतवर्ष में एक रेकार्ड पैदा किया और जिसका मस्तिष्क गौरव से ऊंचा हुआ, जहां के बहादुर सिपाही देश के अन्दर लडने गये इस

Page No.96

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सबका जिक्र जरूर गवर्नर महोदय और वित्त मंत्री महोदय ने किया। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि मजदूरों और किसानों ने सबसे आगे बढ कर इस कार्य के अन्दर हिस्सा बंटाया। लेकिन हमारे वित्त मंत्रीजी ने इतना जरूर किया कि उनके कन्धों पर टैक्स का बोझ लाद दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हमारी दूसरी योजना और तीसरी योजना की आदत है, जिसका कि जिक्र इकॉनॉमिक वीकली के अन्दर भी आया है कि जहां हमारा प्लान्ड एक्सपेंडीचर वर्ष दर वर्ष चार करोड बढ़ता है, वहां हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडीचर पांच करोड बढ़ जाता है और केपीटल इन्वेस्टमेंट दो करोड बढ जाता है। चार करोड के मुकाबले में सात करोड की इन्क्रीज होती है, यह वर्ष दर वर्ष होता है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर एक नाजायज बच्चे के रूप में यह शिशु हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर को प्राप्त होता है। मैं अर्ज करूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज अगर सारे टैक्सों का तखमीना लगायें तो वित्त मंत्रीजी उन पुरानी बकाया को चुकती कराने में असमर्थ रहे हैं इसलिये उनको चाहिये था कि वे इस दिशा में कदम उठाते। देश के निर्माण के लिये यह बहुत जरूरी है।

अब अगर टैक्स की बात सोचें तो पहले वर्ष में एक करोड, दूसरे वर्ष में १ करोड ४५ लाख और तीसरे वर्ष में साढ़े चार करोड के घाटे का बजट पेश करते हैं। यह केवल ४।। करोड नहीं रहने वाला है बल्कि इससे भी ज्यादा बढ़ जायेगा और यह पांच करोड या ५।। करोड होगा। पांच वर्षों में आप इसको जोडेंगे तो यह पांच वर्षों में ३२ करोड हो जाएगा और खुदा जानता है, कि यह कहीं ३२ करोड से भी बढ़ कर ३५ करोड न हो जावे। आखिर आप ये टैक्सेज लगाते हैं, यह उन लोगों से वसूल करना है जो जमीन पर खेती करते हैं न कि किसी दूसरे लोगों से। आप सेल्स के द्वारा या लैंड रेवेन्यू के द्वारा इन टैक्सों को वसूल करेंगे। इसमें मैं यह कहूंगा कि आप उनकी रोटी पर टैक्स लगा रहे हैं। जो लोग बाजरे और ज्वार की रोटी खाते हैं उन पर भी आप टैक्स लगा कर रुपया वसूल करेंगे। आप देखेंगे कि जो सेल्स टैक्स आप वसूल करते हैं वह भी गरीब लोगों से वसूल किया जाता है और उसका भार भी गरीबों पर ही पडता है। सेल्स टैक्स का भार भी किसानों पर पडेगा। वे अपने जानवरों को बेचेंगे या खरीदेंगे तो उन पर इसका बहुत भार पडेगा राजस्थान में जानवर ज्यादा है। लेदर इन्डस्ट्रीज के आधार पर भी जब लेदर वगैरह बाहर जावेगा तो टैक्स लगेगा। जब कि यहां राजस्थान में सारे भारतवर्ष से ज्यादा जानवर होते हैं तो भी सरकार लेदर इन्डस्ट्री क्रियेट नहीं कर सकी।

उपाध्यक्ष महोदय, और भी दलीलें हो सकती हैं और दूसरे टैक्स हो सकते हैं या दूसरे जरिये हो सकते हैं जिससे आमदनी बढ़ाई जा सकती है। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने इस संबन्ध में बहुत प्रकाश डाला है, लेकिन मैं आपके सामने दो चीजें पेश करना चाहता हूं। एमर्जेन्सी की हालत में जब देश पर भयंकर आक्रमण हुआ है उस समय हमारे देश में प्राडक्शन बढ़े और मोर्चे पर लडाई के लिये सामान और जवान ये दो चीजें परम आवश्यक हो जाती हैं। इस बजट के नीचे वे भी चिपक रही हैं। अगर आप एग्रीकल्चरल प्राडक्शन–वीट, बारले और राइस के आंकडे

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

देखेंगे—जो एक डायरी इस विभाग की तरफ से जारी की गई है और मेरे पास है वह डायरी और एक दूसरी किताब जो स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से छपी है-अगर आप दोनों में दिये हुए आंकडों का मुकाबला करेंगे तो आपको मालूम होगा, आप देखेंगे कि दोनों के आंकडे आपस में मेल नहीं खाते। आप १९६१ के के आंकडे इसमें से निकालें और देखें तो आपको मालूम होगा कि १९६०-६१ में बाजरे की प्राडयूस एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की डायरी के हिसाब से १४४ पौ० पर एकड है और अगर स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई जो बेसिक किताब है उसमें देखें तो आपको मालूम होगा कि ६०-६१ में बाजरे के आंकडे २२३ पौ० पर एकड है। आप और किसी भी वस्तु को ले लीजिये। वीट को ले लीजिये। स्टेटिस्टिक्स बुक में वीट १९६०-६१ में ७७१ पौ० पर एकड दिखाया गया है तो एग्रीकल्चरल डायरी में ८४४ पौ० पर एकड दिया हुआ है। ये आपके आंकडे हैं जो आपस में टेली नहीं करते और जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि खेतों में और खलियानों में पैदावार बढी है।

मैं यह कहूंगा कि हमारा इरिगेटेड एरिया बढा है। सारे राजस्थान में ५९-६० में १०, १२ लाख से भी ऊपर इरिगेटेड एरिया गया है। अगर आप इस प्रपोर्शन से प्रड्यूस को देखें कि वह कितनी बढी है तो आपको मालूम होगा कि इरिगेशन सालों साल बढता जाता है और उसके मुकाबले में प्राडक्शन सालों साल गिरता जा रहा है।

सन् ५७-५८ में ७,००,१४४ एकड एरिया था और इरिगेशन क्राप ४२७० एकड था। ५८-५९ में ७,००,१४२ था तो इरिगेशन बाई क्रॉप ४,१६६ एकड था। इससे जाहिर होता है कि इरिगेशन से प्रॉडक्शन नहीं बढी है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि जो पैसे इरिगेशन पर खर्च किये जा रहे हैं वे फिजूल जा रहे हैं। होना तो यह चाहिये कि जिस तरह से सिंचाई बढती है उसी तरह से आमदनी भी बढनी चाहिये मगर ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिये इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

इसी प्रकार इन्डस्ट्रियल प्राडक्शन भी डिक्लाइन हो रहा है। नीचे जा रहा है। गंगानगर सुगर प्रॉडक्शन के बारे में कहा गया है कि प्रॉडक्शन बढ गया है। मगर अभी गंगानगर सुगर मिल ने खास खास लोगों को पत्र दिये जिसमें एम. एल. ए. को भी पत्र भेजा है। उसमें बताया गया है कि जहां हम ६०० टन प्रतिदिन क्रशिंग करते थे वहां आज एक हजार टन बढा दिया है लेकिन हमें ६०० टन गन्ना भी गंगानगर में प्राप्त नहीं हो रहा है। यह है राजस्थान सरकार का कदम इस संबन्ध में।

एग्रीकल्चर बढाने के सिलसिले में मैं कहूंगा कि भाखरा क्षेत्र में काफी पैदावार बढाई जा सकती है वहां जमीन बेकार पडी है। स्वयं मंत्री महोदय ने अपने बयान में बताया कि हजारों बीघा जमीन बेकार पडी है। वहां गंगानगर में ३० हजार भूमिहीन लोगों की दरख्वास्तें भूमि प्राप्त करने के लिये आई हुई पडी है, जो लोग धरती चाहते हैं मगर सरकार उनको दे नहीं पा रही है। सरकार उनको कोई मुफ्त में तो धरती देती नहीं है। वहीं बीकानेर रियासत के भयकर कानून भूमि के संबन्ध में लागू हैं और उन्हीं के द्वारा जमीन दी जा रही है। ५०००) या ७००७) रुपये, सन् १९४२ से ४९ तक की प्राइस इन्डेक्स ले लें तो भी उनमें

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

कोई फर्क नहीं आता। आज आप उनको जमीन देते हैं तो उनसे हिसाब भी मांगते हैं। अगर एक साल का भी हिसाब नहीं है तो वह भूमि उसको नहीं मिल सकती और अगर किसान किसी कारण वश १० साल में कोई एक भी किस्त नहीं देता तो उसके लिये आपने यह कानून बना रखा है कि उस जमीन से उसको हटा दिया जाता है और वह जमीन उससे वापिस ले लेते हैं।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी चीफ मिनिस्टर ने इस कानून में कुछ तरमीम की है। उसके जरिये से उन्होंने एक साल की गिरदावरी उनको माफ कर दी है कि अगर एक साल की गिरदावरी नहीं दे सकें तो वह जमीन उनसे नहीं ली जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, ३० हजार एप्लीकेशन्स जमीन को प्राप्त करने के लिये वहां पर आई हुई हैं उनमें से अगर आप दो या तीन हजार लोगों को जमीन एलॉट करेंगे तो भी फिर २७ हजार आदमी तो बगैर भूमि के बेकार ही रह जावेंगे। मैं कहूंगा कि वहां के लोग आज १२-१३ सालों से इस नहर की आशा लगाये हुए वहां पर बैठे हैं कि जब नहर आएगी, हम आबाद हो जावेंगे। मगर जब उनको जमीन नहीं मिलेगी तो वे आबाद क्या बेकार हो जावेंगे। आप राजस्थान केनाल प्राजेक्ट की ओर ध्यान दें। वहां पर लोग २०-२० मील से पानी ला कर पीते थे और पीया है और वहां पर जिनका १०० वर्षों का जमीन का कब्जा है वे इसी आश में बैठे रहे थे कि नहर आने पर हमको जमीन मिलेगी। मैं समझता हूं कि उनको निराश नहीं करना चाहिये। सरकार को उनको जमीन देनी चाहिये। बनारा, भीलावा तहसील नोहर, भादरा आदि स्थानों में जहां पर जिस जमीन को पहले सेटलमेंट डिपार्टमेंट ने रद्दी करके छोड दिया, उसे अब जोड दिया गया है और उस जमीन का सरकार ने ६५ रुपये फी एकड तावान कायम कर दिया है। यह राजस्थान सरकार का नक्शा है विकास का।

अब मैं कुछ बातें आपको पेश करूंगा जिससे आमदनी प्राप्त होगी। आज आप देखते हैं कि मनी-लैन्डर लोग ऊंची दरों का ब्याज लेकर गरीब जनता का खून चूस रहे हैं। आप धौलपुर के प्रधान जगन्नाथजी को देखें, ६० परसेन्ट कंजर उनकी मुट्ठी में हैं और उनको रुपया उधार दिया हुआ है जिसको वे चाहे थाने में बुला कर बन्द करवा देते हैं। उनके यहां २५-३० लोग गिरवी रखे हुए हैं। यही हाल बाली तहसील के गौरिया गांव का है वहां ग्रासियों की बस्ती है। वहां मिश्रु नाम का मनी-लैन्डर है उसके यहां बहुत सी औरतें गिरवी रखी हुई हैं। इस प्रकार यहां कुल १ लाख २० हजार मनी-लैन्डर्स हैं जो जनता का शोषण कर रहे हैं। अगर आप उन पर ज्यादा टैक्स लगावें तो लगा सकते हैं और उससे, आपको मैं यह कहूंगा कि दो करोड से ज्यादा आमदनी हो सकती है। 'Plunder without danger vibhag' अगर इस पर आप लाइसेन्स जारी कर दें, २ परसेन्ट या ४ परसेन्ट भी टैक्स ज्यादा लगा दें तो ठीक होगा।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य समय की सीमा का ध्यान रखें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: केवल दो मिनिट और लूंगा। वूल इन्डस्ट्री एक मुख्य चीज है। न्यूजीलैन्ड के

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

स्पेशलिस्ट के आने के बाद इस बात को साबित कर दिया है कि राजस्थान के अन्दर भारतवर्ष की सबसे अच्छी वूल होती है और इसमें से ६० परसेन्ट वूल टोप वूल बनाई जा सकती है। अगर आप राजस्थान के अन्दर शीप्स देखें तो सारे भारतवर्ष की ४५ परसेन्ट वूल का प्रोडक्शन यहां होता है। १.६७ वूल ईल्ड हिन्दुस्तान का है वहां राजस्थान ४.०० ईल्ड करता है। यदि इस धंधे को सम्हाला जाय, न्यूजीलैंड के एक्सपर्टस् की राय के बाद इसे सम्हाला जाय तो लाखों नहीं करोड़ों रुपयों की आमदनी हमें वूल दे सकती है।

पलाना की खान के बारे में मैं निवेदन करूं, जो दुर्लक्ष्यपूर्ण व्यवहार पलाना की खान के साथ किया गया, कितने आदमियों को बेकार कर के निकाला गया, उनको कम्पेन्सेशन दिया है पर राजस्थान को कितना घाटे में रखा है। यह सब सरकार की लापरवाही से हुआ। साइन्टिफ़िकली, प्रोपरली कोआर्डीनेटेड ड्रिलिंग किये बिना जलहरी में कुआ खोद लेते हैं जिसके नीचे मिट्टी आ जाती है उसके नीचे से टनेल बनाई जाय तो १६५ फीट नीचे डिगिंग करना पड़ेगा। उन्होंने टैक्निकली, बायोलोजी के प्रिन्सिपल के ऊपर प्रोपरली डिगिंग किया, और उन्होंने बताया कि लिग्नाइट का अथाह भण्डार जैसा महाराष्ट्र में पाया गया, आन्ध्र में पाया गया वैसा लिग्नाइट का भण्डार है। जैसा थर्मल स्टेशन नेवेली में है वैसा वहां थर्मल स्टेशन कायम किया जा सकता है। सारे राजस्थान की बिजली एक तरफ, एक तरफ भाखरा नांगल और चम्बल की बिजली दूसरी तरफ उसकी बिजली, ऐसा थर्मल स्टेशन कायम किया जा सकता है। पर पलाना खान के साथ इस तरह का दुर्लक्ष्यपूर्ण व्यवहार किया गया। हनुमानगढ़ की फर्टीलाइजर फैक्टरी जालान साहब को दे दी। अगर राजस्थान सरकार फर्टीलाइजर फैक्टरी को चलाती तो उससे राजस्थान का प्रोडक्शन बढ़ता। जहां ८० लाख एकड़ धरती राजस्थान केनाल से प्रभावित होती है, १० लाख एकड़ धरती भाखरा से और १२ लाख एकड़ से ज्यादा धरती गंग केनाल से प्रभावित हुई है वहां यदि हनुमानगढ़ फर्टीलाइजर फैक्टरी को जोश औ खरोश के साथ राजस्थान सरकार चलाती तो राजस्थान का प्रोडक्शन बढ़ता। पर यह नहीं करके गरीबों की रोटी पर, किसानों पर सरकार टैक्स लगाना चाहती है।

इससे अधिक मैं कुछ न कह कर, एक नंगी तस्वीर वित्त मंत्रीजी ने जो समाजवाद की दोहाई दे कर समाजवाद की पेश की है, उसके बजाय यह तस्वीर मैं पेश करना चाहता हूं।

श्री ब्रजेन्द्रपाल (करौली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट पर दो दिन से वाद-विवाद हो रहा है, उसको सुनने के बाद एक ऐसी भावना समझ में आती है कि जो टैक्सेज इस साल बजट में नये लगाये गये हैं वे अनुचित हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि एक एक्सपेंडिंग इकॉनामी में टैक्सेज लगाने आवश्यक हैं क्योंकि एडीशनल सोर्सेज हम चाहते हैं, अपनी फाइव ईयर प्लान के लिये। उनके लिये एडीशनल टैक्सेज और रिसोर्सेज अत्यावश्यक हैं। पर साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिये। उनमें से मैं संक्षेप में दो

(श्री ब्रजेन्द्रपाल)

कुछ निवेदन कर सकूंगा थोड़े समय में वह निवेदन करने की कोशिश करूंगा।

जब हम नये टैक्सेज लगाते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन का हमको ध्यान रखना चाहिये। जैसे टैक्सेज हमने लगाये लेकिन टैक्सेज जिन पर लगते हैं वे मासेज इस डेमोक्रेटिक सेट-अप में कम से कम यह आशा जरूर करती हैं कि एड्मिनिस्ट्रेशन टैक्स पेअर्स की केपेबिलिटी को ध्यान में रखे, हरैसमेंट नहीं हो, इकॉनामी मेजर्स काम में लाये जायं, और जो कटौती खर्च में कर सकें उनको किया जाय। अगर इन बातों को ध्यान में रख कर टैक्सेज हम लगायें और ये सारी बातें पूरी हो जाती हैं तो टैक्स पेअर्स को टैक्स देने में कोई अड़चन, रुकावट होने की आशा नहीं। पर हम देखते हैं कि जहां तक इकॉनामी का सवाल है और फिजूलखर्ची का सवाल है सब में फिजूलखर्ची देखने में आई है, वही पंचायत समितियों में है। उदाहरण तो ऐसे बहुत हैं पर एक उदाहरण मैं आपके समक्ष, सरकार के सामने रखना चाहूंगा। हर एक पंचायत समिति में इतने एक्स्टेन्शन ऑफिसर्स हैं कि उनके वर्क को अगर कार्डिनेट कर के बी. डी. ओज के हवाले किया जाय तो अच्छा रहेगा और यह टेक्निकल स्टाफ हर पंचायत समिति से हटा कर अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लगाया जाय ताकि वहां से टेक्निकल राय पंचायत समिति को दे सकें। इस तरह हम बहुत से खर्च कम कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे भी बहुत से केसेज हैं, जिनको आज तक भी कोई पी. डी. आर. की कार्यवाही नहीं हुई और न आशा ही है। ऐसे भी सरपंच हैं जो दस, दस हजार रुपया ले कर बैठे हैं पर उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

इसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत फिजूल खर्ची और इनएफिशियेन्सी नजर आती है। ऐसे बहुत से पुलिस स्टेशन्स हैं जिनकी आम तौर पर चर्चा है कि उनकी इन्कम ५० थाउजेंड सालाना है। अगर हम एफिशियेन्सी लायें और इस करप्शन के मामले में ध्यान दें तो जनता के भाव सरकार के प्रति अच्छे हो सकते हैं। इन बातों की कमी नहीं हो तो ऊपर से यह टैक्सेज का बोझा होने से अशान्ति होने का अन्देशा है।

इसी तरह से मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के बारे में अर्ज करना चाहूंगा। आज दो साल से हम चाहते हैं कि हम इकॉनामी को बढ़ायें, पैदावार बढ़ायें पर अफसोस के साथ अर्ज करना पड़ता है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट की इनएफिशियेन्सी इन दो वर्षों में बहुत अधिक रही है।

खास तौर पर मैं मेरे सब-डिविजन की कुछ बातें अर्ज करना चाहूंगा। जितने भी नये और पुराने बंध हैं उनकी सब नहरें टूटी हुई हैं। मुख्य जो बांध है, 'कालीसिल बंध' वह एक मेजर प्राजेक्ट है, उसकी जो केनाल है वह डिफेक्टिव है और कई वर्ष से उसका पानी बेकार जा रहा है लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेन्ट ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसी तरह 'नमदार केनाल' है वह भी टूटी हुई है, उसका पानी बेकार जा रहा है और किसान उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार रूपपुरा की जो लाइन है वह भी टूटी हुई है। इरीगेशन डिपार्टमेन्ट का इस ओर ध्यान दिलाया गया लेकिन इस प्रकार के अहम मामलों की सुनाई तो दूर, मंत्री महोदय ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया।

(श्री ब्रजेन्द्रपाल)

इसी तरह एक बहुत ही अहम बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा और वह यह है कि राजस्थान सरकार ने एक कालेज ऑफ नर्सिंग खोलने का विचार किया है और इसका इनोगरेशन सी. सी. एम. अमेरिका से हुआ है टैक्निकल कोलोबोरेशन के अन्तर्गत। इस सी. सी. एम. ने अपने चार एक्स्पर्ट्स राजस्थान में भेजे और करीब साल भर से उन पर चार हजार रुपया महीना खर्च कर रहे हैं लेकिन अब तक राजस्थान सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है जब कि सरकार इस कालेज के लिये एक लाख से अधिक खर्चा भी कर चुकी है लेकिन समझ में नहीं आता है कि डाइरेक्टर साहब नहीं चाहते या पता नहीं क्या कारण है, क्या गड़बड़ी चल रही है कि आज तक ४ एक्स्पर्ट्स जयपुर में ठहरे हुए हैं, खर्चा कर रहे हैं लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है।

इसी प्रकार फारेस्ट के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सेंक्चुअरी सरकार ने बनायी है, जयसमंद सेंक्चुअरी पर जो खर्चा हो रहा है वह बेकार हो रहा है। खास तौर पर जयसमन्द में तो एक भी जानवर नहीं है इस पर ४० हजार लगाये हैं जब कि कोई जानवर भी नहीं है।

नये टैक्सेज के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो नये टैक्स लगाये गये हैं खाद्यान्न पर और लैंड रेवेन्यू पर जो सेस लगा है उनके बारे में वित्त मंत्रीजी से नम्र निवेदन करूंगा कि वे इनको विथड्रा कर लें। उनकी पूर्ति के लिए ऐसे साधन जुटा सकते हैं, उसमें एक यह भी है कि इन्डस्ट्रियल सेस लगाने का सरकार विचार कर सकती है। क्योंकि बहुत सी इन्डस्ट्रीज के लिए सरकार ने कन्सेशन्स दिये हैं तो हम उन पर टैक्स लगा कर इनकम करें तो कोई इन्जस्टिस नहीं होगी।

इसी प्रकार स्टोन क्वेरीज से जो पत्थर निकलता है उस पर फर्स्ट पोइन्ट पर सेल्स टैक्स लिया जाता है। अगर यह लास्ट पोइन्ट पर लिया जाय तो सेल्स टैक्स की आमदनी दुगुनी से अधिक हो सकती है।

इसी प्रकार सोशियल वेलफेयर में से १ करोड़ रुपया बचा सकते हैं। इस मद में खास कर कम्युनिटी डवलपमेन्ट और सोशल वेलफेयर में अक्सर फिजूलखर्ची देखने में आती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर इस ओर ध्यान दिया गया तो अवश्य कुछ घाटे की पूर्ति हो सकती है। इसलिये जो एडीशनल टैक्स वित्त मंत्री महोदय ने लगाये हैं वे उनको विथड्रा करें।

अनेक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल सारस्वत।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अर्थ मंत्रीजी द्वारा जो बजट सदन में ६३-६४ का पेश होकर जो पर विचार रक्खा गया है वीं पर दो दिनों से विचार हो रहा है। जो बजट ई ढंग से बनाया है कि आज तक किसी प्रान्त में और कहीं भी नहीं आयो। मैं समझा के अर्थ मंत्री महोदय ई बजट पर कदे भी विचारपूर्ण ढंग से सोच्यो नहीं। अगर वां सोच-विचार कर आं ढंग को बजट राखता दो दिन से जकी बजट की बहस चल रही है वीं की नौबत नहीं आती।

Page No.102

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

अब सूं पहले भारत का काफी लम्बा चौड़ा बजट देसाईजी, म्हारा अर्थ मंत्रीजी पेश करयो। वीं में जका जका टैक्सां अर्थ मंत्रीजी घटे राख्या वीं पर पूर्णतया सोच-विचार कर बा बातों राख दी गई ही और मारो पड़ौसी प्रान्त पंजाब जब आपको बजट विचारार्थ असेम्बली में राखणोहार हो और जब मुरारजी भाई द्वारा सेन्टर रो बजट पेश हुयो तो वींके साथ ही पंजाब सरकार बिना टैक्सां का बजट राख्यो। क्यों, वीं ने पतो हो रेवेन्यू में बचत की योजना मुरारजी भाई राख दी है वींनें देखता हुआ यो मद्दो राख नीं सका। पर म्हारा अर्थ मंत्री महोदय सूं बहुत पहले भारत सरकार का बजट आ चुका। फेर भी वीं यो बजट रखता विवेकसूं काम नहीं लेवता। ई ढंगो-बेढंगो बजट जीं को छोटो मिनखां पर यानी गरीब तबका पर असर होगा वो बजट ही सदन में वे लाया, विसू प्रत्येक मिनखा का दिमाग पर और मानस पर ई ढंग को असर पड़ रह्यो है कि जगह जगह सूं लोगों की विचारधारा जको व्यक्त हो रही है वे अत्यन्त दुख पूर्ण है, वां लोगां ने या बात कहन रो मौका मिल रह्यो है कि बजट बिलकुल गरीबां ने दुख देगा, मैं समझूं कि अर्थ मंत्री या दिनां में बजट राखण पहले जयपुर की सीमा सूं बाहर नहीं गया होगा और देहातों सू वां को सम्पर्क नहीं होगा वां एक दौरो गांवों को लगावे, दो दो दिन की छुट्टियां में, मां तो गांवां में हालियां की छुट्टी मनाय आया हैं, वे भी देहात में जावता तो ई की जरूरत नहीं पड़ती, व्ह टैक्सां ने वापिस ले लेता। कहावत है पंचां को हुकम सरमाथा, पै नालो तो वठे ही पड़सी। या बातचीत जकी है बिल्कुल देहात में आवे है। अब मैं बजट में के के कमियां है वो रखणो चावूं।

बजट में चार करोड़ रुपया रा टैक्स लगाया है। अर्थ मंत्री जो कमी बतायी उण हिसाब सूं चार करोड़ रुपया री कमी है आपांरा इण ६३-६४ रा बजट में। अगर इण कमी ने मिटावणरो ख्याल होतो अर्थ मंत्री ने, तो वे आपणा राजकाज पर थोड़ो सो ध्यान देता। आज जका लोगां री खून पसीना री कमाई सूं जो लोग आपणो निर्वाह कर रह्या है वां किसान और मजदूरां से या साधारण लोगों सूं टैक्स लेवण री नौबत ही नहीं आवती। जिस्या टैक्स रखीया गया है राजस्व कर ओ सीधो किसाना पर पड़े है। मुरारजी भाई कम्पलसरी सेविंग रे नाम पर पहला ५० प्रतिशत बढा दियो है उण उपरान्त आप भी और बढावो और सेल्स टैक्स री दर बढा रह्या हो, या बिल्कुल भी वाजिब बात नहीं है।

दूसरी बातचीत जका टैक्स आप लगा रह्या हो उसरो असर गाव री जनता पर पड़े है। अच्छी सरकार रो, जो भी देश में आयी है, परम कर्तव्य रह्यो है कि वे जनता रे रोटी, कपड़ो, शिक्षा पानी सब कुछ रो प्रबन्ध करें। म्हारा अर्थ मंत्री ने आज जनता री रोटी पर एक परसेन्ट, दो परसेन्ट और तीन परसेन्ट टैक्स लगावा में कोई हिचक नहीं आयी।

इणरे अलावा बिजली पर भी टैक्स लगायो। राजस्थान में, उपाध्यक्ष महोदय, पानी सैंकड़ों फीट नीचे है, दानी-मानी लोग कुआ पर पम्प लगा रक्खया है वे पम्प बिजली सूं चाले है वा कुआ पर जो खर्चा आवे है बिजली रो हजार-हजार रुपया महीना रो

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

खर्च आवें है उणा पर भी टैक्स लगाया है । इण वास्ते म्हे अर्थ मन्त्री महोदय सूं एक डेपुटेशन में मिल्या और कह्यो के जो दानी-मानी लोग जनता रे सुविधा रे वास्ते बिजली रा कुआ चलाया आप उणां पर तो टैक्स मत लो । तो उणारो कहणो है कि जो दानी-मानी लोग हजार रुपया बिजली रा भर सके है वे म्हानें पचास रुपया टैक्स रा देता नहीं हिचकिचावेला । ई बात पर म्हा लोग वापिस आ गया ।

अर्थ मंत्री जी सूं म्हारो निवेदन है कि आप राजस्थान में जो बेढब खर्चा बढा राख्यो है वीं खर्चा नें जनता बरदाश्त नी कर सके । आप इण तरह सूं टैक्स लगाता रहया तो जनता भले ही थोडा दिनां रे वास्ते आप लोगां री धांधली नें बरदाश्त कर ले, लेकिन आ मनमानी जनता ज्यादा बरदाश्त करबा वाली नहीं है । आपरो हाउस में बहुमत है । अनुशासन रे नाम पर कोई भी सदस्य जो जनता सूं चुन्योडा है ए सब टैक्स बरदाश्त नहीं कर सकेला । हां में हां मिलाबा वाला भी बरदाश्त नहीं कर सकेला । एक बार आपरी हां में हां जरूर मिला देवेला, पर म्हं चेतावनी देणो चाहूं कि जो भी सदस्य आप आप री कॉन्स्टी-ट्यूएन्सी में जावेला वो वानें महंगो पडेला । अर्थ मंत्री जी तो जयपुर में बैठा रेवेला, पर जो सदस्य आप आप रा गांवां में जावेला और एजीटेशन रो नेतृत्व संभाले ला जद वें मुख्य मंत्री जी सूं और होम मिनिस्टर साहब सूं बात करेला और वारन्ट इश्यू करावेला । आ आप पक्को समझ लो कि आप जो नासमझी रो बजट पेश कर्‌यो हो इण सूं जनता आन्दोलन करेला वो आपका रोक्या सूं भी रुकबा वाला नहीं । आपरी पार्टी रा सदस्य भी इण में शामिल होवेला । आपनें रात्रि रा १२ बजिया तक समझाता रह्‌या फेर भी आपरे समझ में इणा री बात बैठी नहीं । म्हं फेर आपनें कह रह्‌यो हूं कि आप विवेक सूं काम नहीं कर रह्‌या हो, आप आ मत सोच जो के म्हारी कुरसी कोई छुडाय नहीं सके है । जनता में वा ताकत है जो बडा बडा बादशाहां नें गद्दी सूं उतार नीचा दिया, बडी बडी बादशाहत और टोपियां जनता रा एजीटेशन सूं बदल गई ।

ई वास्ते म्हे अर्थ मंत्री जी सूं विनयपूर्वक बात कहूं कि आपरी अवस्था अब साठ वरस री हो गई; साठ वरस रे बाद आदमी में बिचारवा री कमी आ जावे, तो इण हालत में वे आपरां मित्रा सूं, खास सलाहकारां सूं सम्मति लेवे और अपना मुद्दा पर फेर विचार करे कि किण ढंग रो वे बजट राख्यो है । जिको कोलाहल मच रहयो है । काश्तकारां पर और दूसरा लोगां पर जिण प्रकार रा टैक्स आप लगा रहया हो वे आपनें वापिस लेणा चावे । आप आ मत सोचो के म्हे तो शहरी क्षेत्र सूं चुनाव जीत कर आयो हूं । आपनें, हो सके आयन्दा चुनाव में देहात रो टिकट मिल जावे तो वठे न नेहरू जी री चाले ला और न थारी कांग्रेस पार्टी री । पिछली बार भी आपनें हारनो पड्‌यो, आपनें कोई भी किसान वोट नहीं देवण वाला है । इण वास्ते जिण प्रकार री चार करोड रुपया री आमदनी रा टैक्स लगाबा री बात राखी है वा वापिस लेनी चाहीजे । आप इण तरह सूं जो चार करोड री आमदनी करणो चावो हो वो होवेगी नहीं ।

शासन सुधार रा काम और जनता री भलाई रो काम आप लोगां सूं बैठेला नहीं ।

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

पहली आप १ करोड रुपया रो टैक्स लगायो और अब चार करोड रुपया, भगवान करे आयन्दा आपने मोको नहीं मिले ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : तो फेर वे कठे बैठेला । .

श्री मोहनलाल सारस्वत : अब टैम नहीं कि राजस्थान री सारी बातां बता सकूं । आयन्दा अगर मोको मिल्यो तो आप १६ करोड सूं कम घाटा रो बजट नहीं राखोला । औसतन चौबीस गुना बढतो जावे है । पहले एक करोड और बाद में चार करोड रो घाटा रो बजट राख्यो, इणी ढंग सूं चौगुना बढावा देता रहयां तो आगे वालो बजट १६ करोड रुपया रो घाटा वाला बजट होवेला । इण वास्ते इस्या आदमिया पर पहले सूं ही प्रतिबन्ध लगा दियो जावे ताकि भविष्य में वे नी आ सके और नी इण प्रकार रो बजट ही म्हा लोगा रे सामने आवे । ज्यारो राजस्थान रे भविष्य री कोई चिन्ता नहीं वा लोग इण तरह रो बजट रखे; इण प्रकार का टैक्स बढावे आ कोई उचित बात नहीं ।

अब मैं असली पोइन्ट पर आऊं हूं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : तो अभी तक आप नकली पोइन्ट पर कह रहे थे क्या ?

श्री मोहन लाल सारस्वत : व्यासजी, थोडा आप विराजो ।

श्री चन्दनमल वैद : (उप मंत्री वित्त) : Time is up we should adjourn.

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हुआ, कल ११ बजे तक के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बज कर १ मिनट पर बृहस्पतिवार दिनांक १४ मार्च, १९६३ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई) ।

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, दिनांक ६ मार्च, १९६३)

पशुओं की नस्ल सुधारने पर खर्चा

राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा मैसर्स भारत प्रेस, अलवर से रोडवेज के टिकटों की छपाई ।

प्रेस कर्मचारी यूनियन बीकानेर–डाइरेक्टर का मुआयना

रेगिस्तानी लोगों को फूड एडल्टरेशन एक्ट के अन्तर्गत लाइसेन्स

मिल्क स्कीम के अन्तर्गत अधिकारी

निवाई–डांगथल वाया वनस्थली मार्ग पर मोटर परमिट

नगरपालिका भादरा को सहायता की धनराशि

जिला भरतपुर की अदालतों में सवर्णों तथा हरिजनों के संघर्ष के फौजदारी केसेज

बीकानेर, जोधपुर तथा शेखावाटी जिलों में सिंचाई-प्रणाली

मावली तहसील में चम्बल की बिजली

आहू नदी की सहायक छोटी नदी पर पुल—झालावाड़

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत नगरपालिकाओं का पंचायतों में परिवर्तन

मोकलसर पावर हाउस द्वारा बिजली

सब-जेल-निम्बाहेड़ा

राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा व्हाइट पेपर के लिफाफों की खरीद

पंचायत समिति, सांचोर में पतरों का अलाटमेंट

जालोर में टिड्डियों से फसल को नुकसान

चित्तौड़गढ़-उदयपुर वाया मंगलवाड़ रूट का नेशनेलाईजेशन

टेप मेजरिंग की खरीद

देवगढ़ डिस्पेंसरी में फर्नीचर की कमी

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—नीम-का-थाना

(दिनांक ६ मार्च, १९६३ का स्थगित प्रश्न)

विद्युत कनेक्शन्स सम्बन्धी विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

२. सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री भवानी शंकर नन्दवाना, उप मंत्री, ने पंचायत एवं विकास विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखीं :—

(१) अधिसूचना संख्या एफ. २४ । पी. एस. । रूल्स (५) ४० । ६२।२०।२२ दिनांक २२ नवम्बर, १९६२, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सर्विस (रिवाइज्ड पे स्केल्स) रूल्स, १९६२ [Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishad Service (Revised Pay Scales) Rules, 1962] प्रकाशित किये गये हैं।

संक्षिप्त-विवरण

(२) अधिसूचना संख्या एफ. ४। एल. जे. । २ (२५) ६२।२७६३४ दिनांक २१ दिसम्बर, १९६२, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (एपाइन्टमेन्ट आफ कौन्सल्स) रूल्स, १९६२ [Rajasthan Panchayat and Nyaya Panchayat (Appointment of Counsels) Rules, 1962] प्रकाशित किये गये हैं।

३. अध्यक्ष द्वारा सूचना

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि प्रजा समाजवादी दल के नेता श्री मुरलीधर व्यास एवं समाजवादी दल के नेता श्री रामकिशन ने यह सूचित किया है कि राजस्थान विधान सभा में समाजवादी तथा प्रजा समाजवादी विधायक दलों का विलय हो जाने के फलस्वरूप समाजवादी संयुक्त दल का गठन हुआ है।

इस नये दल का नाम "समाजवादी संयुक्त दल" है और इसके नेता श्री मुरलीधर व्यास हैं।

४. आयव्ययक, १९६३-६४

प्रथम अवस्था—सामान्य वाद-विवाद

आय-व्ययक, १९६३-६४ पर सामान्य वाद-विवाद आज भी जारी रहा जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री मानसिंह महार
(२) श्री रामानन्द अग्रवाल
(३) श्री तेजा राम गहलोत
(४) श्री रामकिशन
(५) श्री गोकुल प्रसाद शर्मा
(६) श्रीमती सुमित्रा देवी
(७) श्री योगेन्द्र नाथ हांडा
(८) महाराजकुमार श्री ब्रजेन्द्रपाल

श्री मोहनलाल सारस्वत बोल रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५ बजे गुरुवार, दिनांक १४ मार्च, १९६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

गुरुवार, दिनांक १४ मार्च, १९६३
की कार्य सूची

आय-व्ययक, १९६३-६४ सम्बन्धी अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६८ का उत्तर देखिये)

राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा बकरा, बकरी, भैंस और ऊंट की नस्ल सुधार हेतु सालवार खर्चे का विवरण :—

बकरा, बकरी:—

१६५८-५६	..	..	२१ जमनापारी	२००० रु०
१६५६-६०	..	..	१०१ जमनापारी	१०००० रु०
१६६०-६१	..	..	१७ जमनापारी	२००० रु०
१६६१-६२	..	..	१६ जमनापारी	२००० रु०
१६६२-६३	..	..	१६ जमनापारी	१५०० रु०

भैंस :—

१६५७-५८	..	..	२२ भैंसें	१०५०० रु०
१६५८-५६	..	..	४४ भैंसें	२२००० रु०
१६५६-६०	..	..	८८ भैंसें	१४३०० रु०
१६६०-६१		..	४३ भैंसें	२१४०० रु०
१६६१-६२	..	..	४२ भैंसें	२१००० रु०

ऊंट :—

१६५६-६०	..	..	११०३२५ रु०
१६६०-६१	..	..	१०६५० रु०
१६६१-६२	..	..	४७६२५ रु०

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ का उत्तर देखिये)

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत सन् १९५९ में नगरपालिकाओं से पंचायतों में परिवर्तित नगरपालिकाओं की सूची ।

	नाम	सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
१.	विजयनगर	५,८०२
२	नरायना	५,५१७
३.	लालसोट	५,७३९
४.	बसवा	४,०६५
५.	बैराठ	५,२१८
६.	शाहपुरा	६,०७१
७.	मनोहरपुरा	६,५४६
८.	दांता	५,३४८
९.	लोसल	६,७३६
१०.	बिसाऊ	७,८०२
११.	टोडारायसिंह	७,१९९
१२.	कुम्भेर	५,३८८
१३.	भुसावर	६,३४४
१४.	नगर	४,२०९
१५.	हिन्दूमलकोट	१,६२४
१६.	गलियाकोट	३,३६७
१७.	बैगू	५,४२८
१८.	भवानीमन्डी	५,२२९
१९.	पिडावा	५,४२२
२०.	तिजारा	५,२९६

सन् १९५९ से १९६२ तक पंचायतों से नगरपालिकाओं में परिवर्तित की गई पचायतों की सूची ।

नाम				सन १९६१ की जनगणना के आधार पर
१. बिसाऊ	..	..	..	९,०२१
२. टोडारायसिंह	..	..	..	९,००८
३. पीपाड	..	..	..	१२,५५७
४. सादडी	..	..	..	१२,५९५
५. भवानीमन्डी	..	..	..	७,२४७

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३२७ का उत्तर देखिये)

सन् १९६१-६२ के लिए ग्रामंत्रित टेन्डर नोटिस के ग्राइटम नं० २१४, २१५ एवं २१६ पर ग्रंकित टेप मेंजरिंग मैसर्स कृष्णा कार्मशियल एजेन्सी, ग्रजमेर से खरीदी गई थी ग्रौर इनका व्यौरा निम्नलिखित है :—

Item No.	Tape Measuring Mastermaps	Quantity	Amount
214	Masterpiece Metallic tape 5/8" width of 100 ft. as per sample @ 296.39 nP. per doz. graduated on the back side in centimeters.	4 Doz.	1185.56 nP.
215	-do- 50 ft. as per sample @ 185.91 nP. per doz.	6 Doz.	1115.46 nP.
216	-do- 25 ft. as per sample @116.21 nP. per doz.	6 Doz.	697.26 nP
214	-do- 100 ft. as per sample @ 296.39 nP. per doz. (P. O. No. 6545-51 dt. 23-3-62 Govt. sanction No. F. 2 (47) HD/61, dt. 23-3-62)	35 Doz.	10373.65 nP.
	TOTAL:	51 Doz.	13371.93 nP.

Item No. 214 Tape Measuring Chesterman metallic Triple, or Indian 5/6" width of 100 ft.

S. No.	T. No. 2	Rate per Unit per Doz. 3
I	34 No sample	Rs. 257.00 nP. N. S. Inclusive S. T.
II	48C. No sample	Rs. 257.00 nP. N. S. only metres 30 metre
III	27	Rs. 268.48 nP. Freeman Sample also for 215 to 219.
IV	49 No sample	Rs. 276.00 nP. N. S. Landmaster Brand Certificate by the Alipur Test.
V	95	Rs. 279.00 nP. Masterman's 25 ft. sample same for items 214 to 216.

1	2	3
VI	91 approved	Rs. 296.39 nP. Master metallic measuring. Sample same for 214 to 219.
VII	29 No sample	Rs. 297.00 nP. Measuring Brand Indian make N. S.
VIII	110 No sample	Rs. 298.00 nP. Landmaster N. S.
IX	48 No sample	Rs. 299.00 nP. Single part, N. S.
X	107	Rs. 303.94 nP.
XI	40 No sample	Rs. 304.75 nP. Freeman N. S.
XII	20	Rs. 305.00 nP. Freeman Brand as per sample of 25 ft. only to show quality. Sample same for items 214 to 219.
XIII	48B. No sample	Rs. 311.00 nP. Double 1008/30 Me t N. S.
XIV	17(2)	Rs. 320.50 nP. Measures King.
XV	17(1)	Rs. 324.00 nP. Metric Inches graduals (not legible) sample same for Item No. 214 to 216.

Item No. 215—Tape measuring Chesterman metallic Triple or Indian width of 50 ft.

S. No. 1	T. No. 2	Rate per Doz. Unit 3
I	34 No sample	Rs. 161.00 nP. N. S. inclusive Sales Tax. Before original Tender. Difference in ration in words Rs. One Hundred Sixty only.
II	48C. No sample	Rs. 161.00 nP. N. S. Meters only.
III	27	Rs. 166.48 nP. Sample I. 214 Freeman.
IV.	95	Rs. 175.00 nP. Masterman Metallic Measuring Tape. Refer sample I. 214.

1	2		3
V	49	No sample	Rs. 180.00 nP. N. S. Landmaster Brand Certified by Alipur Test.
VI	91	approved	Rs. 185.91 nP. Masterman Metallic measuring. Tape Refer Sample I. 214.
VIIA	29	No sample	Rs. 189/- Measure King Brand Indian make N.S.
VIIB	110	No sample	Rs. 189.00 nP. N.S. Land Master.
VIIIA	20		Rs. 191.00 nP. Freeman Brand of 25 ft. long to show quality. Refer sample I.214.
VIIIB	48A	No sample	Rs. 191.00 nP. N.S.
IX	40	No sample	Rs. 192.00 nP. N.S.
X	107	No sample	Rs. 193.50 nP. N.S. (Refer S.I. 214)
XI	48B	No sample	Rs. 203.00 nP. N.S. Double 50/15 N.
XII	17(2)		Rs. 213.00 nP. Measure King (Refer sample Item No. 214)
XIII	17(1)		Rs. 216.00 nP. Record (Refer sample Item No. 214)
XIV	23		Rs. 224.00 nP. inclusive Sale Tax. Refer sample I. 214.
XV	1(2)	No sample	Rs. 340.00 nP. Indian N.S.

Item No. 216 Tape Measuring Chesterman Metallic Triple Or Indian 578" width.

S. No. 1	T. No. 2		Rate per Doz. Unit. 3
I	34	No sample	Rs. 95.00 nP. N.S. Inclusive S. Tax.
II	48C.	No sample	Rs. 96.00 nP. N.S. Meters only.
III	27		Rs. 107.72 nP. Freeman. Refer S.I. 214.
IV	49	No sample	Rs. 110.00 nP. N.S. Landmark Brand. Certified by Alipur Test.

परिशिष्ट

1	2	3
V	95	Rs. 115.00 nP. Masterman 25 ft. Refer sample Item No. 214.
VI	110 No sample	Rs. 116.00 nP. Landmaster. XX
VII	91 Approved	Rs. 116.21 nP. Masterman metallic measuring Tape. Sample Item 214.
VIII	29 No sample	Rs. 117.00 nP. measuring Brand Indian make.
IXA	20	Rs. 119.00 nP. Refer sample Item 214.
IXB	48A No sample	Rs. 119.00 nP.
X	40 No sample	Rs. 119.75 nP.
XI	107 No sample	Rs. 130.75 nP. (Refer sample Item 214).
XII	48B No sample	Rs. 126.00 nP. Double Feet 10/72M.
XIII	17(2)	Rs. 129.75 nP. measuring | Refer sample
XIV	17(1)	Rs. 132.00 nP. Record. | Item 214.
XV	23	Rs. 184.00 nP. Inclusive Sales Tax. Refer sample Item 214.

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक १३ मार्च, १९६३)

स्कम्भ १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
२१८०	१३	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
२१८३	स्कम्भ	१२८३	२१८३
,,	शीर्षक	तारांकित	तारांकित
२१८५	शीर्ष	--	(श्री कुमारानन्द)
२१९२	१९	श्री श्रवणलाल (अनुपस्थित)	श्री श्रवणलाल (अनुपस्थित)
२१९५	१७	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
२२००	१८	श्री गिरघारी	श्री गिरधारी
२२०३	१६	एग्रीमेन्ट	एग्रीमेन्ट
२२०७	४	सामगी	सामग्री
२२०८	१९	कानट्रेक्ट	कॉन्ट्रेक्ट
२२०९	शीर्ष	--	(श्रीमती कमला बेनीवाल)
२२१०	अन्तिम से २ व ३	मंत्री (श्री मथुरादास माथुर)	गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर)
२२१६	१	गाये	गये
२२२३	अन्तिम से ४	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह्
२२३१	शीर्षक	संयुक्त समाजवादी- १३ मार्च १९६३-विधायक दल का गठन	तारांकित प्रश्नोत्तर-१३ मार्च १९६३-संयुक्त समाजवादी
२२३२	१८	माथूर	माथुर
२२५२	अन्तिम से २	(उप-मंत्री)	(उप-मंत्री, विद्युत्)
२२५५	३	हं	हूं
२२७१	शीर्ष	अगरवाल	अग्रवाल
,,	२४	कियेट	क्रियेट
२२७५	१७	है	हैं
२२७८	अन्तिम पंक्ति	ह–	है–
२२७९	३	रिसोर्सज	रिसोर्सेज
,,	१५	ह	है
२२८१	अन्तिम पंक्ति	ो	जो
२२८४	१९	मंजर	मंजूर
,,	२१	कहुंगा	कहूंगा
२२८८	१२	बनाय	बनाये
२२८९	१	मालुम	मालूम
२२९१	४	Dont	Don't
२२९५	अन्तिम से २	एस्टीमटेड	एस्टीमेटेड
२२९६	२०	एकजम्प्ट	एग्जम्प्ट
२२९७	शीर्ष	श्रीरामानद	श्री रामानन्द
२३१६	अन्तिम से २	टक्सों	टैक्सों

१	२	३	४
२३३५	१०	श्री गकुल प्रसाद शर्मा	श्री गोकुल प्रसाद शर्मा
२३४६	२२	श्री माणकचन्द सुरणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
"	२५	श्री गोकुल ासाद शर्मा	श्री गोकुल प्रसाद शर्मा
२३४७	५	Order Please, Order!	Order Please ! Order !!
"	२५	बैद	वैद
२३४८	१	OrderPlease, Order	Order Please ! Order !!
"	७	श्री भैरोंसह	श्री भैरोंसिह
"	२०	जिनक	जिनके
२३५२	९	श्रीमती सुमित्रा देवी	श्रीमती सुमित्रा
२३५३ से २३६१ तक	शीर्ष	" "	"
२३५५	१२	ज न	जिन
२३५८	२४	श्रीमती सुमित्रा देवी	श्रीमती सुमित्रा
२३५९	१७	" "	" "
२३६१	२३	ढेने	देने
२३७५	५	इनोगरेशन	इनआॅग्युरेशन
२३८२	७	up we	up, we
२३८३	३ (बांई ओर)	—	तारांकित प्रश्नों के शीर्षक —२१७९ —२१७९
"	१९ (दांई ओर)	गये पत्र	गये पत्र—२२३२
"			
२३८५	९ (बांई ओर)	द्वारा सूचना	द्वारा सूचना —२२३१
२३८६	प्रथम (दांई ओर)	१९६३-६४	१९६३-६४—२२३३